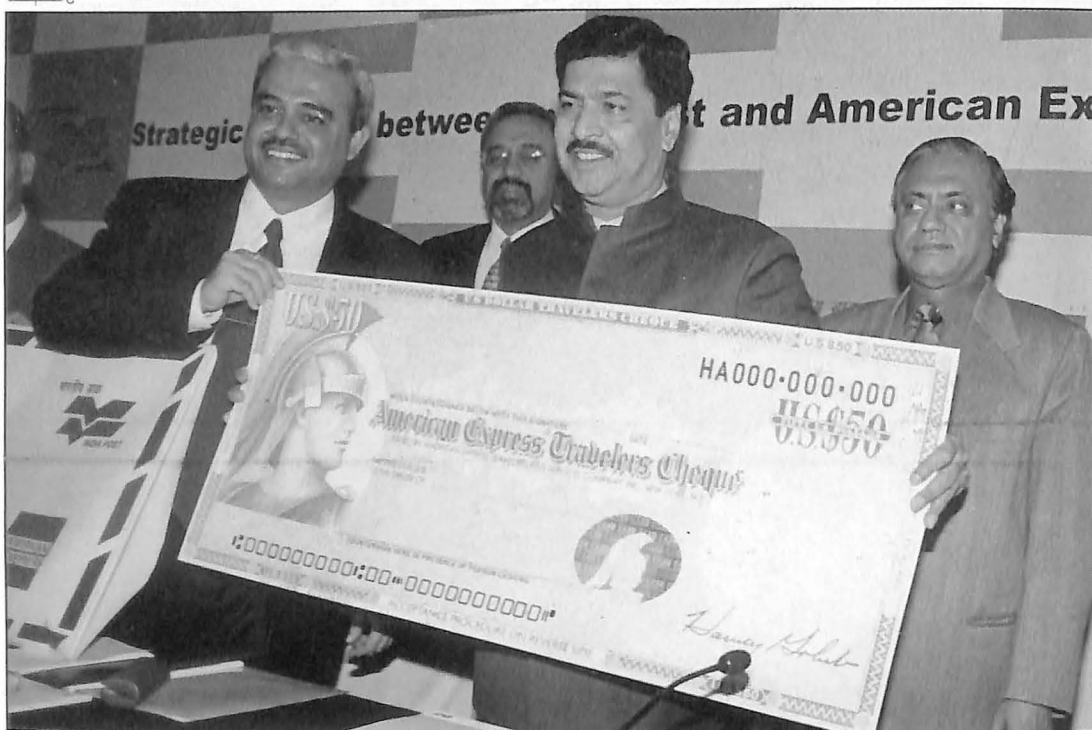




दिल्ली में 25 जनवरी, 2002 को भारतीय डाक और अमेरिकन एक्सप्रेस के बीच नीतिगत गठबंधन के समारोह के अवसर पर श्री प्रमोद महाजन, माननीय संसदीय कार्य और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

Shri Pramod Mahajan, Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs and Communications & Information Technology at the function of Strategic alliance between India post and American Express at Delhi on 25th January 2002.



श्री एस.सी. दत्ता, सचिव, डाक एवं अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड।

Shri S.C. Dutta, Secretary, Posts and Chairman, Postal Services Board.



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2001-2002

भारतीय डाक विभाग
(संचार और सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

भारत

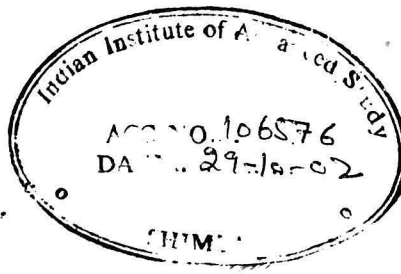
DEPARTMENT OF POSTS
(MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY)
INDIA

विषय सूची

भाग I

वार्षिक रिपोर्ट (2000-2001)

	पृष्ठ सं.
तालिका सूची	iv
लक्ष्य एवं उद्देश्य	1
अध्याय 1 पुनरीक्षा	3
अध्याय 2 संगठन	9
अध्याय 3 डाक प्रचालन	15
अध्याय 4 व्यवसाय विकास कार्यकलाप	23
अध्याय 5 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	31
अध्याय 6 प्रौद्योगिकी	41
अध्याय 7 वित्तीय सेवाएं	45
अध्याय 8 वित्तीय प्रबंधन	51
अध्याय 9 मानव संसाधन विकास	61
अध्याय 10 सतर्कता कार्यकलाप	65
अध्याय 11 अन्य कार्यकलाप	67
अध्याय 12 पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यकलाप	73



भाग-II

कार्यकलाप
(अप्रैल-दिसम्बर, 2001)

Library

IAS, Shimla



00106576

81



CONTENTS

PART I

ANNUAL REPORT (2000-2001)

	Page No.
List of Tables	v
Mission Statement	2
Chapter 1 Overview	4
Chapter 2 Organisation	10
Chapter 3 Postal Operations	16
Chapter 4 Business Development Activities	24
Chapter 5 International Relations	32
Chapter 6 Technology	42
Chapter 7 Financial Services	46
Chapter 8 Financial Management	52
Chapter 9 Human Resource Development	62
Chapter 10 Vigilance Activities	66
Chapter 11 Other Activities	68
Chapter 12 Development Activities in North-East	74

PART II

Activities (April-December 2001)	82
-------------------------------------	----

तालिका सूची

क्र. सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
1.	मनीआर्डर परियात तथा प्रेषित मनीआर्डरों का मूल्य	17
2.	डाक परियात	17
3.	आधुनिकीकृत और कम्प्यूटरीकृत किए गए सेल कार्यालय	19
4.	व्यवसाय विकास कार्यकलापों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि	23
5.	अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट-ई.एम.एस. परियात	35
6.	एल.सी./ए.ओ. डाक	35
7.	विदेश पार्सल परियात	37
8.	विदेश मनीआर्डर	37
9.	बचत योजनाएं : कार्य व्यापार रूपरेखा	45
10.	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन : 2000-2001	47
11.	राजस्व और व्यय (2000-2001)	53
12.	2000-2001 में एजेंसी सेवाओं के संबंध में कार्यकारी व्यय की वसूली	55
13.	2000-2001 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत	57
14.	सेवाओं की लागत	59
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजना व्यय	73
16.	2001-2002 के दौरान डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य व्यापार	89
17.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बकाया पैराओं का ब्यौरा	95
18.	31.3.2001 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	97
19.	31.3.2001 को भूतपूर्व सैनिकों/विकलांग भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला कर्मचारियों की संख्या	97
20.	कार्मिक : 31.3.2001 को वास्तविक संख्या	101
21.	डाकघरों, कार्मिकों तथा मेल परियात की संख्या : रूपरेखा-1947-48 से 2000-2001 तक	103



LIST OF TABLES

Sl.No.	Tables	Page No.
1.	Money Order Traffic and Value of Money Orders Transmitted	18
2.	Mail Traffic	18
3.	Mail Offices Modernised and Computerised	20
4.	Product-wise Revenue Growth of Business Development Activities	24
5.	International Speed Post - EMS	36
6.	LC/AO Mails	36
7.	Foreign Parcel Traffic	38
8.	Foreign Money Orders	38
9.	Saving Schemes : Business Profile	46
10.	Performance of PLI/RPLI : 2000-2001	48
11.	Revenue and Expenditure (2000-2001)	54
12.	Recovery of Working Expenses on account of Agency Services in 2000-2001	56
13.	Funds Surrendered and Saving during 2000-2001	58
14.	Cost of Services	60
15.	Plan Expenditure in North Eastern Region	74
16.	PLI/RPLI Business : 2001-2002	90
17.	Details of outstanding Paras in Report of C & AG of India	96
18.	No. of Employees : Scheduled Castes/Tribes as on 31.3.2001	98
19.	No. of Employees : Ex-servicemen, Disabled Ex-servicemen and Women as on 31.3.2001	98
20.	Personnel : Actual Strength as on 31.3.2001	102
21.	No. of Post Offices, Personnel and Mail Traffic: A Profile - 1947-48 to 2000-2001	104

लक्ष्य और उद्देश्य

भारतीय डाक विभाग का उद्देश्य भारत और पूरे विश्व में उच्च गुणवत्ता वाली डाक, पार्सल और सम्बद्ध सेवाएं प्रदान करना, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और समाज के समक्ष उनकी आशाओं से भी अधिक कार्यकुशल और उत्कृष्ट संगठन के रूप में पहचान बनाना तथा निम्नलिखित कार्य निष्पादित करना है :

- उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के प्रति पूर्ण समर्पण।
- कार्यकुशल और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, यही उपभोक्ता द्वारा खर्च किए धन का असली मूल्य है।
- प्रत्येक कर्मचारी के लिए चुनौतीपूर्ण तथा लाभप्रद कैरियर प्रदान करने के प्रति वचनबद्धता।
- देश के सामाजिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक जीवन के एक भाग के रूप में जिम्मेदारियों को पूर्ण मान्यता प्रदान करना।
- सभी क्षेत्रों में अग्रणी तथा अभिनव बने रहने के प्रति संपूर्ण उत्साह।



MISSION STATEMENT

The Mission of the India Post is to provide high quality mail, parcel and related services in India and throughout the world; to be recognised as an efficient and excellent organisation exceeding the expectations of the customers, employees and the society; to perform the task by:

- Total dedication to understanding and fulfilling customer needs.
- Total devotion to providing efficient and reliable services, which the Customers consider to be value for money.
- Total commitment to providing challenging and rewarding career for every Employee.
- Total recognition of the responsibilities as a part of the social, industrial and Commercial life of the country.
- Total enthusiasm to be forward looking and innovative in all areas.

अध्याय-1

पुनरीक्षा

आर्थिक परिदृश्य

1.1 विश्व भर में डाकघर की भूमिका में परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि पारंपरिक डाक कार्यकलापों का स्थान इलेक्ट्रॉनिक डाक और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने ले लिया है। जन उपयोगिताओं के केन्द्र के रूप में अपनी शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए डाकघर नए कार्यकलापों को तीव्रता से अपना रहा है। अधिकांश देशों में वित्तीय सेवाओं को बल प्रदान करना नई कार्यकलापगत नीतियों का हिस्सा रहा है। इस संदर्भ में वर्ष के दौरान भारतीय डाक ने अपने द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र का व्यापक आधार तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए। इसने प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के साथ अनेक नीतिगत साझेदारी की, जिन सभी का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना तथा विभाग के लिए राजस्व अर्जन में योगदान करना था।

1.2 2000-2001 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6% थी जबकि 1999-2000 के दौरान यह 6.4% तथा 1998-99 में 6.6% थी। लगातार दूसरे वर्ष विकास दर के मंद हो जाने के बावजूद भारत को विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की विशिष्टता प्राप्त है।

1.3 2000-2001 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की कुल विकास दर में 6% तक की कमी का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र की विकास दर में 1999-2000 में 9.6% से 2000-2001 में घटकर 8.3% होना रहा। तथापि 2000-2001 में निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसका कारण व्यापार में और अधिक उदारीकरण, शुल्क में कटौती तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में और अधिक विदेशी निवेश के साथ-साथ रुपए का अवमूल्यन था।

चुनौतियां और कार्यनीतियां

1.4 समूचे विश्व में डाक-प्रशासन, डाक के बढ़ते हुए परिमाण, ग्राहकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता, निजी कुरिअर उद्योग के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संज्ञार प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व विकास के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं। यू.पी.यू. के एक अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि डाक परियात की मात्रा में होने वाली वृद्धि अथवा कमी निम्नलिखित कारकों के कारण हो सकती है:-

* आर्थिक कारक	-	45 प्रतिशत
* डाक कारक	-	24 प्रतिशत
* सामाजिक कारक	-	21 प्रतिशत
* प्रौद्योगिकीय कारक	-	10 प्रतिशत

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी डाक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ (यू.पी.यू.) के तत्वावधान में कार्यनीति तैयार कर रहे हैं।

1.5 जहां एक ओर समाज को उसकी आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से और अपेक्षाकृत सस्ती डाक सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर डाक को अन्य क्षेत्रों जैसे व्यापार तथा उद्योग, सरकारी तथा संस्थागत निकायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकाकर अधिक त्वरित सेवा की मांग करते हैं। विभिन्न श्रेणियों की डाक जैसे घरेलू डाक, सरकारी डाक, कारपोरेट क्षेत्र की डाक, समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं, द्वितीय श्रेणी की अन्य डाक, जिनकी समय-संवेदनशीलता भिन्न-भिन्न होती है, के प्रोसेसिंग को ग्राहकों की सुविधा के अनुरूप बनाने तथा उसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। चुनौतियों का सामना करने और सेवाओं में सुधार लाने के लिए डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का समावेश डाक प्रशासनों द्वारा विश्व भर में इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं। आने वाले समय में ग्राहक की अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी और उसे संतुष्ट रखा जाना निहायत ही आवश्यक है।

विभाग के उद्देश्य

1.6 भारतीय डाक के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- देश के जनजातीय, पहाड़ी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी भागों में बुनियादी डाक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- कार्यकुशल, भरोसेमंद तथा किफायती सेवाएं प्रदान करना;
- बाजार की जरूरतों के अनुसार मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना;
- कार्य की बढ़ती मात्रा को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए सेवाओं का आधुनिकीकरण करना और ग्राहक एवं कर्मचारियों के संतुष्टि-स्तर में वृद्धि करना;
- एक प्रगतिशील संगठन बनाना; तथा



Chapter 1

OVERVIEW

Economic Scenario

1.1 The role of Post Office around the world is undergoing changes as traditional postal activities are supplanted by electronic mail and use of New Technologies. Increasingly, post office is adopting new business to optimize its strength as an outlet of public utilities. Energising Financial Services has been a part of the new business strategies in most countries. In this context during the year India Post took several initiatives to broad base the range of Financial Services provided by it. It forged a number of strategic partnerships with leading financial institutions all aimed at enhancing customer satisfaction and contributing towards revenue generation for the Department.

1.2 Real GDP growth in 2000-2001 was 6% compared to growth rate of 6.4% during 1999-2000 and 6.6% in 1998-99. Despite deceleration of growth rate for the second consecutive year, India had the distinction of being one of the fastest growing economies in the world.

1.3 The reduction of overall growth rate of GDP to 6% during 2000-2001 was mainly due to a decline in the growth rate of the service sector from 9.6% in 1999-2000 to 8.3% in 2000-2001. However, there was a significant growth in exports in 2000-2001 due to rupee depreciation along with further trade liberalization, tariff reductions, and more foreign investment in export oriented sectors like information technology.

Challenges and Strategies

1.4 Postal administrations the world over are grappling with the challenges posed by growing volume of mail, the need to deliver services faster to the customers, increasing competition from private courier industry and unprecedented advances in communications technology. A UPU study has shown that the increase or decline in postal traffic volumes can be attributed to the following factors.

* Economic factors	-	45%
* Postal factors	-	24%
* Social factors	-	21%
* Technological factors	-	10%

Postal administrations everywhere, under the aegis of the Universal Postal Union (UPU), are evolving strategies to respond to these challenges.

1.5 While a relatively cheap and affordable postal service has to be provided to the society at large, the Post also has to cater to the specific needs of segments like the business and industry, government and institutional bodies who demand a much quicker service even at a relatively higher cost. There is a need for customization and prioritization in the processing of different categories of mail like household mail, government mail, corporate sector mail, newspapers and magazines, other second class mail, which have different time-sensitivity. Modernization of postal operations and induction of technology are important steps initiated by postal administrations the world over, to meet the challenges and improve the service. The customer in future is going to be very demanding and he must be kept satisfied.

Objectives of the Department

1.6 The major objectives of India Post are to:

- ensure availability of basic postal services in all parts of the country, including tribal, hilly and remote areas.
- provide efficient, reliable and economic service.
- provide value-added services according to market requirements.
- modernize the services to handle the growing volume of work with efficiency and enhance customer and employee satisfaction.
- be a forward-looking organization, and

- अधिक संसाधन जुटाना और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करना।

1.7 विश्व सेवा दायित्व के प्रति भारतीय डाक की एक प्रतिबद्धता है। यह विश्व सेवा दायित्व के प्रति इसकी प्रतिबद्धताओं और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रति इसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। बीजिंग कांग्रेस 1999 ने यह प्रतिबद्धता दोहराई है। इस प्रतिबद्धता के अनुसार भारतीय डाक को एक किफायती मूल्य पर डाक के संग्रह, प्रेषण और वितरण के लिए बुनियादी सुविधाएं औचित्यपूर्ण ढंग से मुहैया करानी हैं। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार विभाग में 1,54,919 डाकघरों का नेटवर्क है जिनमें से 1,26,146 शाखा डाकघर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ये सभी डाकघर सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार डाक के वास्तविक वितरण की दृष्टि से, शहरी केन्द्रों में प्रतिदिन दो वितरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में छः वितरण प्रदान करने का भारतीय डाक का रिकार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन सहित विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाताओं के साम्य में है। इसे निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:-

1.8 जबकि विभाग लोगों को आसान मूल्य पर बुनियादी डाक सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसने गत कुछ वर्षों से ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर विपणन प्रतियोगी मूल्य पर मूल्यवर्धित डाक सेवाएं शुरू करने के लिए पहल करने की भी कोशिश की है। व्यवसाय विकास निदेशालय द्वारा अनेक मूल्यवर्धित उत्पादों का विपणन किया गया है। इनमें बिजनेस पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, डाटा पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा शामिल हैं। ग्राहकों के विशेष वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे और अधिक उत्पाद, जैसे और जब आवश्यक होंगे, शुरू किए जाएंगे।

1.9 अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000-01 (प्रोजेक्शन) के दौरान 20 सेवाओं में से केवल तीन सेवाएं अपनी पूरी लागत वसूल करने में सफल हो सकीं। वर्ष 2000-01 के दौरान कुल राजस्व 32978.1 मिलियन रुपए था जबकि नेटवर्किंग व्यय 48475.7 मिलियन था जिससे 15497.6 मिलियन रुपए का अंतर रह गया। विभिन्न उत्पादों पर आर्थिक सहायता की सीमा बुक पैटर्न और नमूना पैकेटों पर 81.99% से भारतीय पोस्टल आर्डर पर

	शहरी/दिन	ग्रामीण/सप्ताह
अर्जेंटीना	1.0	-
बेल्जियम	2.0	6.0
ब्राजील	1.0	-
ब्रिटेन	2.0	6.0
चीन	2.5	5.0
मिश्र	2.0	6.0
जर्मनी	1.0	6.0
भारत	2.0	6.0
इंडोनेशिया	3.0	2.0
आयरलैंड	1.0	5.0
इजरायल	1.0	6.0
इटली	1.0	6.0
फिलीपीन्स	2.0	3.0
रूस	2.0	6.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.0	6.0

- generate more resources and improve financial performance.

1.7 India Post has a commitment with regard to the universal service obligation. This is in accordance with its commitments to the Universal service obligation. This is in accordance with its commitments to the Universal Postal Union. The Beijing Congress 1999 has reiterated this commitment. In terms of this commitment, India Post has to provide reasonable access to basic facilities for collection, transmission and delivery of mails at an affordable price. The Department has a network of 1,54,919 post offices as on 31.3.2001 out of which 1,26,146 are branch offices catering to the needs of the rural areas. All these offices are offering full range of services. Similarly, in terms of physical delivery of mails India Post's record of providing two deliveries per day in urban centres and six deliveries a week in rural areas compares well with the best in the world including USA, Belgium, Germany, Britain and China as could be seen from the following table:-

1.8 While the Department is committed to providing basic postal services to the people at an affordable price, it has also in the last few years tried to take initiatives to introduce value added postal services at market competitive price depending on the needs of the customers. A number of value added products have been marketed by the Business Development Directorate including Business Post, Speed Post, Express Parcel Post, Greetings Post, Data Post, Speed Post Passport Service. More such products keeping in view the requirements of specific segments of customers would be introduced as and when necessary.

1.9 During the year 2000-01 (projection) it is estimated that out of 20 services only three services were able to recover full cost. Total revenue during the year 2000-01 was Rs. 32978.1 million against networking expense of Rs. 48475.7 million leaving a gap of Rs. 15497.6 million. The subsidy on various products ranged from 81.99% in respect of "Book Patterns & Sample Packets" to 94.13% in respect of

	Urban/Day	Rural/Week
Argentina	1.0	-
Belgium	2.0	6.0
Brazil	1.0	-
Britain	2.0	6.0
China	2.5	5.0
Egypt	2.0	6.0
Germany	1.0	6.0
India	2.0	6.0
Indonesia	3.0	2.0
Ireland	1.0	5.0
Israel	1.0	6.0
Italy	1.0	6.0
Philippines	2.0	3.0
Russia	2.0	6.0
USA	1.0	6.0

94.13% तक रही। 12 सेवाओं पर डाक शुल्क में 1 जून, 2001 से संशोधन कर दिया गया जिससे 3000 मिलियन रुपये वार्षिक के अतिरिक्त राजस्व के अर्जन होने की आशा है। बजट पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई है:-

- (i) आर्थिक सहायता का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का रखरखाव करने पर खर्च कर दिया जाता है जो 2001-2002 वित्त वर्ष के अंत में अकेले लगभग 5630 मिलियन रुपये यानी कुल आर्थिक सहायता का लगभग 40% बैठता है।
- (ii) पंजीकृत समाचार-पत्रों के प्रेषण के लिए रियायती शुल्क जो 1030 मिलियन रुपये प्रतिवर्ष बैठता है। 'पंजीकृत समाचार-पत्र' शब्द में दैनिक समाचार-पत्रों को छोड़कर विभिन्न प्रकार के साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिकाओं का डाक से प्रेषण शामिल है।
- (iii) मुद्रित सामग्री वाले बुक पैकेटों के डाक द्वारा प्रेषण पर आर्थिक सहायता, जिस पर लगभग 400

मिलियन रुपये प्रति वर्ष बैठता है।

- (iv) मनीआर्डर और पंजीकृत डाक के कम मूल्य निर्धारण के कारण आर्थिक सहायता/मनीआर्डर पर आर्थिक सहायता की राशि 3200 मिलियन रुपये तथा पंजीकृत डाक पर 3900 मिलियन रुपये प्रति वर्ष है।

1.10 विभाग शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में डाक तथा वितरण सेवाओं में सुधार के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहा है। यह प्रधान डाकघरों के संपूर्ण कार्यकलापों का तेजी से कंप्यूटरीकरण कर रहा है तथा और अधिक कंप्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्रों की संस्थापना कर रहा है। विभाग उच्च गति के 150 बी-सेट का नेटवर्क चालू कर रहा है।

1.11 विभाग अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का निरंतर समावेश करते हुए इसे जनोपयोगी सेवा का एक बेहतर साधन बनाने के लिए अपने प्रबंधन को जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के और अधिक अनुरूप करने, सेवाओं को ग्राहकों के और अधिक अनुकूल बनाने तथा प्रणाली को और अधिक सुगम बनाकर परिष्कृत करने का अथक प्रयास कर रहा है।

Indian Postal Order. The postal tariff in respect of 12 services was revised with effect from 1st June 2001 which is expected to generate an additional revenue of Rs. 3000 million annually. The need for subsidization of budget has arisen mainly due to the following reasons:-

- (i) The major portion of the subsidy is consumed for maintaining postal network in the rural areas which alone accounts for approximately Rs.5630 million i.e. about 40% of the total subsidy at the end of 2001-2002 financial year.
- (ii) Concessional tariff for transmission of registered newspapers which account for Rs.1030 million per year. The term registered newspaper includes transmission by post of weekly/fortnightly/monthly magazines and journals of kinds other than the daily newspapers.
- (iii) Subsidy on account of transmission by post of book packets containing printed

materials which accounts for about Rs. 400 million per year.

- (iv) Subsidy on account of under-pricing of Money Order and Registered Post. On Money Order the amount of subsidy is Rs. 3200 million and on Registered Post Rs. 3900 million per year.

1.10 The Department is taking various steps to improve the mail and delivery services in both urban and rural areas. It is busily computerizing the entire functions in Head Post Offices and setting up more computerized registration centres. The Department is commissioning a network of 150 high speed VSATs.

1.11 The Department is sparing no efforts to make the management more responsive to public needs and expectations, make the services more customer friendly and humanize the system more perceptibly even as it inducts and assimilates increasing doses of technology into its operations to make a better instrument of public utility service.

अध्याय-2

संगठन

2.1 भारतीय डाक, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है। यह विभाग श्री प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अधीन काम कर रहा है। श्री तपन सिकंदर, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। श्री एस.सी. दत्ता, सचिव, डाक विभाग के साथ-साथ महानिदेशक, भारतीय डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड हैं।

2.2 डाक सेवा बोर्ड इस विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष और तीन सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के पास प्रचालन, आधारीक संरचना एवं वित्तीय सेवाएं तथा कार्मिक विभाग हैं। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, सचिव, डाक सेवा बोर्ड के बतौर बोर्ड की सहायता करते हैं। इस समय, उप महानिदेशक (फिलैटली), सचिव, डाक सेवा बोर्ड के बतौर बोर्ड की सहायता कर रहे हैं। मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक कार्यात्मक सहयोग देते हैं।

2.3 डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल, राज्य का सह-टर्मिनस है। इसके अपवाद हैं-पूर्वोत्तर सर्किल जिसमें छह उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र सर्किल जिसमें गोवा राज्य शामिल है, पश्चिम बंगाल सर्किल जिसमें सिक्किम राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, केरल सर्किल में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शामिल है और पंजाब में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। प्रत्येक सर्किल की अध्यक्षता प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा की जाती है। प्रत्येक सर्किल को परिक्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें फील्ड यूनिटें होती हैं, जिन्हें डिवीजन (डाक/रेल डाक सेवा डिवीजन) कहा जाता है। हरेक परिक्षेत्र की अध्यक्षता पोस्टमास्टर जनरल द्वारा की जाती है जो उस क्षेत्र का डाक प्रबंधक होता है। सर्किलों और परिक्षेत्रों में सर्किल स्टैम्प डिपो, डाक भंडार डिपो तथा मेल मॉटर सेवा आदि जैसी अन्य प्रकार्यात्मक अवलंबी संभार तंत्र यूनिटें भी होती हैं।

2.4 इन 22 सर्किलों के अलावा एक अन्य डाक सर्किल भी है जिसे बेस सर्किल कहा जाता है, जो सशस्त्र सेनाओं की डाक संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बेस सर्किल की अध्यक्षता अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा द्वारा की जाती है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में शत-प्रतिशत सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं तथा सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के लिए भी 75 प्रतिशत कार्मिक डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

2.5 देश भर में डाकघरों को मुख्य, उप तथा शाखा डाकघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। उप डाकघर विभागीय डाकघर हैं जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। मुख्य डाकघरों को उनके कार्यभार तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है, इनमें से सबसे बड़े डाकघर मुंबई और कलकत्ता के जनरल पोस्ट आफिस (जी.पी.ओ.) हैं और उनके बाद अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ स्थित जी.पी.ओ. आते हैं।

2.6 विभाग के संगठनात्मक ढांचे में, प्रौद्योगिकी के समावेश के कारण संचार बाजार में भारतीय डाक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में पिछले कुछ समय से पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन को परिवर्तन की संक्रमणकालीन समस्याओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे उच्चतर प्रबंधन में समन्वय और मानीटरिंग की भूमिका को समुचित महत्व देते हुए मुख्यतया प्रकार्यात्मक आधार पर तैयार किया गया है। निर्णयकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए पारंपरिक पिरामिड प्रणाली को डेस्क प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये सुधार प्रणाली को उस गतिशीलता और सामर्थ्य से अनुप्राणित कर देंगे जो एक अनुक्रियाशील, संवेदनशील, दक्ष और कुशल प्रबंध प्रणाली के लिए आवश्यक है।



Chapter 2

ORGANISATION

2.1 The India Post under the Ministry of Communications and Information Technology continues to function under Shri Pramod Mahajan, Minister of Parliamentary Affairs and Communications & Information Technology. Shri Tapan Sikdar is the Minister of State for Communications & Information Technology. Shri S.C. Dutta is the Secretary, Department of Posts, Director General, India Post and the Chairman of the Postal Services Board.

2.2 The Postal Services Board, the apex management body of the Department, comprises the Chairman and three Members. The three members of the Board hold portfolios of Operations, Infrastructure & Financial Services, and Personnel. The Joint Secretary and Financial Adviser to the Department is a permanent invitee to the Board. The Board is assisted by a senior officer of the Directorate as Secretary to the Board and presently DDG(Philately) is assisting the Board in this capacity. Dy. Directors General, Directors and Assistant Directors General provide necessary support for the Board at the Headquarter.

2.3 For providing postal services, the whole country has been divided into 22 Postal Circles. Each circle is co-terminus with a State except in case of the North Eastern Circle comprises six North Eastern States, Maharashtra Circle includes the State of Goa, West Bengal Circle includes the State of Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Kerala Circle includes the Union Territory of Lakshadweep and Punjab Circle includes the Union Territory of Chandigarh. A Principal Chief Postmaster General/Chief Postmaster General heads each of these Circles. Each circle is divided into Regions comprising groups of field units, called Divisions (Postal/RMS Divisions). Each Region is headed by a Postmaster General who is the Postal Manager of the area. In the Circles and Regions there are other functional

supporting logistical units like Circle Stamp Depots, Postal Stores Depots and Mail Motor Service etc.

2.4 Over and above these 22 Circles, there is another Postal Circle, the Base Circle, to cater to the postal communication needs of the armed forces. Base Circle is headed by the Additional Director General, Army Postal Service. Cent per cent of the officer cadre of Army Postal Services is on deputation from the civil post and 75 per cent of the other ranks of the Army Postal Service are also drawn from the Department of Posts and the remaining personnel are recruited by the Army.

2.5 Post offices in the country are categorised as Head, Sub and Branch Post Office. Gramin Dak Sewa Branch Post Offices are located in rural areas. The Sub Post Offices are departmental offices located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the largest being the General Post Offices at Mumbai and Calcutta, followed by GPOs at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Kanpur and Lucknow.

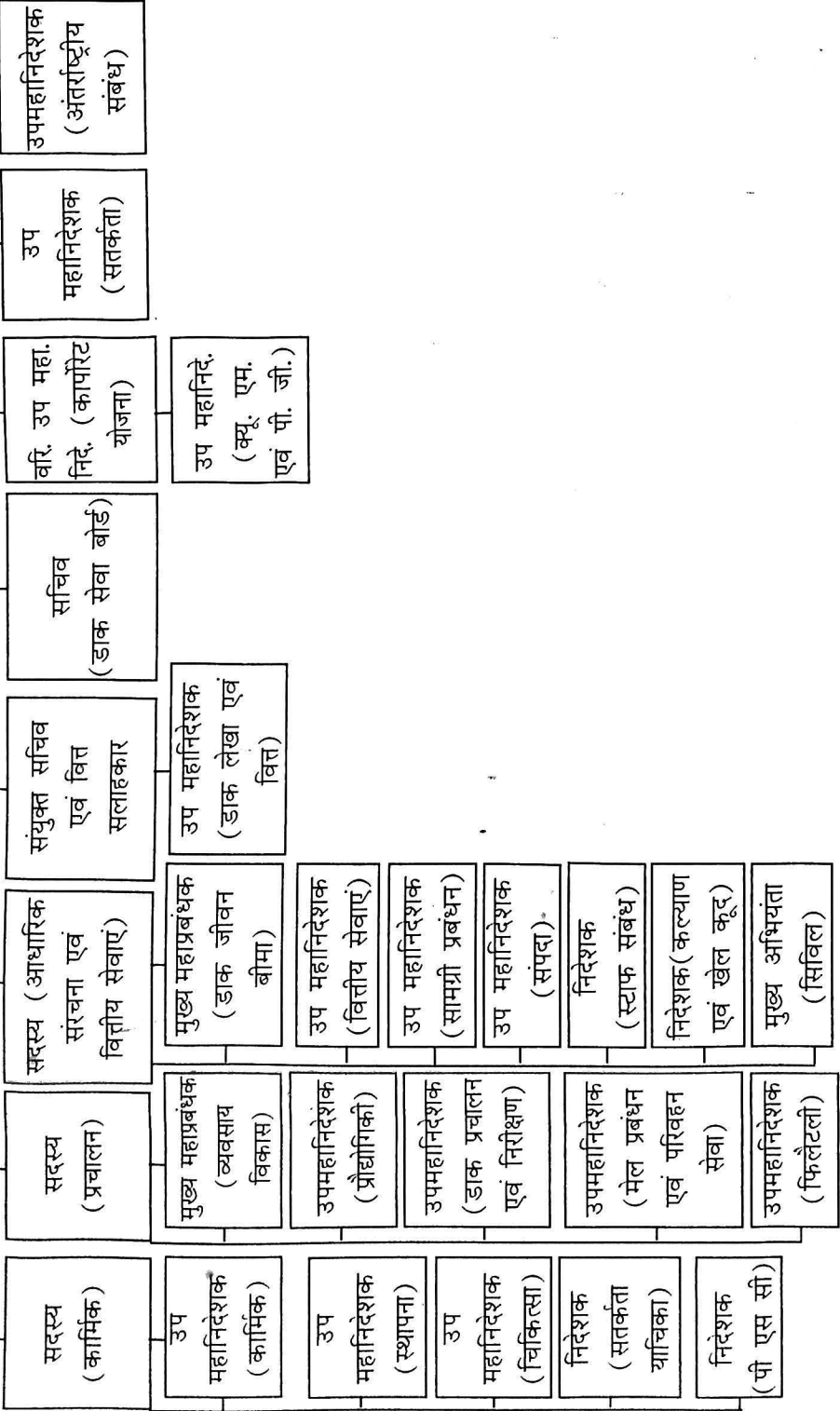
2.6 The organisational set up of the Department has been undergoing restructuring in recent times as a response to the challenges faced by the post in the communication market due to induction of technology. This restructuring is designed to tackle the transitional problems of change and is primarily on functional basis giving due importance to the coordinating and monitoring role of the higher management. Steps have been taken to substitute the traditional pyramidal system with desk level system to support the decision-makers. These reforms are being introduced to infuse the system with dynamism and strengths that are needed to create a responsive, sensitive & efficient and management system.

डाक विभाग का संगठनात्मक चार्ट

संसदीय कार्य और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

सचिव/महानिदेशक डाक, अध्यक्ष डाक सेवा बोर्ड

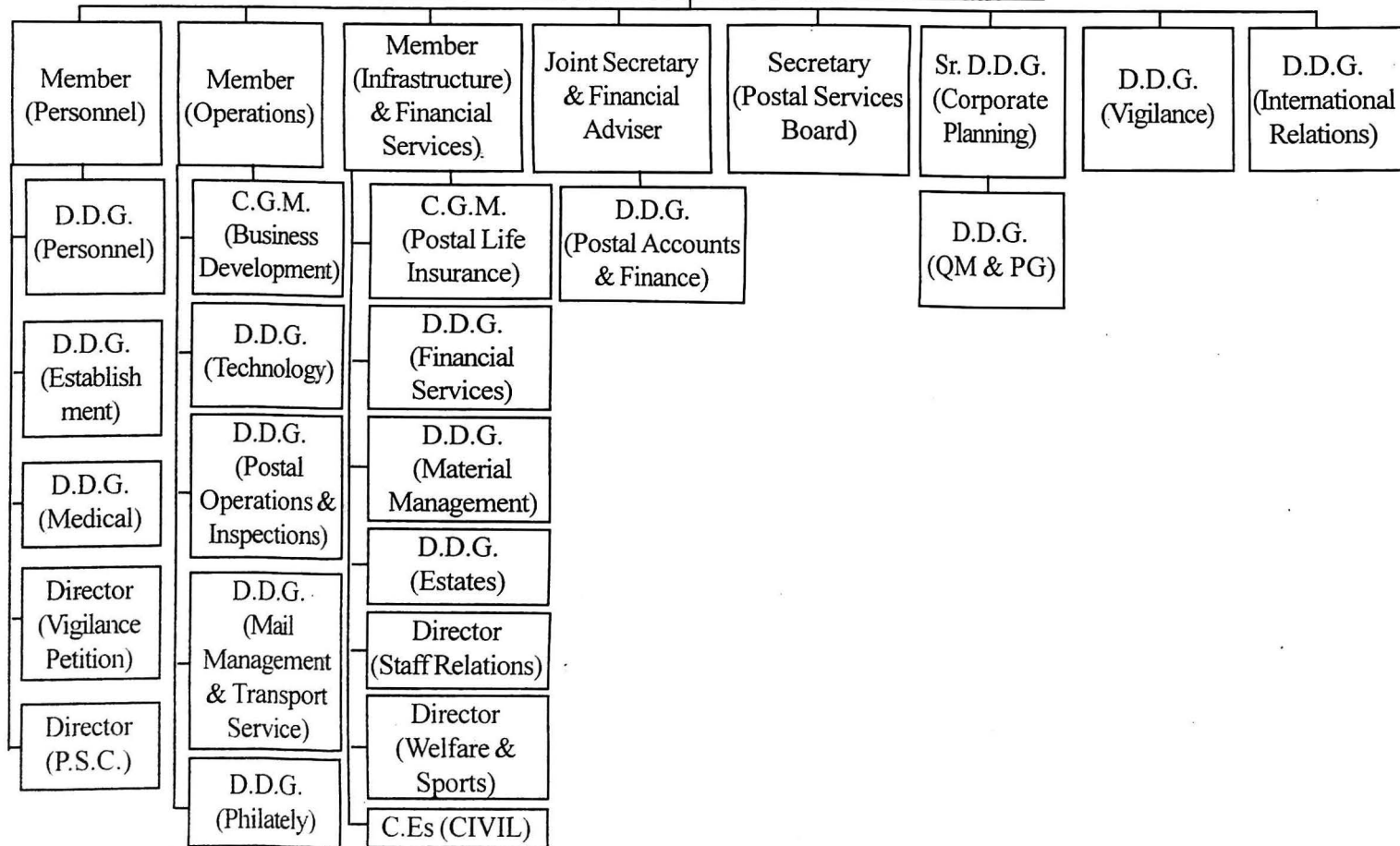


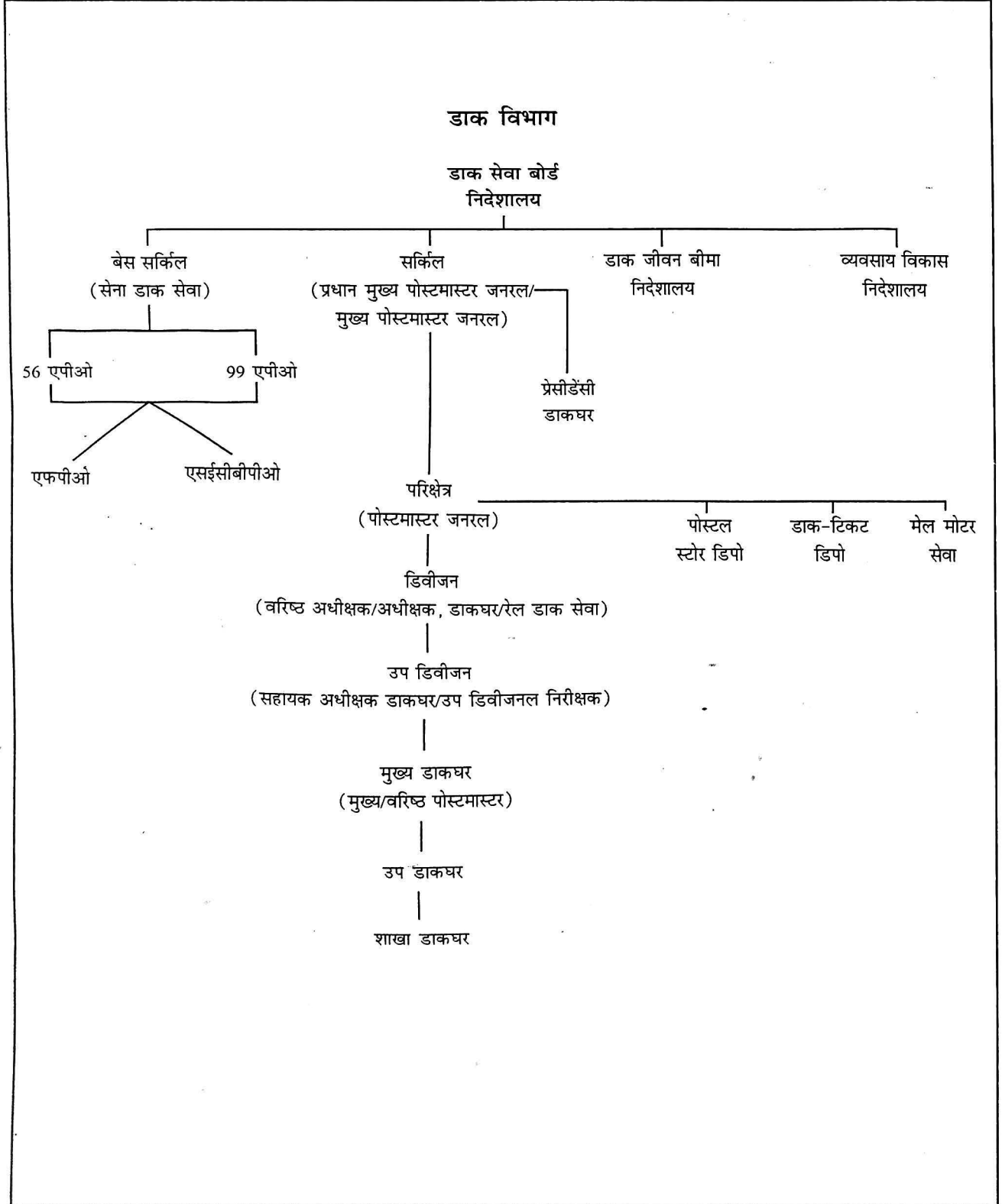
ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF POSTS

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS
& INFORMATION TECHNOLOGY

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS
&
INFORMATION TECHNOLOGY

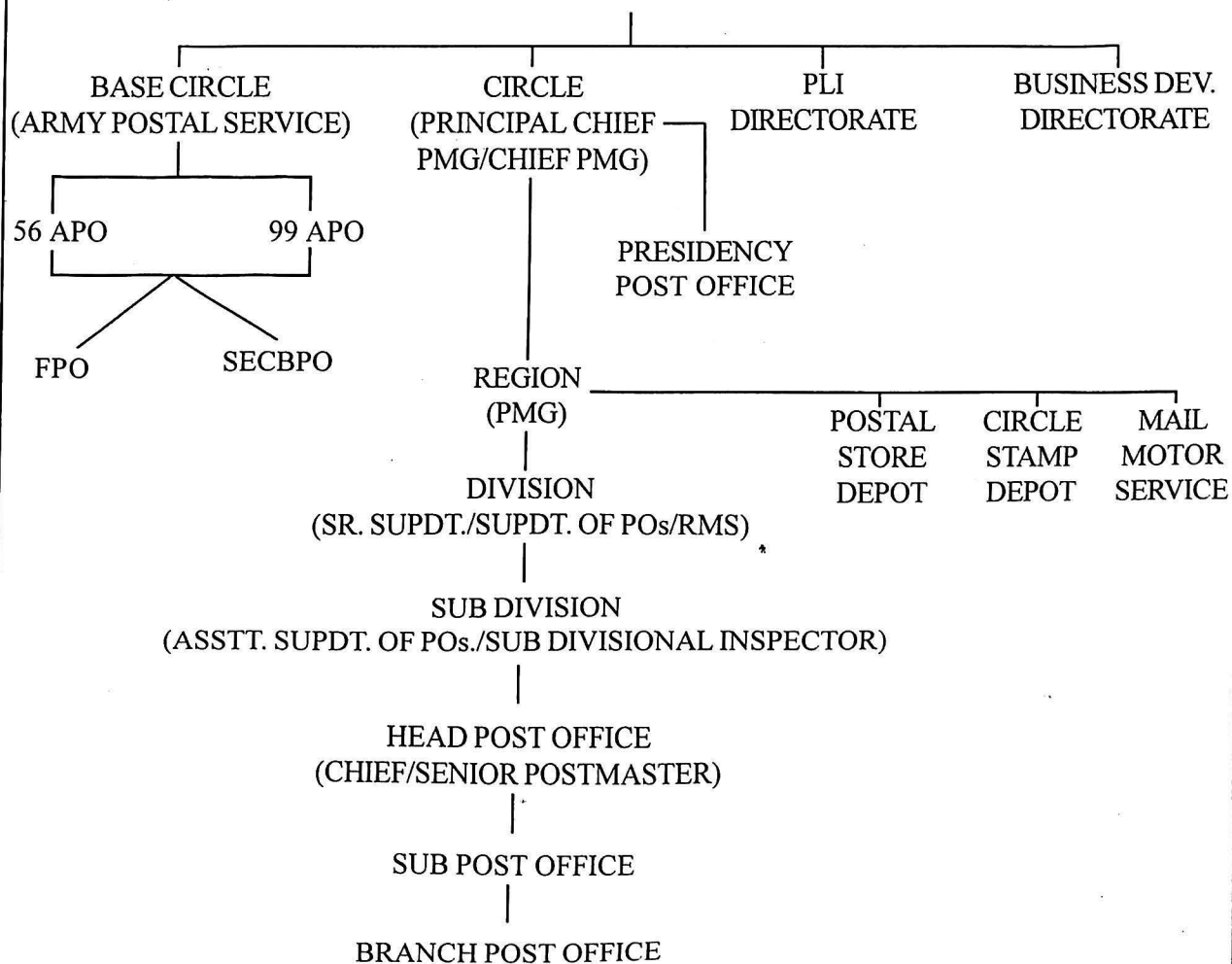
SECRETARY/DIRECTOR GENERAL, POSTS/CHAIRMAN,
POSTAL SERVICES BOARD





DEPARTMENT OF POSTS

POSTAL SERVICES BOARD DIRECTORATE



अध्याय-3

डाक प्रचालन

डाक नेटवर्क

3.1 वित्तीय वर्ष के अंत तक अर्थात् 31.3.2001 तक भारतीय डाक का 1,54,919 कार्यालयों का नेटवर्क जिसमें ग्रामीण डाक क्षेत्र के 1,38,443 डाकघर भी शामिल हैं, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 23,344 डाकघर थे जिनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में और चुनिंदा गांवों में ही चल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पिछले 50 वर्षों के दौरान डाकघरों का नेटवर्क का विस्तार अपनी क्षमता से सात गुना अधिक हुआ है। एक डाकघर औसतन 21.21 वर्ग कि.मी. के घेरे तथा 5449 की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है।

3.2 देश के डाक नेटवर्क का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर की पद्धति के माध्यम से किया गया जिन्हें अतिरिक्त विभागीय एजेंट कहा जाता था। इन्हें अब ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जाना जाता है। हाल के वर्षों में, दूर-दराज तथा दूरवर्ती गांवों जिनमें अभी भी कोई डाकघर नहीं है, में आधारभूत डाक सेवा उपलब्ध करवाने के मद्देनजर डाक सेवा के तीसरे स्तर अर्थात् पंचायत संचार सेवा केन्द्र को प्रारंभ किया गया। ये केन्द्र डाक-टिकटों तथा डाक स्टेशनरी की बिक्री, पत्रों को एकत्रित करने एवं उन्हें वितरित करने तथा पंजीकृत मदों आदि को बुक करने संबंधी जैसी मूलभूत सेवाओं को रिटेल में उपलब्ध कराने के लिए नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय दोनों ने सिफारिश की है कि ग्रामीण डाक सेवक द्वारा चलाए जा रहे शाखा डाकघरों को पंचायत संचार सेवा योजना में बदलने पर विभाग को विचार करना चाहिए। इससे कम खर्च में डाक सेवा की अधिक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी तथा यह पंचायतों की अंतरित शक्तियों के अनुरूप होगी।

3.3 “डाक नेटवर्क का विस्तार” योजना स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमलाप शुरू किए गए हैं :-

- (क) उन गांवों, अधिमानतः ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघर खोलना, जहां फिलहाल कोई डाकघर नहीं है तथा जहां निर्धारित मानदंडों के आधार पर डाकघर खोलने का औचित्य है बशर्ते कि लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध हों। पहाड़ी, जनजातीय और दुर्गम

क्षेत्रों में डाक नेटवर्क उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।

- (ख) जहां कहीं मानदंडों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर औचित्यसम्मत हो, विशेष रूप से नये विकसित शहरी क्षेत्रों और शहरों में अधिक आबादी वाले औद्योगिक टाऊनशिप आदि में ग्रामीण डाक सेवा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर करना। वर्ष 2000-2001 अर्थात् नौवीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के दौरान देश भर में कुल 363 ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघर तथा 52 विभागीय उप डाकघर खोले गए। वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए 500 ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान 2005 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए। वर्ष 2001-2002 के लिए 2000 पंचायत संचार केन्द्र खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है।

डाक सेवाएं

3.4 डाकघर में डाक प्रचालनों में अन्य सेवाओं के साथ-साथ निम्नलिखित मूल डाक सेवाओं का समूचा क्षेत्र शामिल है:-

- डाक-टिकट तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री
- पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग
- बीमाकृत वस्तुओं की बुकिंग
- मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग
- मनीआर्डर और पोस्टल आर्डरों के माध्यमों से धन प्रेषण तथा
- पार्सलों की बुकिंग

3.5 परंपरागत रूप से ये सेवाएं मैनुअल काउंटरों पर प्रदान की जा रही थीं। ग्राहकों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब काउंटर प्रचालनों को उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि एक



Chapter 3

POSTAL OPERATIONS

Postal Network

3.1 At the end of the financial year i.e. 31-3-2001, India Post with its network of 1,54,919 Post Offices which includes 1,38,443 Post Offices in rural areas, has the largest network in the world. At the time of independence India had 23,344 Post Offices, which were largely confined to urban areas and selected villages. During the 50 years since independence, the network of post office has grown to seven times its strength. On an average, a post office serves an area of 21.21 sq. km. & population of 5449.

3.2 Expansion of postal network in the country especially in rural areas was mainly done through a system of Extra Departmental Branch Post Offices, named by Extra Departmental Agents now called Gramin Dak Sewaks. In recent years, in order to provide access to basic postal facilities for people in far-flung and remote villages, which are still without a Post Office, a third tier of postal service i.e. Panchayat Sanchar Sewa Kendras has been introduced. These Kendras serve as nodal point for retailing some of the basic services like sale of stamps and postal stationery, collection and delivery of letters and booking of registered articles etc. Both Planning Commission and the Ministry of Finance have recommended that Department should consider replacing the Gramin Dak Sewak run Branch offices by Panchayat Sanchar Sewa Yojna. This would ensure greater access to postal services at lesser cost and in conformity with devolution of powers to Panchayats.

3.3 The following activities have been undertaken under Plan Scheme "Expansion of Postal Network".

- (a) Opening of Gramin Dak Sewa Branch Post Offices in villages, preferably Gram Panchayat Head Quarter villages where no Post Office exists at present and where such a Post Office is justified on the basis of prescribed norms, subject to availability of targets and resources. There

was a special emphasis on provision of postal network in hilly, tribal and inaccessible areas.

- (b) Upgradation of Gramin Dak Sewa Branch Offices into Departmental Sub Offices (DSOs) where justified with particular emphasis on newly developed areas of cities, urban agglomerations industrial townships etc., on norm based justification and availability of resources. During the year 2000-2001, the 4th Year of the 9th Five Year Plan, a total number of 363 Gramin Dak Sewa Branch Offices and 52 Departmental Sub Offices (DSOs) were opened throughout the country. A target of opening of 500 Gramin Dak Sewa Branch Offices and 50 Departmental Sub Offices (DSOs) has been set for Annual Plan 2001-2002. 2005 Panchayat Sanchar Sewa Kendras were opened during the year 2000-2001. A target of opening 2000 Panchayat Sanchar Kendras has also been fixed for the year 2001-2002.

Postal Services

3.4 Postal operations at the post office encompass the entire gamut of the basic postal services which inter alia include:

- (i) Sale of stamps and stationery
- (ii) Booking of registered articles
- (iii) Booking of insured articles
- (iv) Booking of value payable articles
- (v) Remittance of money through money orders and postal orders
- (vi) Booking of Parcels

3.5 Traditionally, these services were being provided at manually operated counters. Considering the vital need for providing the benefit of technology to the customers, the counter operations are now being progressively computerised to provide a greater range

ही खिड़की से अधिकाधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकें जिससे सेवाएं अधिक अनुक्रियाशील हों और उनमें गलती की संभावना भी कम हो तथा व्यर्थ के काम से बचा जा सके।

3.6 पिछले वर्ष के परियात की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पारेषित मनीआर्डर के मूल्य तथा मनीआर्डर परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1 में दिए गए हैं।

तालिका-1 मनीआर्डर परियात तथा पारेषित मनीआर्डरों का मूल्य			
	1999-2000	2000-2001	वृद्धि/कमी
1. मनीआर्डर परियात (मिलियन में)	113.7	109.5	(-)3.69%
2. पारेषित मनीआर्डरों का मूल्य (मिलियन रु. में)	57079.4	58518.4	(+)2.52%

डाक प्रचालन

3.7 डाक प्रोसेसिंग, पारेषण तथा उनका वितरण विभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। देश की 0.60 मिलियन पत्र-पेटियों से पत्रों को एकत्रित किया जाता है। 548 रेल डाक सेवा (आर एम एस) कार्यालयों के नेटवर्क पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तथा देश

भर में रेल, वायुयान तथा सड़क परिवहन सहित उपलब्ध परिवहन साधनों से इन्हें प्रेषित किया जाता है।

डाक परिमाण

3.8 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान डाक परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-2 में दिए गए हैं।

तालिका-2 डाक परियात (मिलियन में)			
वर्ष	1999-2000	2000-2001	वृद्धि/कमी
1. पंजीकृत वस्तुएं	275.9	245.2	(-) 11.00%
2. अपंजीकृत वस्तुएं	15505.6	13958.0	(-) 9.00%
3. कुल (1+2)	15781.5	14203.2	(-) 10.00%

डाक प्रबंधन

3.9 देशभर में अत्यधिक प्रभावी और अधिकतम कुशल डाक पारेषण नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग ने डाक परियात के विभिन्न भागों का पता लगाया है और प्रत्येक भाग के लिए परियात के निपटान का विशिष्ट तरीका निश्चित किया है। इस प्रकार महानगरों के बीच की डाक के लिए मैट्रो चैनल राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों के बीच तथा इसके विपरीत के लिए राजधानी चैनल, स्थानीय डाक के लिए ग्रीन चैनल, थोक डाक के लिए बिजनेस चैनल और समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए पत्रिका चैनल जैसे विशिष्ट चैनल बनाए गए हैं।

3.10 दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन तथा नववर्ष जैसे फेस्टिवल

सीजन के दौरान डाक की मात्रा में होने वाली आकस्मिक वृद्धि से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रमुख शहरों में, लोगों को उनके पत्र सीधे गंतव्य थैलों में डालने के लिए उचित सुझाव दिया गया जिससे प्रेषितियों को पत्रों का वितरण जल्दी किया जा सके।

डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण

3.11 विभाग ने डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण की एक नीति प्रारंभ की है। डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण का उद्देश्य डाक कार्यालयों में बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना और बेहतर कार्य के वातावरण का निर्माण करना है जिससे संपूर्ण कार्यकुशलता प्राप्त हो सके।

of service from a single window leading to services being more responsive and error free also removing the drudges of work.

3.6 Comparative statistics of Money Order traffic and the value of Money Order transmitted during the year under report as compared with traffic in the previous year are given in Table 1.

TABLE 1			
MONEY ORDER TRAFFIC AND VALUE OF MONEY ORDERS TRANSMITTED			
	1999-2000	2000-2001	Increase/Decrease
1. Money Order traffic (In million)	113.7	109.5	(-)3.69%
2. Value of MOs transmitted (Rs.in million)	57079.4	58518.4	(+)2.52%

Mail Operations

3.7 Mail processing, transmission and delivery are the core activities of the Department. The letters are collected from 0.60 million letter boxes in the country. These are processed by a network of 548 Railway Mail Service (RMS) Offices, and

conveyed by available transports including rail, airlines and road transport, all over the country.

Mail Volume

3.8 Comparative statistics of mail traffic handled during 2000-2001 as compared to previous year, is given in Table 2.

TABLE 2			
MAIL TRAFFIC (In million)			
Year	1999-2000	2000-2001	Increase/Decrease
1. Registered Articles	275.9	245.2	(-) 11.00%
2. Unregistered Articles	15505.6	13958.0	(-) 9.00%
3. Total (1+2)	15781.5	14203.2	(-) 10.00%

Mail Management

3.9 Plans for achieving an efficient mail transmission network throughout the country have been put into effect. With this objective in view, the Department has identified the different segments of mail traffic and devised exclusive handling for each segment. Thus, there are specialised channels like Metro Channel for mail between metro cities, Rajdhani Channel for mail between the national capital and the state capitals and vice-versa, Green Channel for local mail, Business Channel for bulk mail and Patrika Channel for newspapers and periodicals.

3.10 Special arrangements to meet the sudden spurt in traffic during festival season like Diwali, X Mas,

Raksha Bandhan and New Year were made. In major towns, appropriate guidance was provided to the members of the public to post their letters directly into the destination mail bags to speed up transmission delivery to addressees.

Modernisation and Computerisation of Mail Operations

3.11 In order to expedite transmission, processing and delivery of mail, the Department has embarked on a policy of computerisation and modernisation of the mail transmission, processing and delivery in mail offices. The modernisation of mail offices aims at providing better equipment and improved work environment in the Mail Offices, in order to achieve greater over all efficiency.

3.12 लेखादेय मदों जैसे पंजीकृत पत्रों, बीमाकृत मदों आदि की छंटाई को इन मदों के त्वरित निपटान एवं सुरक्षा के उद्देश्य से और शिकायतों/पूछताछ के मामले में अधिक शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

3.13 ट्रांजिट मेल आफिस (टी.एम.ओ.), विशेष रूप से बड़े शहरों में हवाई अड्डों पर डाक के पारेषण का महत्वपूर्ण चरण होते हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान 8 टी.एम.ओ. का कम्प्यूटरीकरण

किया गया जिससे कुल कम्प्यूटरीकृत टी.एम.ओ. 28 हो गए हैं। समग्र योजना यह है कि मेल प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों के बीच संबद्धता स्थापित की जा सके ताकि एक बार जिस डाक वस्तु की प्रविष्टि कर दी जाए, उसे दुबारा अनुवर्ती चरणों में प्रविष्टि करने की आवश्यकता न पड़े।

डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण की उपलब्धि इस प्रकार है :-

तालिका-3 आधुनिकीकृत और कम्प्यूटरीकृत डाक कार्यालय		
कार्यकलाप	2000-01	कुल
मेल आफिसों का आधुनिकीकरण	27	177
रजिस्ट्रेशन सार्टिंग का कम्प्यूटरीकरण	4	60
ट्रांजिट मेल आफिसों का कम्प्यूटरीकरण	8	28

मेल मोटर सेवा (एम एम एस)

3.14 मेल मोटर सेवा विभाग के 1135 मेल मोटर वाहनों और 486 स्टाफ कारों/निरीक्षण वाहनों के रखरखाव, प्रचालन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अपने मेल मोटर वाहन 94 स्टेशनों में चलते हैं। इनमें से 17 स्टेशनों पर बड़े मरम्मत कार्य और रखरखाव कार्य करने के लिए पूर्ण विकसित वर्कशाप सुविधाएं उपलब्ध हैं।

3.15 वर्ष 2000-2001 के दौरान, विभागीय डाक वाहनों ने डाक प्रेषित करने के लिए 24.6 मिलियन कि.मी. की दूरी तय की। इस अवधि के दौरान एम.एम.एस. पर 424.4 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

3.16 डाक के बढ़ते परिमाण और प्रचालन के व्यापक क्षेत्र की आवश्यकता से निपटने के लिए, एम.एम.एस. बेड़े के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए, जिससे प्रतिदिन प्रति डाक वैन का औसत 70 कि.मी. से बढ़कर 72 कि.मी. हो गया।

3.17 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के संबंध में मील-दूरी के नीति निर्देशों के अनुपालन में 5 नए वाहनों को खरीदा गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को सप्लाय किया गया जहां परिवहन के विश्वसनीय और वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं थे।

सामग्री प्रबंधन

3.18 निदेशालय के सामग्री प्रबंधन डिवीजन को देश भर में डाक नेटवर्क प्रचालन के लिए आवश्यक सामग्री, प्रपत्र और उपकरण उपलब्ध कराने, उनकी मानीटरिंग तथा आपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अनेक प्रकार के डाक थैले, लैटर बॉक्स, वर्दी की मदें, कागज तथा अन्य आधारभूत उपकरण या तो सामग्री प्रबंधन डिवीजन द्वारा सीधे प्राप्त और मुहैया कराए जाते हैं अथवा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की एजेंसियों के माध्यम से इनकी आपूर्ति की जाती है। तथापि वर्ष के दौरान कई प्रापण कार्य सर्किलों को विकेंद्रित कर दिए गए हैं जैसे वर्दी, छाता, जूट और सूती ट्वाइन पोस्ट-बाक्स कैबिनेट तथा जूते। इसका उद्देश्य निदेशालय में सामग्री प्रबंधन डिवीजनों को पूरी तरह से पालिसी निर्धारण डेस्क के तौर पर पुनर्गठित करना है। डाकघरों को यह आपूर्ति 46 पोस्टल स्टोर डिपो (पी.एस.डी.) तथा 5 रीजनल फार्म डिपो (आर.एफ.डी.) के माध्यम से की जाती है। ये डिपो उन डाक सर्किलों के अध्यक्षों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं जहां वे स्थित होते हैं। इन डिपो के अतिरिक्त भुवनेश्वर में एक डाक मुद्रण प्रेस है।

3.19 आधुनिकीकरण और बेहतर इन-हाउस सुविधाएं प्रदान करने के भाग के तौर पर, पी.एस.डी./आर.एफ.डी. को मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति की जाती है। प्रभावी सामान सूची

3.12 Sorting of accountable articles like registered letters, insured articles etc., has been computerised for speedy and safe handling of these articles and for more expeditious response in case of complaints/enquiries.

3.13 The Transit Mail Offices (TMOs) especially at the airports in big cities, are crucial stages in the transmission of mail. During 2000-2001, 8 TMOs

have been computerised bringing the total of computerised TMOs to 28. The overall plan is to establish connectivity among different stages of mail processing so that data about a mail-piece once entered, need not be entered again at every subsequent stages of mail processing.

The achievement of modernization and computerisation of mail offices is as follows:

TABLE 3		
MAIL OFFICES MODERNISED AND COMPUTERISED		
Activity	2000-01	Total
Modernisation of mail offices	27	177
Computerisation of Registration Sorting	4	60
Computerisation of Transit Mail Offices	8	28

Mail Motor Service (MMS)

3.14 The Mail Motor Service is responsible for maintenance, operations and administration of 1135 Mail Motor Vehicles and 486 staff cars/ inspection vehicles of the Department. The Department operates its own fleet of mail motor vehicles at 94 stations. Full-fledged workshop facilities for major repairs and maintenance are available at 17 of these stations.

3.15 During 2000-2001 the departmental mail vans covered 24.6 million kms for conveying mails. An expenditure of Rs.424.4 million was incurred on MMS during this period.

3.16 To cope with the requirement of increased volume of mail and wider area of operation, steps were taken to maximize utilisation of the MMS fleet, which increased the average per mail van per day from 70 kms to 72 kms.

3.17 In compliance of the mileage policy directives regarding development of North Eastern Region, 5 new vehicles were purchased and supplied to the remote and backward areas of North Eastern Region where reliable and alternate means of transport were not available.

Material Management (MM)

3.18 Material Management (MM) Division of the Directorate is entrusted with the responsibility of procuring monitoring and supplying material, forms, and equipments required for postal network operation throughout the country. A large variety of mail bags, letter boxes, uniform items, paper and other infrastructural equipment is either procured and supplied directly by Material Management Division or through the agencies of the Directorate General of Supply and Disposal. However, during the year many procurement functions have been decentralised to the circles like procurement of uniform, umbrellas, jute and cotton twine, post box cabinets and footwear. The aim is to restructure the Material Management Division in the Directorate into a purely policy making desk. The supply of stores to post offices is done through 46 Postal Store Depots (PSDs) and 5 Regional Form Depots (RFDs). These Depots work under the administrative control of Heads of Postal Circles in whose jurisdiction they are located. Apart from these Depots, there is a Postal Printing Press at Bhubaneswar.

3.19 As a part of modernisation and providing better in-house facilities, machinery and equipment is supplied

(इन्वेंटरी) नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा 46 डाक भंडार डिपो का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया है।

फिलैटली

3.20 फिलैटली विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना रहा। विशेष डाक-टिकट जारी किए जाने के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया गया। 1.4.2000 से 31.3.2001 की अवधि के दौरान 61 डाक-टिकट जारी किए गए।

3.21 फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार व्यक्तित्व आधारित डाक-टिकटों को विषयगत सेटों में जारी किया जाता है। विभाग ने निम्नलिखित अवसरों पर डाक-टिकटों के सेट जारी किए जिनका शीर्षक था-15 अगस्त, 2000 को "महान नेता : सामाजिक एवं राजनैतिक" (चार डाक-टिकटों का सेट); 31 दिसम्बर, 2000 को "व्यक्तित्व : ऐतिहासिक"; और 27 जनवरी, 2001 को "महान राजनैतिक नेता"।

3.22 भारतीय डाक ने 2 अक्टूबर, 2000 को गांधीजी के फोटो वाला अंतर्देशीय पत्र कार्ड जारी करके इस वर्ष अंतर्देशीय पत्र कार्ड के 50 वर्ष मनाए। वर्ष के दौरान डाक लेखन सामग्री जैसे पोस्टकार्डों, लिफाफों, पंजीकृत लिफाफों, अंतर्देशीय पत्र कार्डों और एरोग्राम जिन पर विज्ञापन और जनता को जागरूक करने वाले उद्धरण और संदेश आदि अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा में लिखे थे, का अभिनव प्रयोग जारी रहा।

3.23 इस अवधि के दौरान, विभाग ने कला और संस्कृति, वनस्पति और जीव-जन्तुओं, विरासत आदि पर भी सुंदर डाक-टिकट जारी किए जैसे :-

- मणिपुर और त्रिपुरा की प्राकृतिक विरासत पर चार डाक-टिकटों का सेट;
- देशी नस्ल के मवेशी, दून घाटी में रेलवे के 100 वर्ष पर चार डाक-टिकटों का सेट;

- सिडनी ओलम्पिक पर चार डाक-टिकटों का सेट;
- अंतरिक्ष विषय पर तीन डाक-टिकटों का सेट;
- मधुबनी-मिथिला चित्रकला पर चार डाक-टिकटों का सेट;
- रत्नों और आभूषणों पर छः डाक-टिकटों का सेट; और
- अंतर्राष्ट्रीय बेड़े का पुनर्विलोकन पर चार डाक-टिकटों का सेट।

3.24 देश भर में 55 फिलैटलिक ब्यूरो और 212 फिलैटली काउंटर्स के अलावा देश के सभी मुख्य डाकघरों के माध्यम से फिलैटली की वस्तुओं का विक्रय किया गया।

3.25 अगस्त 2000 में "सभ्यता के मध्य संवाद" विषय पर डाक-टिकट डिजाइन करने के लिए एक देशव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई। देशभर से 124 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। सी.बी. डी. बेलापुर, नवीं मुंबई महाराष्ट्र के श्री सुभाष ई. पवार का डिजाइन जजों की समिति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यू पी यू भेजा गया।

3.26 वर्ष 1999 में विभाग द्वारा जारी सर्वाधिक लोकप्रिय डाक-टिकटों का चयन करने के लिए डाक विभाग द्वारा 10 से 25 अक्टूबर, 2000 के दौरान एक डाक-टिकट लोकप्रियता मतदान कराया गया। देशभर से लगभग 95,396 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। वर्ष 1999 के तीन सर्वाधिक लोकप्रिय डाक-टिकटों के लिए "प्रौद्योगिकी दिवस", "रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन" और "राष्ट्रीय रक्षा अकादमी" पर जारी किए गए डाक-टिकटों का चयन किया गया।

3.27 संदर्भित अवधि के दौरान, निम्नलिखित सर्किल/राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित की गई :-

7 दिसम्बर से 12 दिसम्बर, 2000 तक नेताजी इंडोर

क्र.सं.	प्रदर्शनी का नाम	स्थान	अवधि
1.	तानापेक्स 2000	कोयम्बटूर	02/08/2000 से 05/08/2000
2.	नागापेक्स 2000	कोहिमा	23/10/2000 से 25/10/2000
3.	हारपेक्स 2001	अम्बाला कैन्ट	23/02/2001 से 25/02/2001

स्टेडियम में विभाग द्वारा 14वीं एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फिलैटलिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

to PSDs/RFDs. In order to ensure effective inventory control computerisation of 46 Postal Store Depots has also been undertaken by the Department.

Philately

3.20 Philately continued to remain an important activity of the Department. Many significant events were commemorated by issue of special stamps. During the period from 01.04.2000 to 31-3-2001, sixty one stamps were issued.

3.21 In accordance with the decision taken by the Philatelic Advisory Committee, personality based stamps are being brought out in thematic sets, to ensure philatelic relevance of these stamps. The Department released sets of stamps titled-“Great Leaders: Social and Political”(set of four stamps) on 15th August 2000, “Personalities: Historical” on 31st December,2000 and “Great Political Leaders” on 27th January,2001.

3.22 The India Post observed 50 years of the inland letter cards this year by issuing inland letter card carrying the photograph of Gandhiji on 2nd October,2000. Items of postal stationery i.e. postcard, envelope, registered envelope, inland letter card and aerogram carrying advertisements, public awareness quotations, messages etc. in English, Hindi as well as regional languages were also issued.

3.23 During the period, the Department released beautiful stamps on art & culture, flora & fauna, heritage etc. such as

- Set of four stamps on Natural Heritage of Manipur & Tripura
- Set of four stamps on Indigenous Breeds of cattle,

100 years of Railways in Doon Valley

- Set of four stamps on Sydney Olympics
- Set of three stamps on Space Theme
- Set of four stamps on Madhubani-Mithila Paintings
- Set of six stamps on Gems & Jewellery and
- Set of four stamps on International Fleet review

3.24 Sale of Philatelic items is carried out all over the country through 55 philatelic bureaux, 212 philatelic counters as well as all the Head Post Offices of the country.

3.25 A nation-wide competition for the design of stamp on theme “Dialogue Among Civilisation” was held in August, 2000. 124 entries were received from all over the country. Design prepared by Shri Subhash E. Pawar of C.B.D. Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra was selected by the Committee of Judges for the National Prize Winner entry and sent to UPU for participation in the International Competition.

3.26 A Stamp Popularity Poll was organised by the Department of Posts during 10-25 October, 2000 for selecting the most popular stamp issued by the Department in the year 1999. About 95,396 entries were received from all over the country. Stamps on Technology Day, Defence Research and Development Organisation and National Defence Academy were selected as the three most popular stamps for the year 1999.

3.27 The following Circle/State Level Exhibitions have been held during the reference period:

S.No	Name of the Exhibition	Place	Duration
1.	TANAPEX 2000	Coimbatore	02/08/2000 to 05/08/2000
2.	NAGAPEX 2000	Kohima	23/10/2000 to 25/10/2000
3	HARPEX 2001	Ambala Cantt.	23/02/2001 to 25/02/2001

14th Asian International Philatelic Exhibition was organised by the Department at Netaji Indoor Stadium,

Calcutta from 7th Dec to 12th December, 2000.

अध्याय-4

व्यवसाय विकास कार्यकलाप

4.1 विभाग के मूल्यवर्धित प्रीमियम उत्पादों के डिजाइन तैयार करने, विपणन को विकसित करने और मानीटरिंग करने के लिए व्यवसाय विकास निदेशालय की 1996 में स्थापना की गई। व्यवसाय विकास निदेशालय का प्रमुख उत्तरदायित्व मूल्यवर्धित सेवाओं के संकेंद्रित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- मौजूदा मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं का विस्तार तथा संवर्धन;
- नए मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं का अभिकल्पन एवं प्रवर्तन;
- इनकी रिटेलिंग और नेटवर्किंग के लिए प्रक्रियाओं, विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करना;
- बाजार अध्ययन, बाजार परीक्षण तथा उत्पाद परिष्कार;
- बाजार-नीतियों, गठजोड़ों और सहयोग का विकास;
- कार्मिक-प्रशिक्षण;
- मूल्यवर्धित उत्पादों तथा सेवाओं की मानीटरिंग तथा पुनरीक्षा;
- विभाग के निष्क्रिय संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करना।

4.2 व्यवसाय विकास निदेशालय निम्नलिखित उत्पादों और

सेवाओं का प्रबंध एवं विपणन करता है :

- (क) स्पीड पोस्ट
- (ख) बिजनेस पोस्ट
- (ग) मीडिया पोस्ट
- (घ) बधाई डाक
- (ङ) एक्सप्रेस डाक
- (च) रीटेल डाक
- (छ) उपग्रह डाक
- (ज) स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा
- (झ) डाटा पोस्ट

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा और डाटा पोस्ट हाल ही में प्रारंभ की गई है।

कारोबार में वृद्धि

4.3 व्यवसाय विकास दल द्वारा उठाए गए नए कदमों के परिणामस्वरूप 2000-2001 में राजस्व बढ़कर 2819.0 मिलियन रुपये हो गया, जबकि 1999-2000 में यह 2224.4 मिलियन रुपये था। प्रत्येक उत्पाद के संबंध में राजस्व में हुई बढ़ोतरी तालिका-4 में दर्शाई गई है।

तालिका-4 व्यवसाय विकास कार्यकलापों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि (रुपये मिलियन में)			
उत्पाद	1999-2000 में राजस्व	2000-2001 में राजस्व	% वृद्धि
स्पीड पोस्ट	1261.7	1514.4	20.03%
बिजनेस पोस्ट	849.2	1116.6	31.49%
मीडिया पोस्ट	57.8	60.5	4.67%
एक्सप्रेस पोस्ट	35.6	105.2	195.51%
उपग्रह डाक	0.6	0.4	(-)33.33%
रीटेल पोस्ट	6.9	12.0	73.91%
बधाई डाक	-	7.2	-
अन्य कारोबारी सेवाएं	12.6	2.7	(-)78.57%
कुल	2224.4	2819.0	26.73%

Chapter 4

BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES

4.1 Business Development Directorate was set up in 1996 to design, develop market and monitor value-added premium products of the Department. The main responsibility of the Business Development Directorate is to ensure focused management of value added services and it includes the following:

- Expansion and promotion of the existing value-added products and services
- Designing & Launching of new value-added products and services
- Set up procedures, regulations and guidelines for their retailing and networking
- Market study, market testing and product improvement
- Market strategies, alliances and cooperation
- Training for personnel
- Monitoring and reviewing of growth of value-added products and services
- Commercial utilization of idle resources of the Department

4.2 The Business Development Directorate manages and markets the following products and services:

- (a) Speed Post
- (b) Business Post
- (c) Media Post
- (d) Greeting Post
- (e) Express Post
- (f) Retail Post
- (g) Satellite Post
- (h) Speed Post Passport Service
- (i) Data Post

Speed Post Passport Service & Data Post have been introduced recently.

BUSINESS GROWTH

4.3 As the result of new initiatives taken by the Business Development Group, the revenue increased to Rs. 2819.0 million in 2000-2001, as compared to Rs. 2224.4 million in 1999-2000. The revenue growth in respect of each product is given in the Table-4:

TABLE-4 PRODUCT-WISE REVENUE GROWTH OF BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES (Rs. in million)			
Product	Revenue in 1999-2000	Revenue in 2000-2001	% of increase
Speed Post	1261.7	1514.4	20.03%
Business Post	849.2	1116.6	31.49%
Media Post	57.8	60.5	4.67%
Express Post	35.6	105.2	195.51%
Satellite Post	0.6	0.4	(-)33.33%
Retail Post	6.9	12.0	73.91%
Greeting Post	-	7.2	-
Other Business Services	12.6	2.7	(-)78.57%
Total	2224.4	2819.0	26.73%

स्पीड पोस्ट

4.4 त्वरित एवं समयबद्ध वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए सात मेट्रो नगरों को जोड़ते हुए 1986 में स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू की गई थीं। आज स्पीड पोस्ट के वृहत नेटवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत भारत में 120 प्रमुख शहरों/नगरों तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में 97 देश जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 700 से अधिक शहर और जिला मुख्यालय जुड़े हुए हैं जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए स्पीड पोस्ट वस्तुएं बुक की जा सकती हैं।

4.5 स्पीड पोस्ट पूरे देश तथा समूची दुनिया में पत्रों, दस्तावेजों तथा 35 कि.ग्रा. तक के पार्सलों की समयनिष्ठ एवं सुनिश्चित वितरण सेवा उपलब्ध कराता है। केन्द्रों को जोड़ने के लिए उपलब्ध तीव्रतम परिवहन के साधन को ध्यान में रखते हुए वितरण मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा के कारोबार का प्रबंध व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ किया जाता है।

4.6 स्पीड पोस्ट के अंतर्गत, स्पीड पोस्ट घरेलू सेवाएं, स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, स्पीड पोस्ट मनीआर्डर और स्पीड पोस्ट उपहार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्पीड पोस्ट का राजस्व 1999-00 में 1261.7 मिलियन रुपये से बढ़कर 2000-2001 में 1514.4 मिलियन रुपये हो गया। कारोबार में महत्वपूर्ण ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं का पता

लगाया जाता है और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ही सेवा ग्राहकोन्मुख बनाई जाती है। बड़ी मात्रा में व्यवसाय देने वाले कारपोरेट ग्राहकों को अतिविशिष्ट ग्राहकों की हैसियत प्रदान की जाती है। इससे कुशल वितरण और पूछताछ का शीघ्रता से उत्तर देने के लिए मानीटरिंग करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।

बिजनेस पोस्ट

4.7 बिजनेस पोस्ट भारी मात्रा में डाक भेजने वालों के लिए उनकी सुविधा और आवश्यकता के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराकर सम्पूर्ण कारोबारी समाधान प्रदान करता है। यह संग्रहण, सन्निवेशन, पतालेखन, सीलिंग, फ्रैंकिंग आदि के रूप में डाक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी पारंपरिक सेवाओं का मूल्यवर्धन करता है। कारपोरेट ग्राहक बिजनेस पोस्ट सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जिसकी महानगरों और शहरों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

4.8 एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में भूतल परिवहन के माध्यम से 35 कि.ग्रा. तक के पार्सलों की बुकिंग एवं इनकी वितरण सुविधा प्रदान की जाती है। इस उत्पाद की वाणिज्यिक प्रयोजन से मार्च, 1999 में पुनः शुरूआत की गई। कारपोरेट ग्राहकों को सविदात्मक आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक्सप्रेस पोस्ट से कारोबार में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान 105.2 मिलियन रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

Speed Post

4.4 Speed Post services were introduced in 1986, linking seven metro cities, with a view to providing fast and time-bound delivery services. As on date, Speed Post has a large network linking 120 major cities/towns in India in the national network and 97 countries in the international network. In addition more than 700 towns and district headquarters are linked in the State speed post network, from where speed post articles can be booked for national and international destinations.

4.5 Speed Post offers time-specific and assured delivery of letters, documents and parcels up to 35 kg. across the country and around the world. Delivery norms are fixed taking into account the fastest transport available to link the stations. The business of speed post service is managed with commercial approach.

4.6 Under the brand Speed Post, are offered Speed Post Domestic services, Speed Post International services, Speed Post Money Orders and Speed Post Gift service. The revenue from Speed Post has considerably increased from Rs.1261.7 million in 1999-00 to Rs. 1514.4 million in 2000-2001. To retain

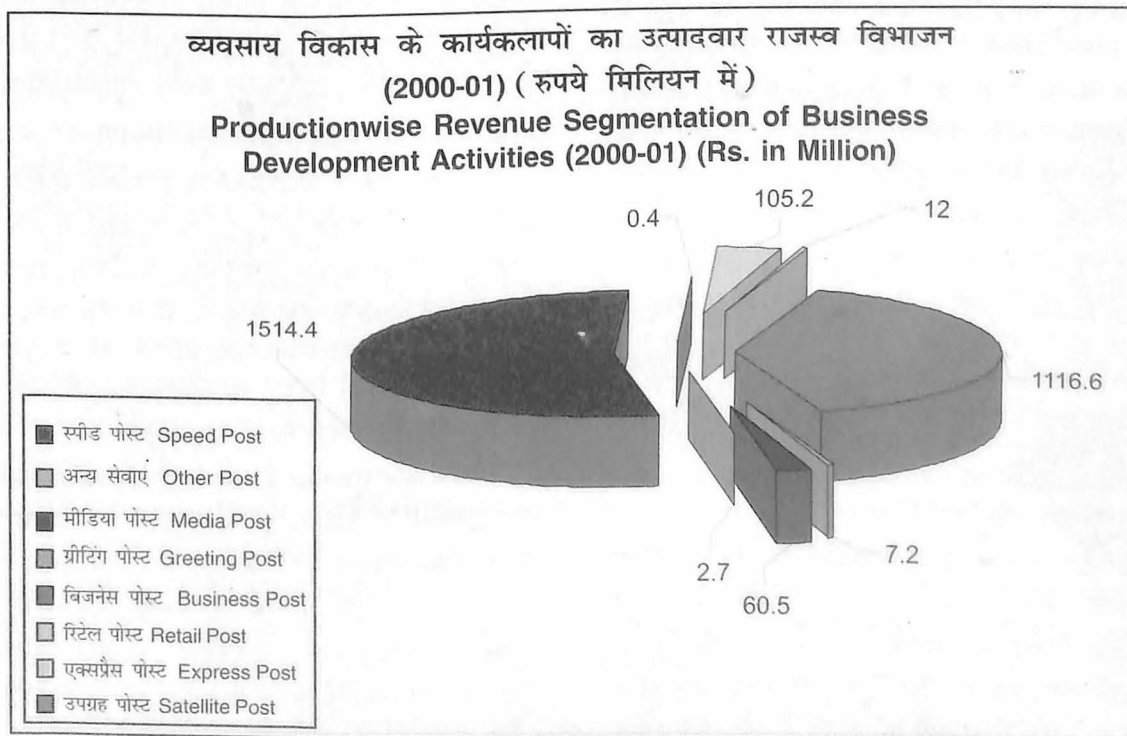
important customers in the business their specific needs are ascertained and the service customized according to their requirements. Corporate customers giving high volume of business are given the status of Very Important Customers. This enables focussed monitoring for efficient delivery and quick reply to their enquiries.

Business Post

4.7 Business Post offers total business solutions for the bulk mailers by providing tailor made services. It provides value addition to all traditional services offered by the Post in the form of collection, inserting, addressing, sealing, franking etc. Corporate customers have been using Business Post services, which has been growing in the metro cities and towns.

Express Parcel Post

4.8 Express Parcel Post provides booking and delivery of parcels up to 35 Kgs. through Surface transportation. The product was re-launched in March 1999 with a commercial focus. The services are provided to corporate customers on contractual basis. The business from Express Post has been growing. The revenue during the year 2000-01 was to the tune of Rs.105.2 million.



मीडिया पोस्ट

4.9 मीडिया पोस्ट कारपोरेट ग्राहकों/सरकारी संगठनों और अन्य बड़े निजी संस्थानों को डाक स्टेशनरी, डाक वाहनों, पत्र पेटियों आदि पर उनके उत्पादों/सेवाओं को विज्ञापित करने के अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2000-01 के दौरान इससे 60.5 मिलियन रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

रीटेल पोस्ट

4.10 समूचे देश में 1,50,000 से अधिक डाकघरों के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से भारतीय डाक अब टेलीफोन/विद्युत/मोबाइल फोन प्रदाताओं आदि जैसे सेवा उद्योगों के उपभोक्ता बिलों को वसूलने का कार्य करता है।

व्यवसाय विकास दल की नई पहल

व्यावसायिक दृष्टिकोण

4.11 व्यवसाय विकास दल 01 अप्रैल, 1999 से लेखाकरण प्रयोजनों के लिए एक स्वतंत्र लाभ केन्द्र है। यह व्यवसाय विकास दल से वसूले गए राजस्व और सेवाओं को चलाने में निहित लागत के बारे में जानने में मदद करता है।

ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली उन्नयन परियोजना

4.12 स्पीड पोस्ट की भारत में आठ शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणाली है। वर्तमान ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है और इसमें बुकिंग, थैला बनाने, पारेषण, वितरण एवं ग्राहक एकाउंट प्रबंधन माइयूएल का समावेश किया जा रहा है। जब एक बार इसे कार्यान्वित कर दिया जाएगा तो ग्राहक ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रम का इस्तेमाल करके इंटरनेट के माध्यम से अपने-अपने पारेषण का पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे। यह सभी स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पोस्ट पारेषणों के लिए उपलब्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट वस्तुओं का पता लगाने के लिए आईपीएस 96 में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में संस्थापित किया गया है और शीघ्र ही इसका विस्तार कोलकाता तक कर दिया जाएगा।

स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार

4.13 आज स्पीड पोस्ट का घरेलू नेटवर्क के अंतर्गत 120 केन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क है और 97 देश अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में आते हैं। बुकिंग नेटवर्क में विस्तार करने के लिए राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संकल्पना की गई। 700 राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं जो अधिकांश जिला मुख्यालयों को जोड़ते हैं और राज्य स्पीड

पोस्ट केन्द्र राष्ट्रीय केन्द्रों और सभी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय गन्तव्य केन्द्रों के लिए स्पीड पोस्ट वस्तुएं बुक कर सकते हैं।

वितरण का यांत्रिकीकरण

4.14 वाहनों के माध्यम से स्पीड पोस्ट वस्तुओं के वितरण में तेजी लाने और प्रचालनात्मक कार्यकुशलता को बढ़ाने में सुधार हुआ है। इसके अलावा, स्पीड पोस्ट की सकारात्मक छवि बनी है। तीव्रता से डाक वितरण करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलूर सहित कई शहरों में डाकियों को मोपेड उपलब्ध कराए गए हैं।

स्पीड पोस्ट वितरण का पुनर्गठन

4.15 तीव्र और दक्ष वितरण करने के लिए स्पीड पोस्ट वितरण को नोडल डाक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत स्पीड पोस्ट का वितरण एक नोडल डिलीवरी कार्यालय से सम्बद्ध समर्पित स्पीड कर्मियों के माध्यम से होता है। शनिवार सहित प्रत्येक कार्य-दिवस को दो बार डाक वितरण की जाती है।

स्पीड पोस्ट केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

4.16 उत्पादकता में वृद्धि लाने और कुशल ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी स्पीड पोस्ट सेवा केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के एक भाग के तौर पर राष्ट्रीय नेटवर्क के अधिकांश स्पीड पोस्ट केन्द्रों में कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोडेम तथा फैक्स मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

स्पीड पोस्ट का आउटसोर्सिंग एक्जीक्यूटिव

4.17 स्पीड पोस्ट में कार्यकुशल एवं कारगर संग्रहण प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कई स्पीड पोस्ट केन्द्रों में आउटसोर्सिंग से संग्रहण शुरू किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत, कारपोरेट और खुदरा ग्राहकों से स्पीड पोस्ट वस्तुओं का संग्रहण करने हेतु एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। ग्राहकों से पारेषणों को लेने के उपरान्त एजेंट इन्हें बुकिंग के लिए स्पीड पोस्ट केन्द्र पर लाते हैं।

सेवा की गुणवत्ता

4.18 सेवा की गुणवत्ता की मानीटरिंग, विशेषरूप से स्पीड पोस्ट पारेषणों के वितरण को सभी स्तरों पर बढ़ाया गया है। स्वतंत्र बाजार सर्वेक्षण कंपनियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 97% स्पीड पोस्ट वस्तुएं समय पर वितरित की गईं। इसके अलावा अभी सभी स्पीड पोस्ट केन्द्रों में डाक वितरण के निष्पादन की दैनिक मानीटरिंग की जाती है।

Media Post

4.9 Media Post provides opportunities to corporate customers/Govt. organisations and other large private institutions to have their products/services advertised on postal stationery, postal vans, letter boxes etc. The revenue during the year 2000-01 was to the tune of Rs. 60.5 million.

Retail Post

4.10 Through its vast network of more than 150,000 post offices across the country, India Post offers collection of consumers bills for service industries like telephone/electricity/mobile phone providers etc.

New Initiatives of Business Development Group Business Approach

4.11 The Business Development Group has been an independent profit center for accounting purposes from 1st April 1999. This helps it to know the revenue realized from the Business Development Group and the cost incurred for managing the services.

Track and Trace System upgradation Project

4.12 Speed Post has electronic tracking system in eight cities in India- Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. The existing TATS system is being upgraded, incorporating booking, bagging, and transmission, delivery and customer accounts management modules. Once this is implemented, the customers will be able to track their consignments through Internet, using a customer friendly program. This will be available for all the speed post and Express Post consignments. For tracing international speed post articles, IPS 96 has been installed at Mumbai, Chennai and Delhi and soon, this will be extended to Calcutta.

Expansion of Speed Post Network

4.13 Today, Speed Post has a vast network of 120 stations in the national network and 97 countries are covered in the international network. The concept of State Speed Post Centres was introduced to expand the booking network. There are 700 State Speed Post Centres linking most of the district headquarter and the State Speed Post Centres can book speed post articles

for the national centres and for all identified international destinations.

Mechanization of Delivery

4.14 Delivery of Speed Post articles through vehicles facilitates quick delivery and operational efficiency. Further, it builds a positive image about Speed Post. For providing faster delivery, mopeds to the postmen have been provided at many stations including Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai and Bangalore.

Speed Post Delivery Restructure

4.15 Speed Post delivery has been restructured under the nodal delivery system for rendering fast and efficient delivery. Under this system, Speed Post is delivered through a set of dedicated speed men attached to a nodal delivery office. There are two deliveries effected on every working day, including Saturdays.

Computerisation of Speed Post Centres

4.16 For increasing productivity and for providing efficient customer service, it has been decided to computerize all Speed Post Centres. As a part of this venture, most of the Speed Post Centres in the national network have been provided with computers, scanners, printers, modems and fax machines.

Outsourcing Collection of Speed Post

4.17 In order to provide efficient and effective collection system in Speed Post, outsourcing was introduced in many Speed Post Centres. Under the scheme, agents are appointed to collect speed post articles from corporate and retail customers. After collection of the consignments from the customers, agents bring them to Speed Post for booking.

Quality of Service

4.18 Monitoring of the quality of service specially delivery of speed post consignments has been intensified at all levels. Surveys conducted by independent market survey companies reveal that 97% Speed Post articles were delivered on time in Mumbai, Delhi, Calcutta and Chennai. Apart from this, at present daily monitoring of the delivery performance in all Speed Post Centres is in position.

विपणन पर बल

4.19 स्पीड पोस्ट और अन्य प्रीमियम सेवाओं के संवर्धन के लिए एक विपणन संरचना तैयार की गई है। प्रमुख केन्द्रों में विपणन कार्यपालकों को नए ग्राहकों की खोज करने तथा मौजूदा ग्राहकों को कुशल सेवा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। स्पीड पोस्ट की तुलना में कुरियरों का निष्पादन, स्पीड पोस्ट के लिए बाजार में संभावनाएं तथा स्पीड पोस्ट के वितरण-निष्पादन पर समय-समय पर बाजार सर्वेक्षण किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए कई स्पीड पोस्ट कर्मियों को प्रचालनों, ग्राहक सेवा और विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है।

बिजनेस पोस्ट केन्द्रों का स्वचलीकरण

4.20 प्री-मेलिंग प्रक्रिया का स्वचलीकरण करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्थित बिजनेस पोस्ट केन्द्रों में पायलट परियोजना आधार पर डेस्क टॉप मेलिंग तथा सन्निवेशन प्रणालियां मुहैया कराई गई हैं।

नई सेवाएं

बधाई डाक

4.21 बधाई डाक सितम्बर, 2000 में शुरू की गई थी। इस नए

उत्पाद से अधिक राजस्व के प्राप्त होने की आशा है। यह उत्पाद भारतीय डाक की महत्वपूर्ण सक्षमता के सहयोग से अभिकल्पित किया गया है। यह बधाई कार्ड एक लिफाफे के साथ बेचा जाता है जिस पर एक डाक-टिकट मुद्रित होता है। यह टिकट कार्ड के ऊपर डिजाइन की एक लघु प्रतिकृति है। यह कार्ड डाक शुल्क सहित 13/- रुपये और 16/- रुपये के हैं। इनकी बिक्री वितरकों और खुदरा विक्रेताओं और चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से होती है।

डाटा पोस्ट

4.22 डाटा पोस्ट भारतीय डाक द्वारा की गई नई पहल का एक भाग है जिसने विपणन समुदाय के बीच काफी रुचि उत्पन्न की है। डाक विभाग द्वारा लिंग, वेतन स्तरों, मीडिया प्रकृति, उत्पाद वरीयताओं आदि पर सूचना सहित परिवार पर संकलित एवं तैयार किया गया यह एक डाटा आधारित उत्पाद है। यह व्यापारिक घरानों को इसकी कीमत का भुगतान करने पर प्रत्यक्ष विपणन में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होगा।

इस उत्पाद पर बेंगलूर और हैदराबाद में प्रयोग पूर्णरूपेण सफल रहा है।



Thrust on Marketing

4.19. A marketing infrastructure has been developed to promote Speed Post and other premium services. In major centres, marketing executives have been entrusted with the task of seeking new customers and to service the existing customers efficiently. Market surveys are conducted periodically on the performance of speed post vis-à-vis couriers, market opportunities for speed post and delivery performance of speed post. Realizing the need for human resource development, many Speed Post Staff have been trained in the area of operations, customer service and marketing.

Automation of Business Post Centres

4.20 Business Post Centres in Delhi Mumbai, Chennai and Calcutta have been provided with Desk top mailing and inserting systems to automate the pre-mailing processes on a pilot project basis.

New Services

Greeting Post

4.21 Greeting Post was introduced in September

2000. This new product is expected to generate much revenue. The product has been designed to synergies with the core competence of India Post. The Greeting Card is sold with an envelope upon which is printed a postage stamp. This stamp is a miniature replica of the design upon the card. The cards are priced Rs. 13/- and Rs. 16/- including postage. They are sold through distributors and retailers and at selected POs.

Data Post

4.22 DATA POST is a part of the new initiatives taken by India Post and has generated considerable interest among the marketing community. The product consists of a database compiled and maintained by DOP on households with information on gender, salary levels, media habits, product preferences etc. This will be available to business houses at a price for making use in direct marketing. The pilot on the product has been successfully completed in Bangalore and Hyderabad.

अध्याय-5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

5.1 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 22वीं कांग्रेस का आयोजन 1999 में बीजिंग (चीन जनवादी गणराज्य) में आयोजित किया गया। भारत को प्रशासन परिषद और डाक प्रचालन परिषद के लिए पुनः चुना गया था। प्रशासन परिषद एक विनियामक संस्था है जो कि यू.पी.यू. के कार्यकरण संबंधी नियम व विनियम तैयार करती है। डाक प्रचालन परिषद पर डाक सेवा संबंधी प्रचालनात्मक, वाणिज्यिक, तकनीकी तथा आर्थिक मामलों का दायित्व है। भारत को यू.पी.यू. के भावी विकास पर उच्च स्तरीय ग्रुप के सदस्य के बतौर 24 देशों के ग्रुप में भी नामित किया गया।

5.2 यू.पी.यू. के डाक प्रचालन परिषद (पीओसी) का वार्षिक सम्मेलन 01 से 11 मई, 2000 को बर्न (स्विटजरलैंड) में आयोजित किया गया। बैठक में भारत ने परिषद की तीन समितियों, सेवा निधि की तदर्थ गुणवत्ता (क्यू.एस.एफ.) समिति, टर्मिनल ड्यूज एक्शन ग्रुप (टी.डी.ए.जी.) तथा तकनीकी सहयोग कार्य दल (टी.सी.ए.जी.) के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। डाक प्रचालन परिषद 2000 ने पत्र-डाक विनियम, पार्सल डाक विनियम तथा डाक भुगतान विनियमों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया। डाक प्रचालन परिषद द्वारा अपनाए गए नए प्रस्ताव पहली जनवरी, 2001 से लागू हो गए हैं। भारतीय डाक ने क्यू.एस.एफ. की विषय निर्वाचन समिति की 13 से 16 फरवरी, 2001 तक आयोजित बैठक में और क्यू.एस.एफ. की 26 फरवरी से 2 मार्च, 2001 तक कार्यान्वयन और उगाही पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।

5.3 प्रशासन परिषद का वार्षिक सम्मेलन 9 से 20 अक्टूबर, 2000 को बर्न (स्विटजरलैंड) में आयोजित किया गया। भारत "सामान्य नीतिगत तथा सैद्धान्तिक मामलों" पर प्रशासन परिषद की समिति-1 का अध्यक्ष है। एच.एल.जी. द्वारा यू.पी.यू. के पुनर्गठन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समिति अपना कार्य प्रारंभ करेगी। प्रशासन परिषद की वित्त समिति (समिति-2) तथा तकनीकी सहयोग समिति (समिति-3) के कार्यों में भारत ने अहम भूमिका निभाई। समिति-2 की सिफारिशों पर आधारित, प्रशासन परिषद ने यू.पी.यू. के वित्तीय नियमों में किए संशोधनों तथा 2001-2002 के दो वर्ष की अवधि के नियमित बजट का अनुमोदन किया। समिति-3 ने विशेष कार्यक्रम की सबसे कम

विकसित देशों (एलडीसी) के पक्ष में कार्यान्वित करने का अनुमोदन किया। सार्वभौमिक सेवा के कार्य क्षेत्र तथा परिधि में विस्तार करने के मद्देनजर तथा संरचनात्मक सुधार एवं डाक विकास की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए इनसे एल.डी.सी. के लिए वृहत स्तर पर अन्तर-क्षेत्रीय परियोजना बनाने की अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो की योजना का समर्थन किया।

5.4 भारत ने यू.पी.यू. के उच्चस्तरीय ग्रुप की तीसरी, चौथी, पांचवीं तथा छठी बैठक जो क्रमशः मई, जुलाई, अक्टूबर, 2000 तथा फरवरी, 2001 में आयोजित की गई थी, में भी हिस्सा लिया। उच्चस्तरीय ग्रुप, वरिष्ठ डाक अधिकारियों का ऐसा मंच है जो कि यू.पी.यू. के भावी लक्ष्य तथा संरचना पर पुनः विचार करता है। उच्चस्तरीय ग्रुप ने यू.पी.यू. के नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्तमान में यह यू.पी.यू. नियमों में नए सुधार लाने पर कार्य कर रहा है। आगे यू.पी.यू. के पुनर्गठन के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गैर-सरकारी पणधारियों की अंतर-सरकारी संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में भी भागीदारी होगी। भारत ने बर्न (स्विटजरलैंड) में 5 से 6 अक्टूबर, 2000 में आयोजित ई.एम.एस. को-आपरेटिव की आम सभा की बैठक में भी भाग लिया। बैठक में विश्वभर में ई.एम.एस. सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।

5.5 एशियाई प्रशान्त डाक यूनियन (ए.पी.पी.यू.) जो एशियाई तथा प्रशान्तीय क्षेत्रों के 28 देशों की एक सीमित यूनियन है, के कार्यों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने एशियाई प्रशान्त डाक प्रशिक्षण केन्द्र के शासी निकाय की 30वीं बैठक तथा 12 से 18 सितम्बर, 2000 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तेहरान में आयोजित एशियाई प्रशान्त डाक यूनियन के आठवें कांग्रेस में भी भाग लिया। ए.पी.पी.यू. कांग्रेस, ए.पी.पी.यू. की सर्वोच्च संस्था है तथा प्रत्येक पांच वर्ष में इसकी बैठक का आयोजन होता है। इस कांग्रेस के दौरान ए.पी.पी.यू. के केन्द्रीय कार्यालय को मनीला से बदलकर बैंकाक में स्थापित करने तथा ए.पी.पी.यू. के केन्द्रीय कार्यालय तथा ए.पी.पी.टी.सी. दोनों के लिए सम्मिलित रूप से एक निदेशक के पद का निर्णय लिया गया। क्षेत्र में सदस्यीय देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। भारतीय डाक ने 22 से 23-02-2001 को



Chapter 5

INTERNATIONAL RELATIONS

5.1 At the 22nd Congress of the Universal Postal Union held at Beijing (People's Republic of China) in 1999, India was re-elected to the Council of Administration and to the Postal Operations Council. The Council of Administration is a regulatory body that frames rules and regulations regarding the functioning of UPU. The Postal Operations Council is responsible for operational, commercial, technical and economic matters concerning the postal service. India was also nominated, as one of the 24 countries, as a member of the High Level Group on the future development of UPU.

5.2 The Annual Session of the Postal Operations Council (POC) of the UPU was held at Berne (Switzerland) from 1st -11th May, 2000. During this meeting, India played an active role in the work of the three committees of the Council, Ad-hoc Quality of Service Fund (QSF) committee, the Terminal Dues Action Group (TDAG) and the Technical Cooperation Action Group (TCAG). The POC 2000 examined the proposals relating to amendment of the letter post regulation, parcel post regulation and postal payment regulations. The new provisions adopted by the POC came into force on 1st January 2001. India Post attended the Steering Committee meeting of QSF from 13th to 16th Feb, 2001 and a seminar on the implementation and realization of the QSF held from 26th Feb to 2nd March, 2001.

5.3 The Annual Session of the Council of Administration (CA) was held at Berne (Switzerland) from 9-20 October, 2000. India is the Chairman of Committee-1 of the CA on "General Matters of Policy and Principle". This Committee will start its work after the HLG submits its report on restructuring of UPU. India played a significant role in the work of the Finance Committee (Committee-2) and the Technical Cooperation Committee (Committee-3) of the Council of Administration. Based on the recommendations of

Committee-2, CA approved the amendments to the UPU Financial Regulations and the regular budget for the two year period 2001-2002. Committee-3 approved the implementation of special programme in favour of the least developed countries. It supported the International Bureau's Plan to formulate a large scale inter-regional project for LDCs aimed at raising the scope and degree of universal service and implementing the process of structural reform and postal development.

5.4 India participated in the 3rd, 4th, 5th & 6th meetings of the High Level Group of the UPU held in May, July and October, 2000 and February 2001 respectively. The High Level Group, is a forum of senior postal officers, with a mandate to consider the future mission and structure of the UPU. The HLG has so far decided on a new mission statement for UPU. It is currently working on the recasting of UPU Acts. Further efforts are on to work out a new structure for UPU whereby the non-governmental stakeholders will also have a say in the working of the inter-governmental body. India also participated in the meeting of the EMS Co-operative General Assembly held at Berne (Switzerland) from 5-6 October, 2000. During the meeting various measures were discussed to improve the quality of EMS Service worldwide.

5.5 India plays a meaningful role in the affairs of the Asian Pacific Postal Union (APPU), a restricted Union comprising 28 countries of the Asian and the Pacific Region. India participated in the 30th meeting of the Governing Board of the Asian Pacific Postal Training Centre and the 8th Congress of the Asian Pacific Postal Union (APPU), held at Tehran, Islamic Republic of Iran from 12-18 September, 2000. The APPU Congress is the supreme organ of the APPU and its meeting is held every five year. During this Congress it was decided to shift the APPU Central Office from Manila to Bangkok and have a common Director for the APPU Central Office and the APPTC. Meaningful discussions were

हांगकांग, चीन में आयोजित एपीपी सहयोग प्रबंध बोर्ड की बैठक में भी भाग लिया।

5.6 भारत ने दिनांक 5 से 6 अक्टूबर, 2000 को मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित विश्व फिलैटली विकास संघ (डब्ल्यू.ए.डी.पी.) के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर श्री बी.एन.सोम, सचिव (डाक) को, डब्ल्यू.ए.डी.पी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। 2 से 5 अक्टूबर, 2000 को जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित पोस्ट एक्सपो- 2000 में भारत ने भाग लिया। 26 से 29 जून, 2000 को बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित विश्व बचत बैंक संस्थान की 7वीं आम सभा में भी भारत ने भाग लिया।

5.7 भारत गणराज्य के संचार मंत्रालय तथा रूसी फेडरेशन के संचार तथा सूचना मंत्रालय के बीच 3 अक्टूबर, 2000 को डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहभागिता के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत गणराज्य की ओर से माननीय संचार मंत्री श्री राम विलास पासवान तथा रूसी फेडरेशन की ओर से संचार व सूचना मंत्री श्री लियनिद डी. रीमैन द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार पर रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के 2 अक्टूबर, 2000 के राजकीय दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

5.8 संयुक्त राष्ट्र के विकास परियोजना के परियोजना समन्वयकर्ता श्री मार्क स्केर ने दिनांक 19 से 26 मई, 2000 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने कथित विषय पर भारत डाक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। यू.पी.यू. अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो के सहायक सलाहकार श्री एम. थिरेरी ब्यूसेन्ट ने दिनांक 2 से 10 अगस्त, 2000 को भारत का दौरा किया तथा भारत डाक के लागत-लेखा माडल तथा अन्य डाक प्रशासनों में उसकी अनुप्रयोज्यता पर विचार-विमर्श किया। न्यूजीलैंड पोस्ट से दिनांक 15 से 18 अगस्त, 2000 को एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा व्यवसाय विकास कार्यनीति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यू.पी.यू. द्वारा बर्न में 01 से 02-03-2001 तक डाक बचत विकास फोरम आयोजित की गई जिसमें भारतीय डाक ने भाग लिया।

5.9 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 30.10.2000 से 10.11.2000 तक पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद में कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत द्वारा बंगलादेश, सूडान, कोमोरोस, जाम्बिया तथा

केन्या के प्रतिभागियों को छह फेलोशिप प्रदान की गई।

5.10 16 से 18 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में डाक और सम्बद्ध मामलों पर भारत उज्बेक संयुक्त समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। जनवरी, 1994 में तत्कालीन उज्बेक राष्ट्रपति के राजकीय दौरे के दौरान डाक और सम्बद्ध मामलों पर भारत गणराज्य और उज्बेक की सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षी करार के क्रम में यह बैठक आयोजित की गई थी। दोनों देशों के बीच फिलैटली, डाक के तीव्र पारेषण, भारत डाक में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, उज्बेक डाक के काउंटर और बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए विचार-विमर्श किए गए और बाद में दोनों ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं के अध्ययन पर सहमत हो गए।

5.11 श्री अता-उर-रहमान, महानिदेशक, बंगलादेश डाकघर ने पारस्परिक महत्व के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 21 से 27 जनवरी, 2001 तक भारत का दौरा किया।

5.12 मारीशस गणराज्य के सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार मंत्री महामहिम श्री दीलचन्द जीहा ने 14-3-2001 को भारत आए डाक तथा दूरसंचार क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत से मेघदूत 98 साफ्टवेयर प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की।

5.13 चालू वर्ष दौरान डाक विभाग ने मुम्बई में एपीएसओ (विदेश) में प्रणाली संस्थापित करके जावक हवाई डाक की मदों की प्रोसेसिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली के प्रयोग की सुविधा प्रदान की। उसके लिए हार्डवेयर की आपूर्ति यूपीयू द्वारा की गई थी।

5.14 भारत ने इस्लामाबाद में जनवरी 2001 में परिवहन तथा संचार पर आयोजित पहली सार्क तकनीकी समिति की बैठक में भाग लिया। समिति ने भारत में डाकघर के आधुनिकीकरण/कंप्यूटरीकरण पर 5 दिवसीय कार्यशाला के लिए निधि प्रदान करने का निदेश दिया। भारत ने 17वीं सार्क पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की जिम्मेदारी भी ली।

5.15 जनवरी 2001 के दौरान वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल (डब्ल्यू यू एफ एस आई) संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से डाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा की शुरुआत करने के लिए करार तथा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

also held on promoting technical cooperation between the member countries in the region. India Post also attended the meeting of APP Cooperative Management Board held at Hongkong, China from 22-23.02.2001.

5.6 India attended the Annual Session of the World Association for the Development of Philately(WADP) held at Madrid(Spain) from 5-6 October, 2000. Shri B.N.Som, Secretary (Posts) was elected the President of the WADP on this occasion. India participated at the POST EXPO 2000 held at Geneva (Switzerland) from 2-5 October, 2000. India participated in the 7th General Assembly of the World Savings Bank Institute held at Berlin(Germany) from 26-29 June, 2000.

5.7 An Agreement on Cooperation in the field of Postal Services was signed between the Ministry of Communications of the Republic of India and the Ministry of Communications and Informatization of the Russian Federation on 3rd October, 2000. The agreement was signed by Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble Minister of Communications of the Republic of India and Mr. Leonid D. Reiman, Minister for Communications and Informatization of the Russian Federation. This agreement was signed during the state visit of the Russian President H.E. Mr. Vladimir Putin to India beginning 2nd October, 2000.

5.8 Mr. Mark Scher, Project Co-ordinator, Postal Savings for Development Project of the United Nations visited India from 19-26 May, 2000. He made a presentation on the subject to Senior Officers of India Post. Mr. Thierry Beaucent, Assistant Counsellor, International Bureau of the UPU visited India from 2-10 August, 2000 to discuss a cost-accounting model for India Post and its applicability in other postal administrations. A three-member delegation from New Zealand Post visited India from 15-18 August, 2000 to make presentations on Business Development Strategy. UPU organised Postal Savings Development Forum at Berne from 1-2.3.2001, which was attended by India Posts.

5.9 An Executive Development Programme was organized at the Postal Staff College of India, Ghaziabad from 30.10.2000-10.11.2000 under the

assistance in kind scheme of the Universal Postal Union. Six fellowships were granted by India to participants from Bangladesh, Sudan, Comoros, Zambia and Kenya.

5.10 The first meeting of the Indo-Uzbek Joint Committee on Posts and Allied Matters was held at New Delhi from 16-18 January 2001. This meeting was convened in pursuance of the bilateral agreement signed between the Government of the Republic of India and the Government of Uzbekistan in the field of Posts and Allied Matters signed during the state visit of the then Uzbek President in January, 1994. Discussions were held on cooperation in the fields of Philately, speedy transmission of mail between the two countries, training facilities available in India Post, counter and savings bank computerization of Uzbek Post, and the later agreed to study the possibility of cooperation in the above mentioned fields.

5.11 Mr. Ata-ur -Rahman, Director General, Bangladesh Post Office visited India from 21-27 January, 2001 to discuss matters of mutual importance.

5.12 H.E. Mr. Deelchand Jeeha, Minister of Information Technology and Telecommunications of the Republic of Mauritius led a delegation of senior officers of the post and telecom sector to India on 14.3.2001 and expressed interest in acquiring Meghdoot 98 software from India.

5.13 During the current year Department of Posts extended the use of International Postal System for the processing of outward airmail items by installing the system at APSO (Foreign) in Mumbai. Hardware for the same was supplied by UPU.

5.14 India attended the Ist SAARC Technical Committee meeting on Transport and Communications at Islamabad in January 2001. The Committee directed on funding a 5 days workshop on post office modernisation/computerisation in India. India also shouldered the responsibility of hosting the 17th SAARC letter writing competition.

5.15 During January, 2001 an agreement as well as MOU was signed for introduction of the International Money Transfer Service in Post Offices in alliance with

5.16 भारतीय डाक ने विश्व फिलैटली विकास संघ (डब्ल्यू ए डी पी) द्वारा ट्यूनिस्, ट्यूनिशिया में 19 से 23-2-2001 तक आयोजित प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता की और परिसंवाद तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली (आई पी एस) परियोजना

5.17 अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस मदों की ट्रेकिंग एंड ट्रेसिंग के लिए दिल्ली और मुम्बई में विगत वर्षों में कार्यान्वित अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली (आई पी एस) परियोजना संतोषजनक ढंग से कार्य कर

रही है। वर्ष के दौरान चेन्नई में आई पी एस परियोजना कार्यान्वित की गई है। कोलकाता में इस परियोजना का प्रारंभिक कार्य पूरा होने वाला है और इसे शीघ्र कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है। दिल्ली और मुम्बई में प्रणाली का उन्नयन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली का प्रचालन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीएनपी) के माध्यम से किया जाता है जिसे पोस्ट नेट कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस का परियात तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5 अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट - ई एम एस परियात			
वर्ष	1999	2000	वृद्धि/कमी
आवक मदें	396393	348820	(-)12.00%
जावक मदें	439425	473076	(+)7.66%

5.18 दिनांक 01.01.2001 से निर्यात विस्तार पटल गुवाहाटी प्रधान डाकघर ने कार्य करना शुरू कर दिया है। निर्यात विस्तार पटल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जावक डाक/पार्सलों के लिए सीमा शुल्क के क्लीयरेंस की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुवाहाटी में खोला गया निर्यात विस्तार पटल वाराणसी, कानपुर, सूरत, नौएडा, आगरा और लुधियाना के बाद 7वां निर्यात विस्तार पटल है।

पत्र डाक

5.19 वर्ष 2000-2001 के दौरान जावक अंतर्राष्ट्रीय पत्र डाक में 15.75% की कमी आई है जबकि उसी अवधि के दौरान आवक परियात में 10.45% की गिरावट दर्ज हुई है। पत्र डाक परियात तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका 6 एल सी/ए ओ डाक - मिलियन कि.ग्रा. में			
वर्ष	1999-00	2000-01	वृद्धि/कमी
आवक मदें	4.19	3.76	(-)10.45%
जावक मदें	3.14	2.64	(-)15.75%

सरफेस एयर लिफ्टेड (एस ए एल) सेवा

5.20 1 नवंबर, 2000 से 15 अन्य बाहरी देशों के लिए पार्सलों की सरफेस एयर लिफ्टेड (एस ए एल) डाक सेवा बढ़ा दी गई है। इनके नाम हैं ईरान, चीन, ब्राजील, बोत्सवाना, आस्ट्रेलिया, कीनिया, ग्रीस, नार्वे, मैक्सिको, फिनलैंड, पुर्तगाल, रशियन फेडरेशन, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और जिम्बाब्वे। इसके साथ ही एस ए

एल पार्सल सेवा अब 38 देशों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

पार्सल

5.21 वर्ष 2000-2001 के दौरान जावक पार्सलों के विदेश परियात में 3.63% की कमी आई है जबकि आवक पार्सलों के विदेश परियात में 5.18% की वृद्धि दर्ज हुई है।



the Western Union Financial Services International (WUFSI), USA.

5.16 India Post chaired the meeting of Management Committee and participated in the Symposium and Training Course organised by World Association for Development of Philately (WADP) on 19-23.2.2001, held at TUNIS, TUNISIA.

International Postal System (IPS) Project

5.17 International Postal System(IPS) Project for the

tracking and tracing of international EMS items implemented at Delhi and Mumbai in the previous years are working satisfactorily. The IPS project at Chennai has been implemented during the year. The preliminary work for the project at Kolkata is nearing completion and is likely to be implemented shortly. Steps are being taken to upgrade the system at Delhi and Mumbai. The International Postal System operates through Universal Postal Union's Virtual Private Network (VNP) called Post NET. The Traffic of international EMS is given in Table 5.

TABLE 5			
INTERNATIONAL SPEED POST - EMS TRAFFIC			
Year	1999	2000	Increase/Decrease
Inward Articles	396393	348820	(-)12.00%
Outward Articles	439425	473076	(+)7.66%

5.18 The Export Extension Counter Guwahati Head Post Office began working with effect from 01.01.2001. The Export Extension Counter will provide Customs clearance facilities for International outward Mails/Parcels. The Export Extension Counter at Guwahati is the 7th Export Extension Counter opened after Varanasi, Kanpur, Surat, Noida, Agra and Ludhiana.

Letter Mail

5.19 Traffic of outward international letter mail has shown a decrease of 15.75% during the year 2000-2001, while the inward traffic during the same period showed a fall of 10.45%. Letter Mail traffic is given in Table 6.

TABLE 6			
LC/AO MAILS - In million Kg.			
Year	1999-00	2000-01	Increase/Decrease
Inward Articles	4.19	3.76	(-)10.45%
Outward Articles	3.14	2.64	(-)15.75%

Surface Air Lifted (SAL) Service

5.20 Surface Airlifted (SAL) Mail Service for parcels has been extended with effect from 1st November, 2000 to 15 more Foreign countries namely Iran, China, Brazil, Botswana, Australia, Kenya, Greece, Norway, Mexico, Finland, Portugal, Russian Federation, South Africa, Thailand and Zimbabwe. With this, the SAL parcel service is now available to 38 countries.

Parcel

5.21 During the year 2000-2001, foreign traffic of outward parcels has registered a decrease of 3.63% while the foreign traffic of inward parcels registered an increase of 5.18%. Foreign Parcel is given in Table 7.

तालिका - 7			
विदेश पार्सल परियात			
वर्ष	1999-00	2000-01	वृद्धि/कमी
आवक मर्दे	230544	242489	(+)5.18%
जावक मर्दे	82394	79407	(-)3.63%

अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा

5.22 आवक मनीआर्डर सेवा 27 देशों के लिए प्रदान की गई है जिसके द्वारा भारत को मनीआर्डर भेजे जा सकते हैं। नेपाल तथा भूटान के लिए दोनों तरफ की मनीआर्डर सेवा प्रदान की गई है जिसके द्वारा भारत को मनीआर्डर भेजे व प्राप्त किये जा सकते हैं।

इस वर्ष के दौरान नेपाल और माल्टा के लिए एकल मनीआर्डर की सीमा को बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। मंत्रिमंडल ने मनीआर्डर करारों के प्रचालन संबंधी उपबंधों के समस्त भावी संशोधनों के लिए भी सामान्य अनुमोदन दे दिया है।

तालिका - 8			
विदेश मनीआर्डर			
क्र. सं.	1999	2000	वृद्धि/कमी
1. मनीआर्डर परियात	48363	51616	(+)6.73%
2. संप्रेषित मनीआर्डरों का मूल्य (मिलियन रु. में)	203.68	195.10	(-)4.21%

पत्र लेखन प्रतियोगिता

5.23 30वीं यू.पी.यू. पत्र लेखन प्रतियोगिता 7 जनवरी, 2001 को आयोजित की गई थी और इस वर्ष कुल 2735 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। युवाओं के लिए यू.पी.यू. और सार्क द्वारा आयोजित की जाने वाली पत्र लेखन प्रतियोगिता का उद्देश्य उनकी लेखन कला को विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को मजबूत करने में योगदान देना है।

अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस

5.24 01 नवंबर, 2000 से ई एम एस (दस्तावेज और वस्तुएं) तथा विदेश पार्सलों (एयर/सरफेस एयर लिफ्टेड और सरफेस) के

डाक शुल्क की दरें संशोधित कर दी गई हैं। ई एम एस की दरों को उच्चतर स्तर पर रखते हुए उसके बाद एयर, सरफेस एयर लिफ्टेड, सरफेस पार्सलों की दरों को ध्यान में रखकर इन दरों को युक्तियुक्त बनाया गया है। ऐसा ग्राहक को उसके धन का अधिकतम मूल्य प्रदान करने की दृष्टि से किया गया है।

ढुलाई और सीमान्त बकाया

5.25 संघ मंत्रिमंडल के अनुमोदन से नेपाल डाक प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई माध्यम से ढुलाई के लिए देय भुगतान और सीमांत बकाया के भुगतान के मुद्दे को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।



TABLE 7
FOREIGN PARCEL TRAFFIC

Year	1999-00	2000-01	Increase/Decrease
Inward Articles	230544	242489	(+)5.18%
Outward Articles	82394	79407	(-)3.63%

International Money Order Service

5.22 Inward Money Order Service is provided with 27 countries where by Money Order can be remitted to India. A two way Money Order Service is provided with Nepal and Bhutan whereby Money Order can be remitted to and from India. During this year

Cabinet approval was obtained for enhancement of a single money order limit with Nepal and Malta. Cabinet has also given a general approval for all future amendments of operational provisions of money order agreements. International money order trend is shown in Table-8.

TABLE 8
FOREIGN MONEY ORDERS

S.No.	1999	2000	Increase/Decrease
1. Money Order Traffic	48363	51616	(+)6.73%
2. Value of MOs transmitted (Rs. in million)	203.68	195.10	(-)4.21%

Letter Writing Competition

5.23 30th UPU Letter Writing Competition was held on 7th January, 2001 and a total of 2735 entries were received this year. The purpose of the letter writing competition conducted by UPU and SAARC for the Young People is to develop their faculty in composition and to contribute to the strengthening of International friendship.

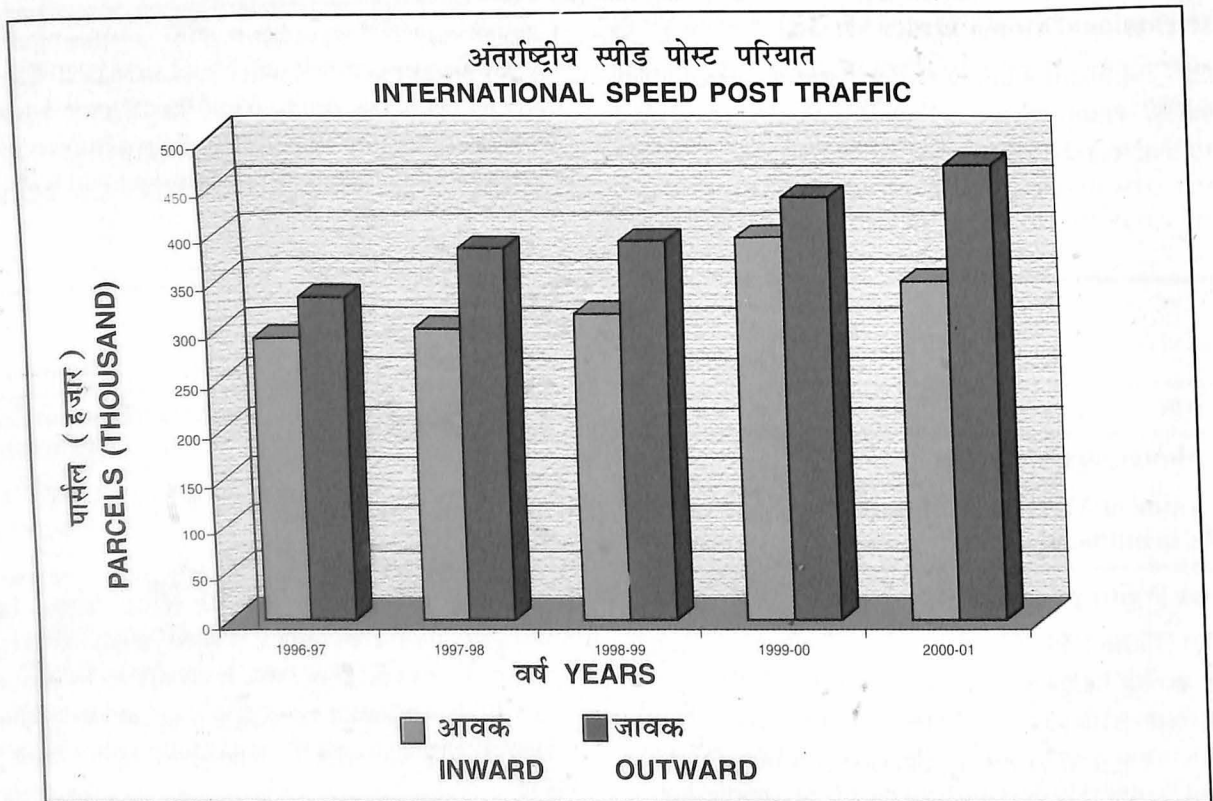
International EMS

5.24 The Postal rates of EMS (documents and merchandise) and foreign Parcels (Air/SAL and

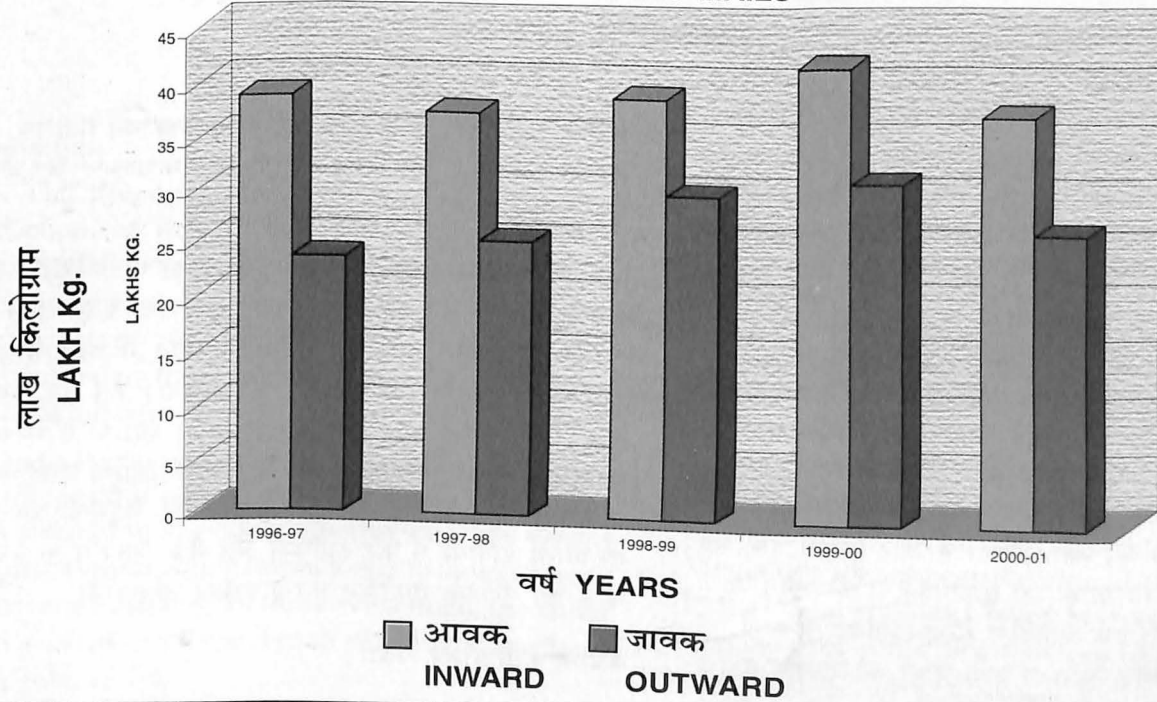
Surface) have been revised with effect from 1st November 2000. The rates have been rationalized by keeping the rates of EMS at the higher level followed by Air, SAL and Surface parcels. This has been done to provide the customer the maximum value for his money.

Conveyance and Terminal Dues

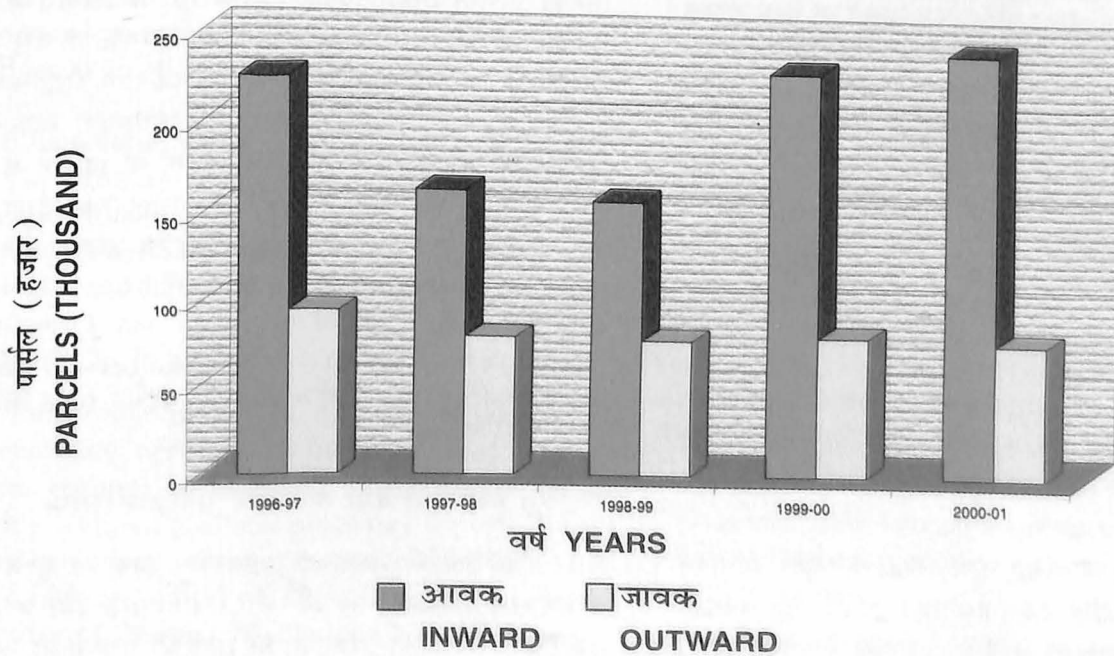
5.25 The issue of the payment of International Air Conveyance Dues and Terminal Dues to Nepal Postal Administration has also been finalised with the approval of the Union Cabinet.



एलसी/एओ डाक
LC/AO MAILS



विदेश पार्सल परियात
FOREIGN PARCEL TRAFFIC



अध्याय 6

प्रौद्योगिकी

भूमिका

6.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, संचार के नए साधनों की शुरुआत और प्रौद्योगिकी विकास ने डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने के भारतीय डाक के प्रयास नब्बे के दशक में प्रारम्भ हुए और फ्रंट ऑफिसों और डाक संरचना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

6.2 भारतीय डाक अब डाक प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के लिए पहले किए गए उपायों का समेकीकरण और एकीकरण करने की ओर अग्रसर है और मौजूदा तथा नए व्यवसाय के लिए विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों को अपने कार्यों में प्रयुक्त कर रहा है। इस वातावरण में मूल्यवर्द्धित सेवाओं की ओर से अत्यंत निर्णायक भूमिका अदा करने की उम्मीद है।

6.3 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभाग की मौजूदा सेवाओं के साथ-साथ नए उत्पादों तथा सेवाओं और मूल्यवर्धन के लिए उपयुक्त एवं नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ अंतरसंबंध बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारतीय डाक द्वारा प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति गठित की गई जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), दूरसंचार विभाग तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति ने नित नई आ रही प्रौद्योगिकियों को प्रभावपूर्ण ढंग से समाविष्ट करने, विद्यमान प्रौद्योगिकी के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए।

काउंटर प्रचालन

6.4 हाल ही में कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय डाक ने लागत-लाभ अनुपात के साथ समझौता किए बिना उभरती हुई प्रौद्योगिकी तथा प्रभावपूर्ण काउंटर प्रचालन के बीच तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वर्ष के दौरान कुल 1000 कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें (एमपीसीएम) लगाई गईं। पुनरीक्षा वर्ष के दौरान जिन कार्यालयों में ये मशीनें लगी हैं उनकी संख्या

बढ़कर 1664 हो गई। कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार ने टिप्पणी की है कि एम पी सी एम उत्कृष्ट जन सेवाओं का अनुपम उदाहरण हैं।

6.5 प्रचालन तथा अनुप्रयोग साफ्टवेयर का मानकीकरण करने, अंतर-प्रचालन, संयोजन और सिंगल पाइंट डाटा एन्ट्री लक्ष्य प्राप्त करने की भारतीय डाक की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी डाकघरों के कार्यों (बचत बैंक के अलावा) हेतु एक व्यापक पैकेज, मेघदूत 98 को 1500 कार्यालयों से अधिक में संस्थापित किया गया। डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर द्वारा पूर्णतया घरेलू रूप से विकसित किया मेघदूत 98 सही मायने में एक बहुमुखी साफ्टवेयर है। किसी डाकघर में फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस के प्रचालन कार्य को पूर्णतया एकीकृत करना इसका उद्देश्य है।

उपग्रह मनीआर्डर सेवा

6.6 अपनी आधुनिकीकरण की कार्यनीति के एक भाग के रूप में भारतीय डाक ने देशभर में जनसाधारण की सहायता करने के लिए एक नवीन उपग्रह आधारित सुलभ पहुंच वाली तत्काल मनीआर्डर सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। मनीआर्डरों के शीघ्र भुगतान की सुविधा देने के लिए डाक प्रणाली में वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) के रूप में नवीनतम प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई है। देश में कुल 139 वीएसएटी स्टेशनों की स्थापना की गई है जिन्हें टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से अन्य 876 स्थानों से जोड़ा गया है। इनमें 1999-2000 के दौरान उच्च गति के 62 वीएसएटी और 266 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशनों का संस्थापन शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2000-01 के दौरान, उच्च गति से 88 वीएसएटी और 466 ईएसएमओ का संस्थापन किया जा रहा है। वीएसएटी पर हो रहे लेन-देनों की संख्या उसके शुरुआत में कुछ हजार से बढ़कर 0.11 मिलियन प्रतिमाह हो गई है।

हाइब्रिड मेल सेवा तथा कारपोरेट मनीआर्डर सेवा

6.7 वीएसएटी के संस्थापन से भारतीय डाक दो मूल्यवर्द्धित उत्पाद यथा हाइब्रिड मेल सर्विस (एचएमएस) और कारपोरेट मनीआर्डर सर्विस की व्यवस्था कर सका है। एचएमएस मूलपाठ



Chapter 6

TECHNOLOGY

Introduction

6.1 The liberalisation of the Indian economy, introduction of new means of communication and technology developments have underlined the need for modernising postal services. India Post's efforts to modernise its services began in the early nineties and was focussed on modernisation of front office areas and postal infrastructure.

6.2 India Post is now moving towards consolidation and integration of the steps taken in the past for computerisation and modernisation of the postal system and harnessing emerging technologies to the existing as well as new business. In this environment the value added services are expected to play an increasingly crucial role.

6.3 A Standing Committee on Technology was constituted by India Post comprising representatives from the Indian Institutes of Technology (IITs), the National Informatics Centre (NIC), the Department of Telecommunications and the Department of Electronics, to advise it in identifying appropriate and new technologies for the existing services, the new products and services, value additions and on interfacing with other Government Departments in the field of Information Technology. The Committee provided valuable suggestions for effective induction of emerging technologies, and improving performance of the existing ones.

Counter Operations

6.4 Technology in the field of computers has been changing very rapidly in recent times. India Post has recognised the need to keep pace with emerging technologies and processes for effective counter operations, without compromising on cost benefit ratio. A total of 1000 Computer based Multipurpose Counter Machines (MPCMs) were installed during the year. The total number of post

offices having such machines went upto 1664 during the year under review. The Ministry of Personnel and Public Grievances, Govt. of India observed that MPCMs were an outstanding example of excellence in public services.

6.5 In keeping with the policy of India Post to standardise operating and application software, achieve inter-operability, connectivity and single point data entry, Meghdoot 98, a comprehensive package for all post office functions (except Savings Bank) was deployed in over 1500 offices. A truly versatile software, Meghdoot 98 has been developed entirely in-house by the Postal Training Center, Mysore. It aims at total integration of front office with back office operations in a post office.

Satellite Money Order Service

6.6 As a part of its modernizing strategy, the India Post has successfully introduced an innovative satellite based easily accessible instant money order service for helping the common man throughout the country. Modern technology in the form of Very Small Aperture Terminals (VSATs) has been introduced in the postal system for facilitating quicker payment of money orders. A total of 139 VSAT stations have been set up in the country which are in turn connected to another 876 locations through the telephone network. This includes 62 High Speed VSATs and 266 Extended Satellite Money Order stations set up during 1999-2000. In addition, 88 High Speed VSATs and 466 ESMOs are under installation during 2000-01. The number of transactions being handled on the VSATs has gone up from a few thousands at the inception to over 0.11 millions per month.

Hybrid Mail Service and Corporate Money Order Service

6.7 Installation of VSATs also enabled India Post to provide two value added products called

तथा डाटा को इलेक्ट्रानिकी द्वारा एक वीएसएटी केन्द्र से दूसरे वीएसएटी केन्द्र में प्रेषण करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है जिससे इसकी हार्ड कॉपी को एक डाक मद की तरह पोस्टमैन द्वारा वितरित किया जा सके। कारपोरेट मनीआर्डर सर्विस ने कारपोरेट ग्राहकों को 10 मिलियन रुपये तक के मनीआर्डर भेजने में सक्षम कर दिया है।

स्वचालित मेल प्रोसेसिंग प्रणाली (एमपीएस)

6.8 भारतीय डाक मुम्बई और चेन्नई में स्वचालित मेल प्रोसेसिंग प्रणाली का उपयोग करती है। ये प्रणालियां प्रतिदिन 10 मिलियन से भी अधिक डाक वस्तुओं को निपटाती हैं। इससे कम समय में भी बृहत मात्रा में डाक निपटाई जाती है।

इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीन (ईएफएम)

6.9 भारतीय डाक ने पहले यह निर्णय लिया था कि सभी इलेक्ट्रो मैकेनिकल फ्रैंकिंग मशीनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करके, उन्हें इलेक्ट्रानिक मशीनों से बदल दिया जाए। बहुमुखी होने के अलावा, इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनों में अतिरिक्त सुरक्षा का गुण है जो उन्हें गड़बड़ी रहित बनाता है तथा राजस्व के क्षरण को रोकता है। इन मशीनों को टेलीफोन लाइनों पर कम्प्यूटर के जरिए दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2000-01 के दौरान कुल 100 इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें संस्थापित की गई हैं जिससे इनकी संख्या बढ़कर 651 हो गई है।

वेब उपस्थिति

6.10 सूचना, संचार एवं विपणन के लिए इंटरनेट की "वर्ल्ड वाइड वेब" का अविर्भाव एक ऐसे माध्यम के रूप में तेजी से हो रहा है जो किफायती और विश्व स्तर पर पहुंच वाला है। विभाग ने 26 जनवरी 2000 से इंडिया पोस्ट. ऑर्ग के नाम से अपनी वेबसाइट स्थापित की है।

6.11 भारतीय डाक निदेशालय का इंटरनेट सुविधा वर्ष 1998-99 के दौरान शुरू हुआ था। इस प्रणाली में 125 नोट्स को कवर करने के लिए इंटरनेट पहुंच, डाक पेटियां, आईसीक्यू, चैट और एफटीपी की व्यवस्था है। इंटरनेट को एक 64 केबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से एकीकृत किया गया है।

6.12 लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) में एक इंटरनेट भी स्थापित किया गया है। अंततः जिसका उद्देश्य एक कागज रहित कार्यालय बनाने की ओर अग्रसर होना है। डाक निदेशालय के लोकल एरिया नेटवर्क का पूर्वोत्तर और असम सर्किल से अंतर्संबंध बना हुआ है। असम सर्किल में गुवाहाटी में एक 64 केबीपीएस लीज्ड लाइन की व्यवस्था की गई है। शिलांग में डायल-अप तंत्र है क्योंकि उस स्टेशन पर किसी लीज्ड सर्किट की व्यवस्था नहीं है।

6.13 ई-व्यवसाय और ई-डाक की क्षमता को पहचानते हुए, भारतीय डाक ने अपनी वेबसाइट एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. इंडियापोस्ट.ऑर्ग स्थापित की है। यह सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाएगी जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर डाक सेवा के संभावित प्रयोक्ता हैं और यह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) सहित अन्य डाक प्रशासनों के साथ संबंध बनाएगी तथा निर्यात योग्य उत्पादों, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के लिए एक विपणन उपकरण के रूप में विकसित होगी।

डाकघरों का आधुनिकीकरण

6.14 भारतीय डाक ने वर्ष 1994-95 से चरणबद्ध तरीके से चयनित डाकघरों का आधुनिकीकरण शुरू किया जिसका, अन्य बातों के साथ-साथ, डाकघरों में प्रचालन उपस्करों का उन्नयन करने और उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल माहौल और कर्मचारियों को एक बेहतर वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य है। यह चालू कार्यक्रम तभी से सफलतापूर्वक लागू किया जाता रहा है। 2000-01 के दौरान 161 डाकघरों को आधुनिकीकृत कर दिया है।

6.15 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारतीय डाक ने अपने आयोजित बजट का 61% प्रौद्योगिकी के अधिष्ठान के लिए किया जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार और उसका उन्नयन किया जा सके, ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके और नए मूल्यवर्द्धित सेवाओं और उत्पादों का विकास कर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।



Hybrid Mail Service(HMS) and Corporate Money Order Service. The former provides the facility to transmit text and data electronically from one VSAT Center to another to effect delivery of its hard copy through the Postman as a postal article. Corporate Money Orders service enables the corporate clients to send Money Orders upto the value of Rs. 10 million.

Automatic Mail Processing System (AMPS)

6.8 India Post uses automatic mail processing system at Chennai and Mumbai. These systems are handling over 10 million articles every day. This has enabled processing of a large volume of mail in a short time.

Electronic Franking Machines (EFMs)

6.9 India Post had earlier decided to phase out all Electro mechanical franking machines and replace those by electronic machines. Besides being versatile, the Electronic Franking Machines have additional security features which make them tamper proof thus preventing leakage of revenue. These machines are also amenable to remote access through computers over telephone lines. A total of 100 Electronic Franking Machines were installed during the year 2000-2001 raising the number to 651.

Web Presence

6.10 The Internet's Worldwide Web is fast emerging as an affordable and globally accessible tool for information, communication and marketing. The Department set up its own Website known as **indiapost.org** w.e.f. 26th Jan.2000.

6.11 The internet facility of India Post Directorate was commissioned during the year 1998-99. The

system provides internet access, mail boxes, ICQ, Chat and FTP to over 125 nodes. Internet has been integrated through a 64 Kbps leased line.

6.12 An intranet has also been set up in the Local Area Network (LAN) that has the objective, in the long run, of moving towards a paperless office. The Postal Directorate's LAN has connectivity to the North Eastern and Assam Circle. Assam Circle has been provided a 64 Kbps leased line at Guwahati. Shillong has a dial up mechanism, as there is no provision of leased circuit at that station.

6.13 Recognising the potential for e-business and e-mail, India Post set up its Website at ***http://www.indiapost.org***. This will facilitate flow of information globally directed at potential users of postal services, connectivity to other postal administrations, including the Universal Postal Union(UPU), and will develop into a marketing tool for 'exportable' products, services and technologies.

Modernisation of Post Offices

6.14 India Post took up modernisation of selected Post Offices in a phased manner from the year 1994-95 which inter-alia aimed at upgrading operational equipment in post offices and providing a friendly ambience for the users and a better working environment for the workers. This on-going programme is being successfully implemented since then. 161 post offices have been modernised during 2000-2001.

6.15 During the 9th Five Year Plan, India Post spent about 61% of its planned budget on induction of technology with a view to improving and upgrading the quality of service, meeting the emerging needs of the customers and developing and providing new value added services and products.

अध्याय-7

वित्तीय सेवाएं

परिचय

7.1 डाक सेवाएं वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपने कार्यकरण का विस्तार कर रही हैं और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दुनिया के अलग-अलग भागों में सौ से अधिक डाक बचत बैंक और जी आई आर ओ काम कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश से इस प्रक्रिया को कार्यरत रूप दिया जा रहा है। इससे डाकघरों के लिए अपने व्यापक नेटवर्क और सामुदायिक स्वीकार्यता का लाभ उठाकर अनेकों प्रकार के धन संबंधी और फ्रैंचाइज वित्तीय सेवाएं प्रदान कर पाना संभव हुआ है।

डाकघर बचत बैंक

7.2 डाकघर द्वारा प्रदान की जा रही पारम्परिक वित्तीय सेवाओं में डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस बी) सम्मिलित है। भारतीय डाक अपने देशव्यापी नेटवर्क, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 1,38,443 डाकघर शामिल हैं, के माध्यम से वित्त मंत्रालय की

ओर से लघु बचत योजनाएं चलाता है।

7.3 डाकघर बचत निम्नलिखित स्कीमों के संदर्भ में सेवा प्रदान करता है:

- बचत खाता योजना
- आवर्ती जमा योजना
- सावधि जमा योजना : 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष एवं 5 वर्ष
- मासिक आय योजना
- लोक भविष्य निधि योजना
- किसान विकास पत्र योजना
- राष्ट्रीय बचत योजना 1992

7.4 बचत योजनाओं के कार्य-व्यापार के विवरण नीचे तालिका 9 में दिए गए हैं:-

तालिका 9		
बचत योजनाएं : कार्य व्यापार रूपरेखा (31.3.2001 की स्थिति के अनुसार)		
योजना का नाम	खातों की संख्या	कुल राशि (मिलियन रूपयों में)
बचत खाता (एसबी)	61116933	88298.7
आवर्ती जमा खाता	47276492	186957.6
सावधि जमा खाता	2426404	696210.3
मासिक आय योजना खाता	8846918	425599.9
राष्ट्रीय बचत योजना-1992	581215	8109.4
लोक भविष्य निधि खाता	1407652	63924.4

नई वित्तीय सेवाएं

7.5 डाकघर बचत बैंक के मौजूदा अधिदेश की समीक्षा करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने डाकघर बचत बैंक के कामकाज का गहन विश्लेषण किया। के पी एम जी (कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड) को भी एक अध्ययन-कार्य सौंपा गया और इनसे अगले कुछेक वर्षों के दरम्यान कुछ निश्चित नए

उत्पादों एवं सेवाओं, जैसे धर्मार्थ निधि का संग्रहण/संवितरण, सामाजिक सुरक्षा हितलाभों और म्युचुअल फंडों/प्रतिभूतियों का वितरण, इलेक्ट्रानिक धन अंतरण, आदि को शुरू करने की सिफारिशें प्राप्त हुईं।

7.6 वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय धन अंतरण प्रणाली की शुरूआत, यूटीआई,



Chapter 7

FINANCIAL SERVICES

Introduction

7.1 Postal Services are diversifying into financial services and data of the UPU indicate that there are more than hundred Postal Savings Banks and GIRO operating in different parts of the world. The process is being facilitated by the induction of information technology making it possible for the post office to provide a wide range of proprietary as well as franchise financial services, leveraging on its wide network and community acceptance.

Post Office Saving Bank

7.2 The traditional financial services offered by the Post Office include the Post Office Savings Bank (POSB). India Post operates the small savings scheme on behalf of the Ministry of Finance through its countrywide network, including 1,38,443 post offices in the rural areas.

7.3 The following schemes are offered by the POSB:

- Savings Accounts Scheme
- Recurring Deposits Scheme
- Time Deposit Scheme: 1 Year, 2 Years, 3 Years and 5 years
- Monthly Income Scheme
- Public Provident Fund Scheme
- Kisan Vikas Patra Scheme
- National Savings Scheme 1992

7.4 The business profiles of the savings scheme are given in Table 9 below:-

TABLE 9		
SAVINGS SCHEME: BUSINESS PROFILE (AS ON 31.3.2001)		
Name of Scheme	No. of Accounts	Total Amount (Rs. in million)
Saving Accounts(SB)	61116933	88298.7
RD Accounts	47276492	186957.6
TD Accounts	2426404	696210.3
MIS Accounts	8846918	425599.9
NSS -92	581215	8109.4
PPF	1407652	63924.4

New Financial Service

7.5 A committee constituted by the Ministry of Finance to review the existing mandate of the post office savings bank made an in depth analysis of the working of the post office savings bank. A study was also entrusted to KPMG(Consulting Private Limited)

and these yielded recommendations for introduction of certain new products and services over the next few years such as, collection/disbursal of charitable funds, distribution of social security benefits and mutual funds/securities, electronic fund transfer etc.

7.6 The Department's new initiatives for

एचडीएयूसी और आईडीबीआई बैंकों के लिए म्युचुअल फंडों का वितरण एवं इलेक्ट्रानिक धन अंतरण जैसी नई पहल इसके ही परिणाम हैं। ग्राहकों और बाजार की अनुक्रिया को ध्यान में रखकर इन स्कीमों को और अधिक क्षेत्रों में पूरी तरह विकसित करने के लिए आगे और कदम उठाए जा सकते हैं

डाक जीवन बीमा

7.7 सन् 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पुरानी कल्याण योजनाओं में से एक है। आज यह स्कीम न केवल केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्मिकों को बल्कि सशस्त्र सेना कार्मिकों, स्थानीय निकायों के

कर्मचारियों, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत सरकार के अनेकों स्वायत्त तथा वित्त संस्थानों और केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवा प्रदान कर रही है। एक अभिनव परिवर्तन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लाभ के लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है।

7.8 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि की स्थिति और वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त कारोबार की स्थिति नीचे तालिका 10 में दी गई है:-

तालिका 10				
डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन : 2000-2001				
योजना का नाम	प्राप्त पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (मिलियन रु. में)	प्राप्त पालिसियों की कुल सं. (सक्रिय)	बीमित सकल राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	156809	13633.4	1952639	104050.8
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	162208	6626.4	823566	28981.6

7.9 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा निम्नलिखित प्रकार की पालिसियों की सुविधा प्रदान करते हैं:

- आजीवन बीमा (सुरक्षा)
- परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सुविधा)
- बंदोबस्ती बीमा (संतोष)
- 15 वर्ष तथा 20 वर्ष का प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (सुमंगल)
- संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा (युगल सुरक्षा)

(vi) 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)

7.10 विभाग ने एक अद्वितीय प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी आरंभ किया है जिसमें डाक कर्मचारियों को नए वित्तीय उत्पादों के बारे में ग्राहकों को प्रभावी रूप से बता पाने हेतु अपेक्षित अनुकूलन एवं कौशल हासिल करने के लिए उनके कार्य-स्थल पर ही उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रायोगिक कार्यक्रम बगैर किसी लागत के कारपोरेट समर्थन से दिल्ली और मुम्बई में चलाया जाता है। यह सरकार-कारपोरेट क्षेत्र की सहभागिता का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

introduction of International Money Transfer in collaboration with the Western Union Financial Services International, distribution of mutual funds and electronic fund transfer for the UTI, HDFC and IDBI banks, are the results. Depending on the response of the customers and the market further steps could be taken for fully developing these schemes over wider areas.

Postal Life Insurance

7.7 Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is one of the oldest welfare schemes for the Government employees. The scheme today caters not

only to employees of the Central and State Government, but also to Armed Forces personnel, employees of the local bodies, Government aided educational institutions, Universities, Nationalized Banks, many autonomous and financial institutions of the Government of India and Central and State Public Sector Undertakings. In a major innovation, Rural Postal Life Insurance scheme was introduced in 1995 for the benefit of the rural populace.

7.8 The status of PLI/RPLI fund as on 31.3.2001 and the business produced during the year 2000-2001 are given in Table 10.

TABLE 10				
PERFORMANCE OF PLI/RPLI : 2000-2001				
Name of Plan	No. of Policies procured	Sum Assured (Rs. in million)	Aggregate No. of policies (Active)	Aggregate Sum Assured (Rs. in million)
PLI	156809	13633.4	1952639	104050.8
RPLI	162208	6626.4	823566	28981.6

7.9 PLI and RPLI offer the following type of policies:-

- Whole Life Assurance (Suraksha)
- Convertible Whole Life Assurance (Suvidha)
- Endowment Assurance (Santosh)
- Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Sumangal)
- Joint Life Endowment Assurance (Yugal Suraksha)

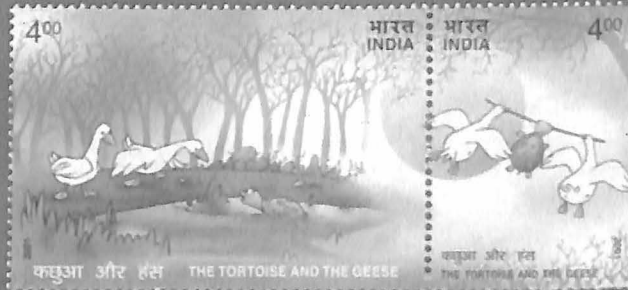
(vi) 10 years RPLI (Gram Priya)

7.10 The Department, has also initiated a unique pilot training programme in which, postal officials are to be trained in their place of work to acquire the necessary orientation and skill for effective interphasing with customers for the new financial products. The pilot programme run at no-cost in Delhi and Mumbai with corporate support providing an example of government- corporate sector partnership.

कुछ विशेष डाक टिकट



SOME THEMATIC STAMPS





अध्याय-8

वित्तीय प्रबंधन

परिचय

8.1 भारतीय डाक जनता को डाकघरों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है। पूर्ण डाक सुविधाओं के अतिरिक्त डाकघर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों की ओर से कई अन्य सेवाएं तथा एजेंसी कार्य भी करते हैं। 2000-2001 के दौरान विभाग का कुल वित्त निष्पादन काफी अच्छा रहा। लगातार पांचवें वर्ष में विभाग 49072.9 मिलियन रुपए के कार्यकारी व्यय को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 49987.0 मिलियन रुपए की संशोधित प्राक्कलन बजट सीमा के भीतर रखने में कामयाब हो सका। यह कड़े बजटीय नियंत्रण और सूक्ष्म मानीटरिंग द्वारा संभव हुआ। वित्त वर्ष

2000-2001 के दौरान विभाग का घाटा 15497.6 मिलियन रुपए का था जो पिछले वर्ष के 15958.2 मिलियन रुपए के घाटे की तुलना में कम था।

8.2 वर्ष 2000-2001 का निवल कार्यकारी व्यय पिछले वर्ष के 36159.4 मिलियन रुपए के व्यय की तुलना में 48475.7 मिलियन रुपए था (अर्थात् इसमें लगभग 34.06% की वृद्धि हुई)। यह वृद्धि मुख्यतः वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार वसूली के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों में बचत बैंक और बचत पत्र कार्य के लिए 13023.5 मिलियन रुपए के पारिश्रमिक लेने के कारण हुई।

Chapter 8

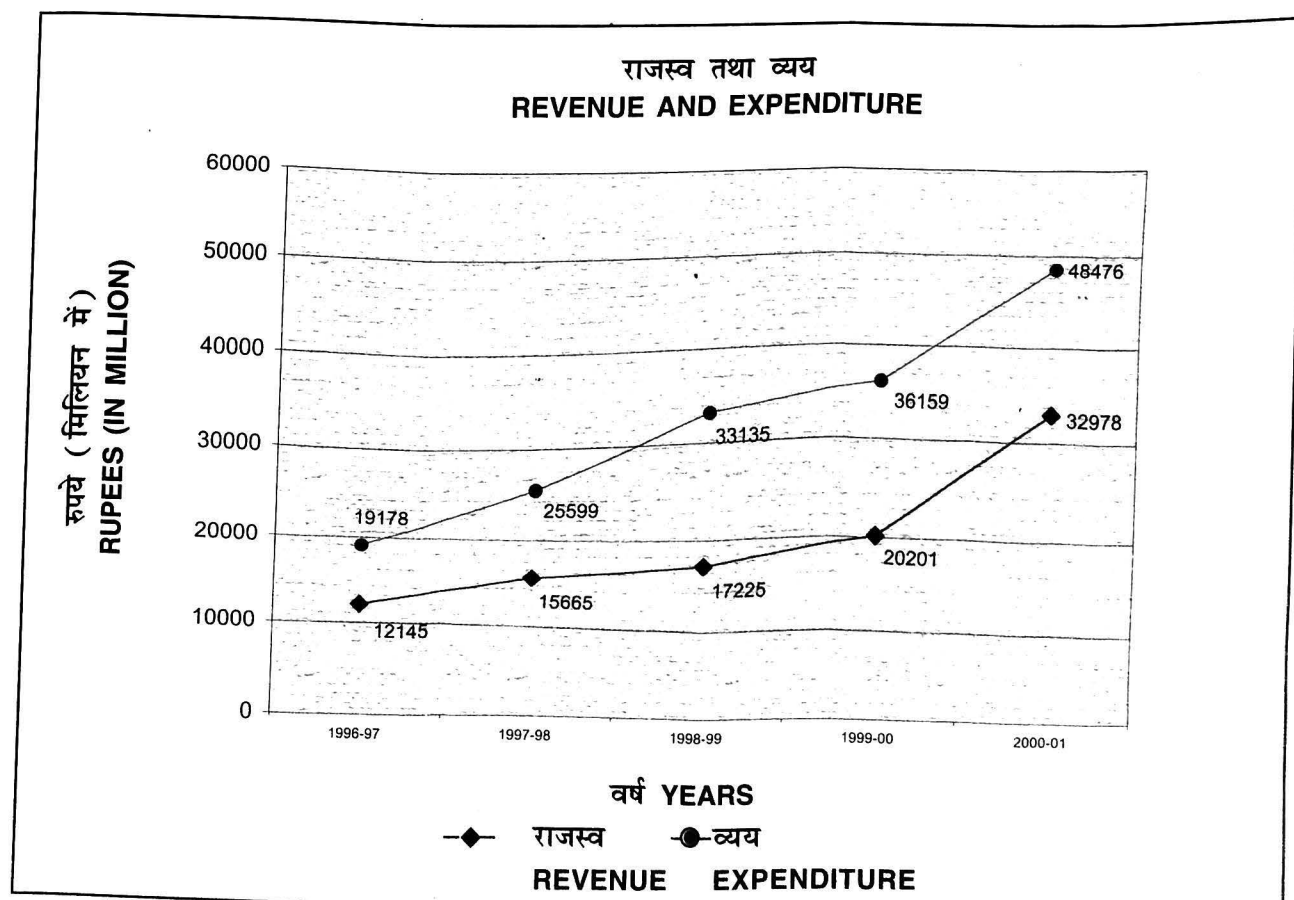
FINANCIAL MANAGEMENT

Introduction

8.1 The India Post provides various services to the public through a nation wide network of post offices. Besides extending purely postal facilities, post offices perform various financial services and agency functions on behalf of the other Ministries/Departments of the Govt. of India. The overall financial performance of the Department during 2000-01 was very good. For the fifth consecutive year the Department has been able to keep the working expenses of Rs. 49072.9 million well within the Revised Estimates budget ceiling of Rs. 49987.0 million, approved by the Ministry of Finance. This was possible through strict budgetary control and

close monitoring. During the financial year 2000-01 the deficit of the Department was Rs. 15497.6 million which was lower than the deficit of Rs. 15958.2 million for previous year.

8.2 The net working expenses of the year 2000-01 were Rs. 48475.7 million against the previous year's expenditure of Rs. 36159.4 million (i.e. an increase of about 34.06%). This increase was mainly due to taking of remuneration of Rs. 13023.5 million for Saving Bank and Saving Certificate work in Revenue Receipts instead of recoveries as per instructions from Ministry of Finance.



तालिका 11 राजस्व और व्यय (वर्ष 2000-01 के लिए)					
(मिलियन रुपये में)					
व्यौरा	वास्तविक आंकड़े	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	2000-01 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) / प्रतिशत कमी (-)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि(+) / प्रतिशत कमी (-)
राजस्व	1999-00	2000-01			
डाक-टिकटों की बिक्री	10711.3	10692.4	10037.1	-6.13%	-6.29%
नकदी के रूप में प्राप्त डाक शुल्क	6518.7	6750.0	6651.9	-1.45%	2.04%
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर आदि पर कमीशन	2535.5	2300.0	2619.7	13.90%	3.32%
# बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पारिश्रमिक	0.00	13173.5	13023.5	-1.14%	-
*अन्य प्राप्तियां	435.7	557.6	645.9	15.84%	48.24%
कुल	20201.2	33473.5	32978.1	-1.48%	63.25%
व्यय					
सामान्य प्रशासन	2841.6	2978.3	2910.0	-2.29%	2.41%
प्रचालन	33801.7	34079.0	33506.3	-1.68%	0.87%
एजेंसी सेवाएं	1780.1	1877.6	1820.2	-3.06%	2.25%
**अन्य	9360.6	11052.1	10836.4	-1.95%	15.77%
कुल सकल व्यय	47784.0	49987.0	49072.9	-1.83%	2.70%
घटाएं वसूलियां	11624.6	750.0	597.2	-20.37%	-94.86%
निवल व्यय	36159.4	49237.0	48475.7	-1.55%	34.06
घाटा (निवल व्यय-राजस्व)	15958.2	15763.5	15497.6	-1.69%	2.89%
# संशोधित अनुमान 2000-01 में और उसके आगे एम एच 1201 राजस्व के अंतर्गत लिया गया।					

* इसमें भारतीय डाक द्वारा बिक्री किए गए पासपोर्ट आवेदन फार्म, पासपोर्ट शुल्क टिकट एवं केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के सेवा प्रभार तथा अन्य डाक प्रशासनों आदि से हुई आय शामिल है।

** इसमें मजदूरी, कार्यालय व्यय, समयोपरि भत्ता, किराया एवं कर, प्रोफेशनल सेवाएं, अनुरक्षण, स्टाफ को सुविधाएं, पेंशन संबंधी प्रभार, आपूर्ति और सामग्री, यांत्रिक उपस्कर, अन्य प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं।

TABLE 11
REVENUE AND EXPENDITURE
(FOR THE YEAR 2000-01)

(Rs. in million)

Particulars	Actuals	RE	Actuals	%age Inc(+)/Dec (-) over RE	%age Inc(+)/Dec (-) over Previous year
Revenue	1999-00		2000-01	2000-01	
Sale of Stamps	10711.3	10692.4	10037.1	-6.13%	-6.29%
Postage Realised in Cash	6518.7	6750.0	6651.9	-1.45%	2.04%
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders etc.	2535.5	2300.0	2619.7	13.90%	3.32%
# Remuneration for Saving Bank/Saving Certificates Work.	0.00	13173.5	13023.5	-1.14%	-
*Other Receipts	435.7	557.6	645.9	15.84%	48.24%
Total	20201.2	33473.5	32978.1	-1.48%	63.25%
Expenditure					
General Administration	2841.6	2978.3	2910.0	-2.29%	2.41%
Operation	33801.7	34079.0	33506.3	-1.68%	0.87%
Agency Services	1780.1	1877.6	1820.2	-3.06%	2.25%
**Others	9360.6	11052.1	10836.4	-1.95%	15.77%
Total Gross Expenditure	47784.0	49987.0	49072.9	-1.83%	2.70%
Less Recoveries	11624.6	750.0	597.2	-20.37%	-94.86%
Net Expenditure	36159.4	49237.0	48475.7	-1.55%	34.06
Deficit(Net Expd.-Revenue)	15958.2	15763.5	15497.6	-1.69%	2.89%
# taken under MH 1201 Revenue in RE 2000-01 and onward					

* This includes service charges retained by the India Post for sale of Passport Application Form, Passport Fee Stamps & Central Recruitment Fee stamp receipts from other Postal Administration, etc.

** This includes Wages, Office Expenses, Overtime Allowance, Rent and Taxes, Professional Services, Maintenance, Amenities to Staff, Pensionary charges, Supplies and Material, Machinery & equipment, other Administrative expenses, etc.

तालिका 12 2000-01 में एजेंसी सेवाओं पर कार्यकारी व्यय की वसूली (मिलियन रुपये में)				
क्रम लेखा शीर्ष सं.	1999-2000 संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	2000-01 संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े
1. बचत बैंक और बचत पत्र #	10550.0	10550.0	00.0	00.0
2. सैनिक पेंशन	4.5	5.1	5.0	4.4
3. कोयला खनिकों तथा ईपीएफ/परिवार पेंशन तथा विविध सेवाओं का भुगतान	28.0	34.2	50.0	26.2
4. रेलवे पेंशन का भुगतान	47.5	45.9	50.0	40.8
5. डाक जीवन बीमा	430.0	796.0	560.0	426.6
6. सीमा शुल्क वसूली	11.0	9.1	10.0	59.5
7. महिला समृद्धि योजना	180.0	173.0	18.2	18.2
8. संयुक्त डाक-तारघरों का टेलीग्राफ हिस्सा	181.5	- 31.3	25.8	-1.6
9. अन्य*	17.5	42.6	31.0	23.1
कुल	11450.0	11624.6	750.0	597.2
# संशोधित प्राक्कलन 2000-01 में और उसके आगे एम एच 1201 राजस्व के अंतर्गत लिया गया।				

* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर-डाक टिकटों की बिक्री पर कमीशन, सेना डाक सेवा, लेखे और अन्य सरकारी विभागों से वसूलियां और पूंजी के नामे डाला जाने वाला स्थापना का भाग आदि शामिल है।

8.3 विभाग की आय “वसूलियां” और “राजस्व” के रूप में होती है। उपर्युक्त तालिका 12 में उल्लिखित वसूलियों की मद विभाग द्वारा अर्जित कमीशन की वह रकम दर्शाती है जो विभाग द्वारा अन्य विभागों तथा संगठनों की ओर से किए गए एजेंसी कार्यों से अर्जित की गई है और राजस्व में डाक मदों की बिक्री, मनीआर्डरों तथा भारतीय पोस्टल आर्डरों पर कमीशन तथा अन्य प्रीमियम सेवाओं और बचत बैंक तथा बचत पत्र कार्य के पारिश्रमिक से हुई प्राप्तियों के जरिये हुई आय है। विभाग की आय खर्च किए गए कार्यकारी व्ययों की तुलना में कम है। इसके परिणामस्वरूप घाटे में और वित्त मंत्रालय से मिलने वाली तदनुसारी वित्तीय सहायता में क्रमशः वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष घाटे में होने वाली वृद्धि की प्रकृति को कार्यकारी व्ययों को नियंत्रित करके और साथ ही विभाग की आय में वृद्धि करके रोका जा सकता है। तथापि कार्यकारी व्ययों की कुछ सीमा तक अत्यधिक कटौती कर पाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि लगभग

88 प्रतिशत कार्यकारी व्यय वेतन, पेंशन आदि से संबंधित होते हैं जो कि अनिवार्य देयताएं हैं। डाक वस्तुओं की शुल्क दरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि करके “राजस्व प्राप्ति” एजेंसी कार्यों के कारण पारिश्रमिक में संशोधन और संगठित विपणन तथा नए-नए उत्पादों के विपणन के लिए नीतिगत तालमेल बिठाकर हाइब्रिड मेल सर्विस, मास मेलिंग, कारपोरेट मनीआर्डर आदि जैसी प्रीमियम सेवाओं पर लाभार्जन को प्रोत्साहित करके सुधार लाया जा सकता है। वर्ष 2000-01 के दौरान विभाग का घाटा 15497.6 मिलियन रुपए था जो पिछले वर्ष के 15958.2 मिलियन रुपए के घाटे की तुलना में कम था। कार्यकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद, यह राजस्व प्राप्तियों और वसूलियों में पर्याप्त वृद्धि के कारण था।

8.4 वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान “कार्यकारी व्ययों” और “पूंजीगत परिव्यय” के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष के दौरान पूर्णतः और समुचित रूप से उपयोग कर लिया गया था। सरप्लस निधि को समय पर वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित कर दिया

TABLE 12					
RECOVERY OF WORKING EXPENSES ON ACCOUNT OF AGENCY SERVICES IN 2000-2001.					
(Rs. in million)					
Sl. No.	Head of Account	1999-2000		2000-01	
		RE	Actuals	RE	Actuals
1.	Saving Bank and Saving certificates #	10550.0	10550.0	00.0	00.0
2.	Military Pension	4.5	5.1	5.0	4.4
3.	Payment of Coal Mines and EPF/Family Pension & Misc. Services	28.0	34.2	50.0	26.2
4.	Payment of Railway Pension	47.5	45.9	50.0	40.8
5.	Postal Life Insurance	430.0	796.0	560.0	426.6
6.	Custom Duty Realisation	11.0	9.1	10.0	59.5
7.	Mahila Samridhi Yojna	180.0	173.0	18.2	18.2
8.	Telegraph share of Combined Offices	181.5	- 31.3	25.8	-1.6
9.	Others*	17.5	42.6	31.0	23.1
	Total	11450.0	11624.6	750.0	597.2
# taken under MH1201 Revenue in RE 2000-01 and onward					

* This includes Commission on sale of Non-Postal stamps of Delhi Administration, Recoveries from Army Postal Services Accounts and other Government Departments and share of Establishment debitable to capital, etc.

8.3 The earnings of the Department are in the form of 'Recoveries' and 'Revenue'. The item 'Recoveries' mentioned in table 12 represents the amount of commission earned by the Department for Agency Functions done on behalf of other Departments and organizations and the 'Revenue' is on account of sale of Postal articles, commission of money orders and Indian Postal Orders and receipts from other premium services and remuneration for the Saving Bank and Saving Certificates work etc. The earnings of the Department are on the lower side in comparison to the working expenses incurred. This has resulted in gradual increase in deficit and corresponding budgetary support from the Ministry of Finance. The trend of increasing the deficit every year can be arrested by controlling working expenses and also by increasing the earnings of the Departments. However, substantial reduction in

working expenses to a certain extent is not practicable as nearly 88% working expenses relating to salary, pension etc., are in the form of committed liabilities. Improvement can be brought about only in the 'Revenue' receipts by adequately increasing tariff rates of Postal articles, revision of remuneration on account of agency functions and also encouraging profit earning on premium service, Hybrid Mail Service, Mass Mailing, Corporate Money Orders, etc. During the financial year 2000-01 the deficit of the department was Rs. 15497.6 million which is lower than previous year's deficit of Rs. 15958.2 million. This was due to appreciable increase in Revenue Receipts and Recoveries, despite increase in the Working Expenses.

8.4 The funds made available by the Ministry of Finance for 'Working Expenses' and 'Capital Outlay' during the year were fully and appropriately utilized

गया था। यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्रभावी बजट नियंत्रण और संभव हो सकी।
मासिक आधार पर व्यय की स्थिति पर निगरानी रखने के कारण

तालिका 13 2000-2001 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत (मिलियन रुपये में)							
व्यय की प्रकृति	अनुपूरक अनुदान सहित बजट प्राक्कलन	पुनः अनुमोदित अनुपूरक अनुदान	कुल	वास्तविक व्यय	अधिक (+) / बचत (-)	अभ्यर्पित/ पुनः अनुमोदित राशि	बचत
3201 कार्यकारी व्यय	52424.7	22.4	52447.1	49072.9	-3351.8	2493.4	-880.8
2552 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	120.0	0.0	120.0	0.0	-120.0	120.0	0.00
5201 पूंजीगत परिव्यय	890.4	101.7	992.1	532.9	-357.5	398.6	-60.6
कुल	53435.1	124.1	53559.2	49605.8	-3829.3	3012.0	-941.4

पूंजीगत परिव्यय

8.5 वर्ष 2000-2001 में नियत परिसम्पत्तियों पर 552.8 मिलियन रुपए का व्यय हुआ जिसमें से 41.39% भूमि और भवनों पर और 58.61% कंप्यूटर, उपकरणों और प्लांट्स, रेल डाक सेवा वैनो, मेल मोटर वाहनों और अन्य पर हुआ। वर्ष के अंत में नियत परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत मूल्य बढ़कर 10077.9 मिलियन रुपए हो गया। वर्ष के अंत तक निवल प्रगामी नियत परिसम्पत्ति मूल्य 8344.4 मिलियन रुपए हो गया।

सेवाओं की लागत

8.6 सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के अत्यावश्यक घटक के रूप में देश के विभिन्न भागों और इसके लोगों के बीच अपेक्षित संपर्क स्थापित करने में डाक सेवाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संभावित सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवाओं को आधुनिकीकृत करने हेतु राजस्व अर्जित करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि व्यावसायिक/वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा प्रमुख रूप से प्रयुक्त सेवाओं को काफी अधिक आर्थिक सहायता न दी जाए, विभिन्न सेवाओं के डाक शुल्क में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

during the year. The surplus funds were surrendered in time to the Ministry of Finance. This appreciable achievement was made possible by effective budgetary

control and by monitoring progress of expenditure on a month to month basis.

TABLE 13 FUNDS SURRENDERED AND SAVINGS DURING 2000-01. (Rs. in million)							
Nature of Expenditure	Budget Est. including suppl. Grant	Suppl. Grant Re-app.	Total	Actual Expd.	Excess (+)/ Saving (-)	Amount Surrendered/ Re-app.	Savings
3201 Working Expenditure	52424.7	22.4	52447.1	49072.9	-3351.8	2493.4	-880.8
2552 Prov. for the Development of N.E. Region	120.0	0.0	120.0	0.0	-120.0	120.0	0.00
5201 Capital Expd.	890.4	101.7	992.1	532.9	-357.5	398.6	-60.6
Total	53435.1	124.1	53559.2	49605.8	-3829.3	3012.0	-941.4

Capital Outlay

8.5 The expenditure on fixed assets in the year 2000-01 was Rs. 552.8 million of which 41.39% was on land and buildings and 58.61% on Computers, Apparatus & Plants, RMS Vans, Mail Motor Vehicles and others. The value of Capital on fixed assets rose to Rs. 10077.9 million, at the end of the year. The net progressive fixed asset value up to the end of the year was Rs. 8344.4 million.

Cost of Services

8.6 The postal services as an essential element of the socio-economic infrastructure have a significant and important role in providing the required connectivity among various parts of the country and its people. Keeping in view this eventual social obligation and the need for generating revenues to modernise the services for meeting the need to ensure that services predominantly utilised by business/commercial sectors do not enjoy too high a level of subsidy, the postal tariff of various services are revised from time to time.

तालिका 14
सेवाओं की लागत

(रुपयों में)

		1998-99 (वास्तविक)		2000-2001 (प्रायोजना)	
क्र. सं.	सेवा का नाम	औसत लागत	औसत राजस्व	औसत लागत	औसत राजस्व
1.	पोस्टकार्ड	4.79	0.25	5.80	0.25
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	4.80	1.50	5.81	2.00
3.	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	4.84	2.58	5.88	4.00
4.	पत्र कार्ड (अंतर्देशीय पत्र)	4.78	1.29	5.78	2.00
5.	पत्र	5.54	4.97	6.72	5.89
6.	पंजीकृत समाचार पत्र - एकल	6.63	0.25	8.07	0.20
7.	पंजीकृत समाचार पत्र - बंडल	10.84	0.51	13.33	0.50
8.	बुक पोस्ट - बुक, पैटर्न एवं सैम्पल पैकेट	6.69	3.60	8.14	4.96
9.	बुक पोस्ट - मुद्रित पुस्तकें	11.01	2.42	13.55	2.44
10.	बुक पोस्ट - अन्य पत्रिकाएं	10.53	1.95	12.94	4.07
11.	पावती	4.48	1.58	5.40	2.00
12.	पार्सल	45.85	34.46	56.28	49.05
13.	पंजीकरण	26.75	11.17	32.09	14.00
14.	स्पीड पोस्ट	26.85	46.62	25.88	40.36
15.	मूल्यदेय डाक	21.06	2.75	25.44	3.96
16.	बीमा	36.32	75.32	43.67	65.90
17.	मनीआर्डर	40.31	18.65	48.62	19.68
18.	तार मनीआर्डर	51.65	20.65	62.33	21.68
19.	भारतीय पोस्टल आर्डर	17.51	1.02	21.81	1.27
20.	विदेश डाक	10.47	13.49	12.82	22.91

TABLE 14
COST OF SERVICES

(In Rs.)

		1998-99(Actual)		2000-2001(Projection)	
Sl.No.	Name of Service	Average Cost	Average Revenue	Average Cost	Average Revenue
1	Postcard	4.79	0.25	5.80	0.25
2	Printed Postcard	4.80	1.50	5.81	2.00
3	Competition Postcard	4.84	2.58	5.88	4.00
4	Letter Card(Inland Letter)	4.78	1.29	5.78	2.00
5	Letter	5.54	4.97	6.72	5.89
6	Regd.Newspaper-Single	6.63	0.25	8.07	0.20
7	Regd.Newspaper-Bundle	10.84	0.51	13.33	0.50
8	Book Post-Book, Pattern & S.Pkts.	6.69	3.60	8.14	4.96
9	Book Post-Printed Books	11.01	2.42	13.55	2.44
10	Book Post-Other Periodicals	10.53	1.95	12.94	4.07
11	Acknowledgement	4.48	1.58	5.40	2.00
12	Parcel	45.85	34.46	56.28	49.05
13	Registration	26.75	11.17	32.09	14.00
14	Speed Post	26.85	46.62	25.88	40.36
15	Value Payable Post	21.06	2.75	25.44	3.96
16	Insurance	36.32	75.32	43.67	65.90
17	Money Order	40.31	18.65	48.62	19.68
18	Tele.Money Order	51.65	20.65	62.33	21.68
19	Indian Postal Order	17.51	1.02	21.81	1.27
20	Foreign Mail	10.47	13.49	12.82	22.91

अध्याय-9

मानव संसाधन विकास

9.1 किसी भी संगठन की शक्ति उससे जुड़े व्यक्तियों में निहित होती है। इस 2,83,609 कर्मचारियों की जनशक्ति वाले विभाग के पास सुविकसित आधारभूत प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध है। यह विभाग मानव संसाधन विकास पर निरंतर सर्वाधिक ध्यान देता रहा है जिसे डाक प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के समावेश की दृष्टि से हाल के वर्षों में और अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। इसने प्रबंध एवं प्रचालन के तथा अन्य कर्मचारियों की दक्षता के निरंतर उन्नयन और उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से ऑन-द-जॉब और संस्थागत, दोनों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।

प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचा

9.2 विभाग के प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं:

- (1) पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद; और
- (2) दरभंगा, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर, और वडोदरा स्थित क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र
- (3) सर्किल/क्षेत्रीय स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब-पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत और डाक प्रशिक्षण केन्द्र सहित।

पोस्टल स्टाफ कालेज

9.3 गाजियाबाद स्थित पोस्टल स्टाफ कालेज विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवा और डाक सेवा समूह "ख" के अधिकारियों में अपेक्षित ज्ञान, दक्षता और आचार-व्यवहार का विकास करना है ताकि वे डाक प्रणाली को अधिक कार्यकुशल और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना सकें। इस दृष्टि से सेवा में भर्ती के समय और सेवाकाल के दौरान उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। डाक सेवाओं के प्रबंध क्षेत्रों में अनुसंधान करना और उसका प्रसार करना तथा पोस्टल डाटा बैंक और डाक्यूमेंटेशन केन्द्रों की स्थापना करना भी कालेज का उद्देश्य है।

9.4 यह कालेज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.), एशियन पैसिफिक पोस्टल कालेज, बैंकाक (थाईलैण्ड) के परामर्श पर

तथा दक्षेस देशों के मध्य हुए करार के अंतर्गत विदेशी डाक प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लाभ के लिए डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशाला का आयोजन भी करता है।

9.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कालेज ने 5 प्रवेश (इंडक्शन) तथा 14 सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 643 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 242 अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

9.6 विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

(1) स्वीडन	1
(2) थाईलैंड (एशिया प्रशांत पोस्टल कालेज)	8
(3) जापान	1

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

9.7 क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं:

- निरीक्षकों और समयमान डाक एवं छंटाई सहायकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना;
- डाक एवं छंटाई सहायकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर्स आदि को सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर तथा साफ्टवेयर प्रणालियों को समझने, उनका प्रचालन करने के लिए अपेक्षित दक्षता और उनकी जानकारी प्रदान करना।

9.8 2000-2001 के दौरान, पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल 10,298 कर्मचारियों को सेवाकालीन और प्रवेश प्रदान किया गया है।

विदेशी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण

9.9 पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद में 30.10.2000



Chapter 9

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

9.1 The strength of an organization is the strength of its people. The Department with a manpower of 2,83,609 regular employees has a well-developed training infrastructure. It has always been giving priority attention to human resource development, which in recent years received added stimulus in view of induction of Technology in postal operations. It has worked out extensive training programmes, both on the job as well as institutional, for the managers, operatives and other functionaries for continually upgrading skills and professional competence.

Training Infrastructure

9.2 The training infrastructure of the department consists of the following training institutes:

1. Postal Staff College India, Ghaziabad.
2. Regional Postal Training Centres at Darbhanga, Madurai, Mysore, Saharanpur and Vadodara.
3. Computer Training Labs at Circle/Regional levels including PSCI/PTCs.

Postal Staff College

9.3 The Postal Staff College India, Ghaziabad is the apex training institution catering to the training needs of the managerial cadres of the Department. The primary objective of the college is to impart induction as well as in-service training to the officers of the Indian Postal Service and Postal Service Group "B" with a view to inculcating requisite knowledge, skills and attitude to enable them to make the Postal System effective and responsive to customer's needs. The college also undertakes and promotes research in the spheres of management of Postal Services. The mandate of the college is also to build up a Postal Data Bank and documentation Centre.

9.4 In addition, the college also organizes work shops on different aspects of the Postal Services at the

behest of the Universal Postal Union (UPU), Asian Pacific Postal College, Bangkok (Thailand) and under the agreement amongst SAARC countries for the benefit of officers belonging to foreign postal administrations.

9.5 During the period under review, the college conducted 5 induction and 14 in-service training programmes, in which 643 officers participated. Besides, 242 officers were imparted training in computers during the period.

Indian Postal Service Officers Trained Abroad

9.6 The number of Indian Officers trained abroad is as under:-

Sweden	1
Thailand (Asian Pacific Postal College)	8
Japan	1

Regional Postal Training Centres

9.7 The main objectives of the Regional Postal Training Centres are:

- To impart induction training to Inspector Posts and Time Scale Postal and Sorting Assistants.
- To impart in-service and refresher training to Postal and Sorting Assistants, Supervisors, Inspectors, ASPOs, Postmasters etc., and
- To impart the skills and knowledge required for understanding and operating Computer hardware and software systems relevant to the needs of the Department.

9.8 A total number of 10298 officials were imparted in-service and induction training during 2000-2001 by the five Regional Training Centres.

Training For Foreign Participants

9.9 An Executive Development Programme was organized at Postal Staff College India, Ghaziabad from

से 10.11.2000 तक एक कार्यकारी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 भारतीय अधिकारियों सहित केन्या, सूडान, कॉमोरोस, जाम्बिया डाक प्रशासनों के एक-एक तथा बंगलादेश के दो अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

9.10 कॉलेज ने भारतीय डाक सेवा 2000 बैच के परिवीक्षकों के साथ भूटान डाक के दो अधिकारियों के लिए भी प्रवेश प्रशिक्षण का आयोजन किया।

9.11 डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर में 8.01.2001 से 17.2.2001 तक आई टी ई सी/ एस सी ए ए पी कार्यक्रम के अंतर्गत “डाक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी” पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें 20 लोगों ने भाग लिया।

कार्यस्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं

9.12 पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद तथा पांच डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा सर्किलों/क्षेत्रों के मुख्यालयों में 33 कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब (सी टी एल) कार्य कर रहे हैं। ये लैब बुनियादी कम्प्यूटर दक्षता प्रदान करने के साथ हमारे अनुप्रयोग साफ्टवेयर जैसे मेघदूत 98, संचय पोस्ट, वी 2 एस बी सी ओ, वी एस ए टी, सी ए एम पी (सी आर सी) आदि का रखरखाव भी करते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के निकट ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना है।

9.13 वर्ष 2000-2001 के दौरान पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और 33 सी टी एल द्वारा कुल 14,119 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।



30.10.2000 to 10.11.2000. One officer each from the postal administrations of Kenya, Sudan, Comoros, Zambia and two officers from Bangladesh attended the programme along with 6 Indian Officers.

9.10 The college had also organized Induction Training for two officers of Bhutan Post along with the Probationers of Indian Postal Service 2000 batch.

9.11 An International Training Programme on **'IT In Postal Services'** under ITEC/SCAAP Programme with 20 participants was conducted at **Postal Training Centre, Mysore** from 08-01-2001 to 17-02-2001.

Workplace Computer Training Facilities

9.12 33 Computer Training Labs (CTL) are functioning at the Headquarters of Circles/Regions in addition to those at Postal Staff College India, Ghaziabad and five Postal Training Centre. These CTLs take care of imparting Basic Computer skills and our application softwares like Meghdoot 98, Sanchay Post, V2 SBCO, VSAT, CAMP (CRC) etc., with the objective of exposing a larger number of staff to computer training near the workplace.

9.13 A total number of 14,119 officials were imparted training during 2000-2001 by the Five Regional Training Centres and 33 CTLs.

अध्याय 10

सतर्कता कार्यकलाप

10.1 यद्यपि विभाग में सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता बनाए रखने का मुख्य उत्तरदायित्व सचिव डाक विभाग का है, तथापि उपमहानिदेशक (सतर्कता) विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी सभी मामलों में सचिव के विशेष सहायक के तौर पर कार्य करते हैं और वे डाक विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

10.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता मामलों को देखने के अलावा निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में संवेदनशील स्थानों का नियमित और अचानक निरीक्षण करने, ऐसी कार्यविधियों की समीक्षा करने और उन्हें दोषरहित बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की आशंका हो। वे विभाग और इसके फील्ड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दूसरे प्रकार के अनाचारों की रोकथाम, इनका पता लगाने और दण्ड देने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

10.3 मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए मुख्यालय में निदेशक (सतर्कता), तीन सहायक महानिदेशक और एक डेस्क अधिकारी हैं। सर्किल, क्षेत्रीय और डिवीजनल स्तर पर सतर्कता संबंधी कार्य इनके प्रमुख यानि प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल और डिवीजनल अध्यक्ष द्वारा अपने समग्र कार्यों और उत्तरदायित्वों के ही एक भाग के रूप में किए जाते हैं।

10.4 विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समय-समय पर बैठकें होती हैं और सी बी आई के साथ परामर्श करके संदेहास्पद अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। संदेहास्पद निष्ठा वाले राजपत्रित अधिकारियों की एक सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने पर अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

10.5 धोखाधड़ी के आठ बड़े मामलों की निदेशालय से प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा जांच की गई। मामलों की सूचना पुलिस/सी बी आई को दी गई। दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के अलावा लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की गई।

10.6 राजस्व की चोरी का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता दल द्वारा 58 कार्यालयों की आकस्मिक सतर्कता जांच की गई। कदाचार और राजस्व की चोरी रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त कार्यवाही की गई।

10.7 1.4.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के सतर्कता कार्यकलाप का सांख्यिकीय सार :

1. दंडित अधिकारियों की संख्या

(क) बड़ा दंड	अधिकारी :	8
	अन्य कर्मचारी :	109
(ख) छोटा दंड	अधिकारी :	2
	अन्य कर्मचारी :	103

2. जांच की गई और केन्द्रीय सतर्कता : 26
आयोग को भेजी गई रिपोर्टें
(सी बी आई मामलों को छोड़कर)
की संख्या

3. परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता
आयोग को भेजी गई सी बी आई
रिपोर्टों की संख्या : -

4. किए गए निरीक्षणों की संख्या : 11287



Chapter 10

VIGILANCE ACTIVITIES

10.1 While the primary responsibility for the maintenance of integrity and efficiency in the Department vests in the Secretary, Department of Posts, Deputy Director General (Vigilance) is the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Department. The CVO acts as the Special Assistant to the Secretary in all matters pertaining to vigilance and provides a link between the Department of Posts and the Central Vigilance Commission (CVC).

10.2 Besides dealing with vigilance cases, the CVO is also responsible for arranging regular and surprise inspections of sensitive spots as a part of preventive vigilance, review and streamline procedures which appear to afford scope for corruption or misconduct, initiate measures for prevention, detection and punishment of corrupt and other malpractices in the Department and its field offices.

10.3 The CVO is assisted by Director (Vig.), three ADsG and one Desk Officer at the Headquarter. At the Circle, Regional and Divisional levels, vigilance related functions are discharged by heads of these formations, viz. Principal Chief Postmasters General, Regional Postmasters General and Divisional Heads, as part of their overall duties and responsibilities.

10.4 Periodical meetings with CBI at various levels were held and agreed lists of suspected officers drawn up in consultation with CBI. Close watch has been kept on the listed officers. Instructions have also

been issued for preparation and maintenance of a list of Gazetted Officers of doubtful integrity.

10.5 Investigations by deputing officers from the Directorate were carried out in eight major cases of fraud. The cases were reported to Police/CBI. Disciplinary proceedings were initiated against the delinquents besides instituting criminal proceedings against the culprits.

10.6 Surprise visits were carried out in 58 offices through Central Checking Squad to detect leakage of revenue. Appropriate action was taken to prevent malpractices and leakage of revenue.

10.7 Statistical Summary of vigilance activities for the period 1.4.2000 to 31.3.2001 (including figures from attached and subordinate office) :

1.	Number of officers punished with		
(a)	Major penalty	Officers :	8
		Other staff :	109
(b)	Minor penalty	Officers :	2
		Other staff :	103
2.	Number of reports examined and sent to CVC (other than CBI cases)	:	26
3.	Number of CBI reports Referred to CVC for advice	:	nil
4.	Number of inspections Carried out	:	11287

अध्याय 11

अन्य कार्यकलाप

कर्मचारी संबंध

11.1 संगठनात्मक दक्षता तथा कर्मचारी के ऊंचे मनोबल हेतु विवादमुक्त औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए कर्मचारी संबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। विभाग का यह प्रयास रहा है कि कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ सद्भावपूर्ण और सार्थक संबंध बनाए रखे जाएं।

11.2 इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोसिएशन को मान्यता) नियमावली और अतिरिक्त विभागीय एजेंट (एसोसिएशन को मान्यता) नियमावली के अंतर्गत यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए पुनर्सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

11.3 विभिन्न सर्विस एसोसिएशनों/फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें/साक्षात्कार आयोजित किए गए। सचिव (डाक) ने सभी तीन फेडरेशनों के साथ विशेष बैठक की ताकि विभाग को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा शुरू की गई नई सेवाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके। एसोसिएशनों से इन योजनाओं के प्रचालन में पूरे मन से सहभागिता करने का अनुरोध किया गया।

11.4 विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक 5 दिसम्बर, 2000 से 18 दिसम्बर, 2000 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इस प्रकार संपूर्ण भारत में डाक सेवा अस्त-व्यस्त हो गई। तत्कालीन माननीय संचार मंत्री के साथ आपसी समझ/बातचीत के बाद फेडरेशनों/एसोसिएशनों द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई।

कर्मचारी कल्याण

11.5 डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य विभाग में कर्मचारी कल्याण, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलाप को विकसित करना, संगठित करना और उन पर समग्र पर्यवेक्षण करना है। इस प्रयोजन से बोर्ड सरकार से अंशदान प्राप्त करता है जिसमें कर्मचारियों से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान तथा अधीनस्थ संघटकों द्वारा आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप के माध्यम से प्राप्त संग्रहों द्वारा वृद्धि की जाती है।

11.6 कल्याण बोर्ड के कोषों का उपयोग छात्रवृत्ति प्रदान करने और बीमारी, मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने, विकलांग कर्मचारियों तथा उनके बच्चों की सहायता करने तथा अवकाश गृहों, मनोरंजन क्लबों तथा सामुदायिक केन्द्रों आदि का रखरखाव करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार से तीस मिलियन रुपए के कुल अंशदान की प्राप्ति हुई, कोष में से आंतरिक रूप से प्राप्त स्रोत सहित इसका उपयोग सामान्य कार्यकलाप के साथ-साथ गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्किल में भूकंप और बाढ़ग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया।

अवकाश गृह

11.7 कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभार्थ पहले से ही काम कर रहे 23 होलीडे होम के अतिरिक्त वर्ष के दौरान पंजाब सर्किल के चंडीगढ़ में एक नया अवकाश गृह खोला गया।

खेलकूद

11.8 वर्ष 2000-2001 के दौरान बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, कुश्ती, वालीबॉल, शतरंज और कैरम, क्रिकेट, एथलेटिक्स और साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबाल, बास्केटबाल तथा भारोत्तोलन/पावरलिफ्टिंग और सर्वश्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान एक सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया। विभाग के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

इन-हाउस पत्रिका-डाक पत्रिका

11.9 डाक पत्रिका डाक विभाग की तिमाही पत्रिका (एक संस्थागत पत्रिका) है जो द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाती है। यह विभाग के भीतर संवाद का एक सशक्त माध्यम है जो कर्मचारियों को विभाग की नीतियों, समस्याओं और विकासों से अवगत रखता है। यह पत्रिका विभागीय कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभाओं को उजागर करने का एक प्रभावी मंच भी है। राजभाषा स्वर्ण जयंती पर एक विशेष अंक हिंदी में प्रकाशित किया गया।



Chapter 11

OTHER ACTIVITIES

Staff Relation

11.1 Staff relations is reckoned as the most important means of maintaining conflict-free industrial relations for organisational efficiency as also for high degree of employee morale. The Department endeavored to maintain harmonious and meaningful relations with the Staff Unions/Associations of its employees.

11.2 During the period, the process of re-verification under the Central Civil Services (Recognition of Service Association), Rules and Extra Departmental Agents (Recognition of Association), Rules were initiated for recognition of the union.

11.3 Meetings/interview were held with the representatives of various service associations/federations. Secretary (Posts) had a special meeting with all the three federations to apprise them of the new services launched by the Department with an objective of making Department self sufficient. The associations were requested to extend wholehearted participation in operation of schemes.

11.4 The Department employees and Gramin Dak Sewaks went on indefinite strike from 5th December 2000 to 18th December, 2000, thus paralysing the postal service in the whole of India. The strike was withdrawn by the Federations/Associations after reconciliation/negotiation with the then Hon'ble Minister for Communications.

Staff Welfare

11.5 The main objective of the Postal Services Staff Welfare Board is to develop, organize and exercise overall supervision over staff welfare, sports and cultural activities in the Department. For this purpose, the Board receives contribution from the Government which is augmented by voluntary contributions from staff as well as the collections arranged by the subordinate formations through sports and cultural activities organized by them.

11.6 The funds of the Welfare Board are utilised for grant of scholarships and providing financial assistance in case of illness, death and natural calamities, helping handicapped employees and their children, and maintenance of Holiday Homes, Recreation Clubs and Community Centers etc. During the year 2000-2001, a total contribution of Rupees thirty million was received from the Government which along with the sources raised internally the fund was used to provide financial assistance to earthquake and flood affected employees in Gujarat, Orissa and West Bengal Circle, in addition to normal activities.

Holiday Homes

11.7 During the year, a new Holiday Home was opened at Chandigarh in Punjab Circle, in addition to the 23 Holiday Homes already functioning for the benefit of the employees and their families.

Sports

11.8 During the year 2000-2001, All India Postal Services Sports Tournaments in Badminton, Table Tennis, Hockey, Wrestling, Volleyball, Chess & Carrom, Cricket, Athletics & Cycling, Kabaddi, Football, Basketball and Weightlifting/Power lifting and Best Physique were organized. A cultural meet was also organized during the period. A number of sports persons from the Department participated in National/International Sports events.

In House Magazine- Dak Patrika

11.9 Dak Patrika is a quarterly magazine (In-house journal) of the Department of Posts, published bilingually. It is an effective medium of Intra-Departmental communications which keeps the employees informed about the policies, problems and developments in the Department. The magazine is also an effective platform for projecting the literary talent of the departmental employees. A special issue on Rajbhasha Swarnjayanthi was published in Hindi.

चिकित्सा सुविधाएं

11.10 विभाग अपने कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को बहुत महत्व देता है। यह 48 नगरों/शहरों में 56 डाक एवं तार औषधालय एवं 7 प्राथमिक उपचार केन्द्र चलाता है। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को भी इन औषधालयों से सुविधा प्रदान की जाती है। 2000-2001 के दौरान दवाइयों की कीमत सहित इन औषधालयों को चलाने में हुआ व्यय 28.62 करोड़ रुपए था। अन्य स्थानों पर जहां डाक एवं तार औषधालय नहीं हैं, वहां डाक विभाग के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों या प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंटों की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

अनुकम्पा नियुक्तियां

11.11 सेवा में रहते हुए विभागीय कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की मृत्यु होने पर और सेवारत कर्मचारियों की अशक्तता के कुछ मामलों में विभाग पात्र मामलों में संबंधित कर्मचारियों के परिवार के किसी एक सदस्य को सामान्य भर्ती नियमों में छूट देकर उचित श्रेणी में नौकरी प्रदान करता है।

सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व

11.12 दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, विभाग में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति के 52838, अनुसूचित जनजाति के 19734, 2676 भूतपूर्व सैनिक, 85 विकलांग भूतपूर्व सैनिक और 33125 महिला कर्मचारी थे। (सारणी सं. 18 व 19 देखें)

स्थापना

11.13 भारतीय डाक सेवा, समूह "क" (1964 बैच) के अधिकारी श्री बी.एन. सोम को सचिव, डाक विभाग के पद पर दिनांक 2 जुलाई, 2000 को नियुक्त किया गया।

11.14 भारतीय डाक सेवा, समूह "क" (1965 बैच) की अधिकारी श्रीमती अपर्णा मोहिले को सदस्य (आधारिक संरचना एवं वित्तीय सेवाएं) के बतौर पदोन्नत कर दिया गया।

11.15 भारतीय डाक सेवा समूह "क" के 3 एस ए जी अधिकारियों को वरिष्ठ उप महानिदेशक/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया। भारतीय डाक सेवा समूह "क" के जे ए जी के 21 अधिकारी एसएजी में पदोन्नत कर दिए गए।

11.16 44 अधिकारियों को जेटीएस समूह "क" में पदोन्नत कर दिया गया तथा एसटीएस समूह "क" के 10 अधिकारियों को जेएजी में पदोन्नत कर दिया गया।

11.17 भारतीय डाक सेवा समूह "क" के 9 प्रशिक्षुओं (सिविल सेवा परीक्षा 1998) का उनके प्रवेश प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया।

11.18 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा- 1999 के परिणामों के आधार पर भारतीय डाक सेवा समूह "क" में नियुक्ति का प्रस्ताव 16 उम्मीदवारों को जारी किया गया जिनमें से 15 उम्मीदवारों ने यह कार्यभार संभाल लिया है।

11.19 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 13 पदधारियों को डाक सेवा समूह "ख" में पदोन्नत किया गया।

11.20 104 पदधारियों को डाक सेवा समूह "ख" में पदोन्नत किया गया।

11.21 बिहार सर्किल में बेतिया में मुख्यालय सहित पश्चिम चम्पारण डाक डिवीजन का सृजन किया गया है।

11.22 तमिलनाडु सर्किल में माइलपुर उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर कर दिया गया है।

11.23 बिहार सर्किल में गया डिवीजन के अंतर्गत जहानाबाद उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर कर दिया गया है।

11.24 पश्चिम बंगाल सर्किल में कल्याणी उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर कर दिया गया है।

11.25 हरियाणा सर्किल में यमुना नगर उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर कर दिया गया है।

11.26 झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ नामक तीन नए डाक सर्किलों का सृजन किया गया है।

11.27 पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद डाक निरीक्षक, रेल डाक सेवा निरीक्षक और वर्दी निरीक्षक के संवर्गों को एक ही संवर्ग में विलय कर दिया गया। "डाक निरीक्षक" के सामूहिक संवर्ग के लिए संशोधित भर्ती नियम तैयार किए गए तथा अप्रैल, 2001 में अधिसूचित किए गए।

कार्य-अध्ययन

11.28 कार्य अध्ययन अनुभाग ने वीपी I, II, और III डेस्क; एसबी- III डेस्क; बीपी-I तथा II डेस्क का अध्ययन किया।

Medical

11.10 The Department attaches great importance to the provision of medical facilities to its employees and their family members. It runs 56 P&T dispensaries and 7 First-aid Centres in 48 cities/towns. The employees of the Department of Telecommunications are also served by these dispensaries. The expenditure incurred on the running of the dispensaries, including the cost of medicines during 2000-2001 was Rs. 28.62 crores. In other places where P&T dispensaries are not available, the employees avail the services of CGHS dispensaries or Authorised Medical Attendants.

Compassionate Appointments

11.11 In the event of the death of departmental officials and extra-departmental agents while in service, and in certain cases of invalidation of officials in service, the Department provides appointment in the appropriate category to a family member of the official concerned, in relaxation of normal recruitment rules in really deserving cases.

Representation of SCs & STs in Service

11.12 As on 31.3.2001 there are 52838 SC, 19734 ST, 2676 Ex-servicemen, 85 Disabled Ex-servicemen and 33125 Women employees in various grades in the Department. (see Table No. 18 & 19).

Establishment

11.13 Shri B.N. Som, an officer of IPoS Group 'A' (1964 batch) appointed as Secretary, Department of Posts on 2nd July 2000.

11.14 Smt. Aparna Mohile, an officer of IPoS Group 'A' (1965-batch) was promoted as Member (Infrastructure & Financial Services).

11.15 3 SAG officers of IPoS Group 'A' were promoted to the grade of Sr. DDG/CPMG. 21 officers of JAG of IPoS Group 'A' were promoted to SAG.

11.16 44 Officers were promoted to JTS Group 'A' & 10 officers of STS Groups 'A' were promoted to JAG.

11.17 9 Probationers of Indian Postal Service Group 'A' (Civil Service Examination - 1998) were given independent charge on their successful completion of induction training.

11.18 16 Candidates were issued offer of appointment to IPoS Group 'A' on the basis of the result of Civil Service Examination-1999 held by UPSC, out of which, 15 candidates have joined service.

11.19 13 officials were promoted to Postal Service Group 'B' through DPC.

11.20 104 officials were promoted to Postal Service Group 'B'.

11.21 West Champaran Postal Division with Headquarter at Bettiah in Bihar Circle has been created.

11.22 Mylapore Sub Post Office has been upgraded to Head Post Office in Tamilnadu Circle.

11.23 Jehanabad Sub Post Office has been upgraded to Head Post Office under Gaya Division in Bihar Circle.

11.24 Kalyani Sub Post Office has been upgraded to Head Post Office in West Bengal Circle.

11.25 Yamuna Nagar Sub Post Office has been upgraded to Head Post Office in Haryana Circle.

11.26 Three new Postal Circles viz. Jharkhand, Uttaranchal and Chhattisgarh have been created.

11.27 Consequent upon the acceptance of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission, the cadres of Inspectors of Post Offices, Inspectors of Railway Mail Service and Inspectors Uniforms were merged into a single cadre. Revised Recruitment Rules for the common cadre of 'Inspectors of Posts' were framed and notified in April, 2001.

Work Study

11.28 Work Study Section carried out the studies of VP-I, II and III Desks, SB-III Desk, BP-I and II Desks. The report about the evolution of norms for the sanction of the staff of various categories in Postal Training Centres of the Department has been issued.

विभाग के डाक प्रशिक्षण केन्द्रों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की मंजूरी के मानदंड तैयार करने के संबंध में एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है।

राजभाषा

11.29 केन्द्र सरकार की नीति के अनुसरण में विभाग सरकारी पत्राचार में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास कर रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुख्यालय और सभी अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रही है।

11.30 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक सर्किल वर्ष में कम से कम एक बार 'राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करने की योजना शुरू की गई। इस अवधि के दौरान उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश सर्किलों में राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सर्किलों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए गए। संसदीय राजभाषा समिति ने 12.9.2000 को पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, विजयवाड़ा, 13.9.2000 को मुख्य डाकघर, गुंटूर, 5.7.2000 को अधीक्षक डाकघर, लेह, 10.7.2000 को डाक विभाग, 21.9.2000 को डाकघर पंचमढ़ी, 25.9.2000 को मुख्य डाकघर, उज्जैन तथा 18.10.2000 को वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, औरंगाबाद के कार्यालय का निरीक्षण किया।

11.31 विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए "अखिल भारतीय डाक राजभाषा शील्ड योजना" शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, अपने-अपने क्षेत्र में हिंदी का अधिकतम कार्य करने के लिए क्षेत्र "क", "ख" और "ग" में स्थित तीनों सर्किलों में से प्रत्येक को प्रत्येक वर्ष तीन चल वैजयन्ती और 5,000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र "क" और "ग" में स्थित सर्किलों को क्रमशः 4,000/- रु. और 3,000/- रु. का द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

11.32 दिनांक 14 सितम्बर, 2000 को निदेशालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। डाक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड ने सरकारी कार्य में राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया। निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष गृह मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव और सचिव (डाक) के संदेश उप महानिदेशक (एमएमएण्डटीएस) द्वारा पढ़े

गए। निदेशालय में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2000 तक "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया।

11.33 भारतीय डाक और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 14 सितम्बर, 99 से 14 सितम्बर, 2000 तक राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। संपूर्ण अवधि के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक पत्रिका के राजभाषा विशेषांक के प्रकाशन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय डाक ने सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रोत्साहन देने में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार जीता।

जन शिकायत

11.34 वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग में जन शिकायत के 787601 मामले प्राप्त हुए और इस अवधि के दौरान 788650 मामलों का निपटान किया गया जिनमें पिछले वर्ष के कुछ मामले शामिल थे।

11.35 प्राथमिकता आधार पर शिकायतों का निपटान करने के उपाय वर्ष भर जारी रहे। सभी सर्किलों में प्रत्येक तिमाही में डाक अदालतें लगाई गईं। कुल 871 शिकायतों का निपटान किया गया। मनीआर्डर, पंजीकृत वस्तुओं और बचत बैंक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए।

11.36 वर्ष 2000-2001 के दौरान 22 और कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए। इस प्रकार 31.3.2001 तक देशभर में 204 ग्राहक सेवा केन्द्र कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं।

11.37 डाक विभाग का नागरिक चार्टर दिनांक 12.7.2001 को जारी कर दिया गया है।

11.38 डाक भवन, नई दिल्ली में दिनांक 12.7.2001 को एक जन शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की गई जिसमें चौबीसों घंटे फैक्स की सुविधा है तथा जिनमें शिकायतें टेलीफोन/फैक्स द्वारा की जा सकती हैं।

11.39 शिकायतों के निपटान की समय सीमा की पुनरीक्षा की गई तथा जन शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिए यह समय सीमा घटा दी गई है।

डाक भवन

11.40 2000-2001 के दौरान 206 स्टाफ क्वार्टर, 3 प्रशासनिक कार्यालय भवन और 45 डाकघर/मेल कार्यालय भवनों का निर्माण किया गया।

Official Language

11.29 In pursuance of the policy of the Central Government, the Department has been making sustained efforts to ensure the optimum use of Hindi in the official correspondence. To ensure the implementation of Official Language Act, 1963 and the Rules made thereunder, Official Language Implementation Committee is functioning in the headquarter as well as in all the subordinate offices.

11.30 With a view to ensure the progressive use of Hindi as Official Language, a scheme of organising RAJBHASHA SAMMELAN in every Circle, at least once a year was introduced. Rajbhasha Sammelans were organized in Orissa, Gujarat, Haryana and A.P. Circles during the period. Steps were also taken to solve the various difficulties faced by the Circles. The Committee of Parliament on Official Language carried out inspections of PMG Office Vijayawada on 12.9.2000, Head Post Office, Guntoor, on 13.9.2000, Supdt. of Post Offices Leh on 5.7.2000, Department of Posts on 10.7.2000, Post Office Panchmarhi on 21.9.2000, Head Post Office, Ujjain on 25.9.2000 and O/o the Sr. Supdt. of Post Offices, Aurangabad on 18.10.2000.

11.31 The Department has introduced an "AKHIL BHARTIYA DAK RAJBHASHA SHIELD YOJANA" for its subordinate offices. Under this scheme, three running shields and cash prize of Rs. 5,000/- are awarded every year to each of the three circles located in regions 'A', 'B' & 'C' for performing maximum work in Hindi in the respective region. Besides, second and third prize of Rs. 4,000/- and Rs. 3,000/- respectively are also awarded to Circles located in regions 'A' and 'C'.

11.32 Hindi Diwas was observed in the Directorate on 14th September, 2000. In a function held in Dak Bhawan, Member (I&FS), Postal Services Board emphasised the need for compliance of the provisions of OL Act and Rules made thereunder in official work. The messages of Home Minister, Cabinet Secretary and Secretary (Posts) were read out by DDG(MM&TS) before the officers and staff of the

Directorate. 'HINDI FORTNIGHT' was organized in the Directorate from 3rd Oct., to 17th Oct., 2000.

11.33 The Golden Jubilee year of Rajbhasha was observed by the India Post and its Subordinate Offices from 14th Sept., 99 to 14th Sept., 2000. During the entire period, various competitions and programmes were organised for promoting the use of Hindi including publication of RAJBHASHA VISHESHANK of Dak Patrika. The India Post won the IInd prize under Indira Gandhi Rajbhasha Shield Yojana for its outstanding work in the promotion of Hindi in the official work.

Public Grievances

11.34 During the year 2000-2001, the Department received 787601 cases of Public Grievances and a total of 788650 cases were settled during the same period which included some cases of the previous year.

11.35 Measures to resolve grievances on priority continued throughout the year. Dak Adalats were held in every quarter in all the Circles. A total of 871 grievances were settled. Special drives were also organised to focus attention on speedy settlement of complaints related to money orders, registered articles and Savings Bank Services.

11.36 22 more computerised Customer Care Centres were opened during the year 2000-2001. Thus, till 31-3-2001, 204 Customer Care Centres have been computerised all over India.

11.37 Citizen Charter of the Department of Posts was released on 12-7-2001.

11.38 A Public Grievance Cell, with 24 hours fax facility in which complaints could be made on telephone/fax was set up in Dak Bhawan, New Delhi on 12-7-2001.

11.39 Time limit for the settlement of complaints was reviewed and reduced to provide prompt settlement of public grievances.

Postal Buildings

11.40 During 2000-2001, 206 Staff Quarters, 3 Administrative Office Buildings and 45 Post Office/Mail Office Buildings were constructed.

अध्याय-12

पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यकलाप

12.1 सरकार के नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलाप के लिए विशेष पहल की है।

12.2 पहले संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक डाक सर्किल द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। परंतु क्षेत्र के सामरिक महत्व पर विचार करते हुए विकासात्मक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रीभूत करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पूर्ववर्ती सर्किल को दो स्वतंत्र डाक सर्किलों में द्विभाजित कर दिया गया। इसमें एक असम सर्किल है जो असम राज्य के साथ कोटमिनस है तथा दूसरा पूर्वोत्तर डाक सर्किल है जिसमें छः राज्य-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। प्रत्येक सर्किल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

12.3 असम डाक सर्किल में 3942 डाकघर हैं जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। प्रत्येक डाकघर औसतन 5653 की जनसंख्या को

तथा 19.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। पूर्वोत्तर डाक सर्किल का मुख्यालय शिलांग में है और इसके अधिकार क्षेत्र में कुल 2915 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर औसतन क्रमशः 78.85 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और 3076 की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराता है। चूंकि यह क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी है तथा जनसंख्या दूर-दूर फैली है इसलिए प्रति कि.मी. सेवित जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से ज्यादा है।

योजनागत कार्यकलाप

12.4 पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों को नौवीं योजना के दौरान और आगे बढ़ाया गया। नौवीं योजना के अंतर्गत वार्षिक योजनाओं के दौरान योजनागत कार्यकलापों के कुल व्यय की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ व्यय निम्नलिखित के अनुसार है:

तालिका 15 पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनागत व्यय (मिलियन रु. में)			
वार्षिक योजना	कुल योजना व्यय	पूर्वोत्तर में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत
1997-98	722.7	58.8	8.0%
1998-99	736.9	82.7	11.0%
1999-00	882.8	61.2	7.0%
2000-01	755.2	101.5	13.4%

2001-2002 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजनागत कार्यकलापों के लिए 142.6 मिलियन रुपये की राशि निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा 2000-2001 के दौरान इस क्षेत्र में किए गए प्रमुख विकासात्मक कार्यकलापों का राज्यवार ब्योरा निम्नानुसार है:

असम

12.5 राज्य में 30 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, 3 विभागीय उप डाकघर और 21 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर डाक सुविधाओं का और विस्तार किया गया। 2000-2001 के

दौरान 7 डाकघरों और एक मेल कार्यालय (तिनसुकिया) का आधुनिकीकरण किया गया। रंगीला रेल डाक सेवा में एक पंजीकरण छंटाई कार्यालय का कम्प्यूटीकरण किया गया है। नलबाड़ी स्थित ग्राहक सुविधा केन्द्र और गुवाहाटी स्थित डाक भंडार डिपो भी कम्प्यूटरीकृत किए गए। कम्प्यूटरीकरण की सुविधा बढ़ाते हुए 30 बहुद्देशीय काउंटर मशीनें, 8 वेरी स्माल अपचर टर्मिनल स्टेशन, 8 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किए गए। 2000-2001 के दौरान गुवाहाटी में एक ट्राजिंट मेल कार्यालय और सिलचर "एस" डिवीजन में एक हेड रिकार्ड कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया। 43 समूह "ग"



Chapter 12

DEVELOPMENT ACTIVITIES IN NORTH EAST

12.1 In accordance with the policy guidelines of the Government, the Department has taken special initiatives for developmental activities in the North Eastern region.

12.2 The whole of North Eastern region was earlier served by only one postal circle. However, considering the strategic importance of the region and to ensure focussed attention to the developmental activities, the erstwhile circle was bifurcated into two independent postal circles- namely the Assam Circle coterminus with the State of Assam and the North-East Postal Circle covering the six states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Each circle is under the administrative control of a Chief Postmaster General.

12.3 Assam Postal Circle, with its headquarter at

Guwahati, has a network of 3942 post offices. On an average, each post office serves a population of 5653 persons and an area of 19.88 sq. kms. North Eastern Circle with Headquarter at Shillong has within its jurisdiction a total of 2915 post offices. On an average each post office serves a population of 3076 persons and an area of 78.85 sq. kms respectively. Population served per kilometer is more than all India average on account of the fact that this circle is a predominantly hilly area and sparsely populated.

Plan Activities

12.4 The developmental programmes initiated during the previous years were continued further during the Ninth Plan. The expenditure in North Eastern region visa-a-vis the total expenditure for plan activities during the Annual Plans under the Ninth Plan is as follows:

TABLE 15			
PLAN EXPENDITURE IN NORTH EASTERN REGION			
(Rs. in million)			
Annual Plan	Total Plan Expenditure	Expenditure in North-East	% over total expenditure
1997-98	722.7	58.8	8.0%
1998-99	736.9	82.7	11.0%
1999-00	882.8	61.2	7.0%
2000-01	755.2	101.5	13.4%

During 2001-2002, an amount of Rs. 142.6 million has been earmarked for various plan activities in the North Eastern Region. The details of major developmental activities undertaken by the Department in the Region, during 2000-2001, state-wise are as follows:-

Assam

12.5 Postal facilities were further extended in the state by opening 30 EDBOs, 3 Departmental Sub post offices and 21 Panchayat Sanchar Sewa Kendras. 7

post offices and one mail office (Tinsukia) were modernised during 2000-2001. One Registration Sorting Office has been computerised at Rangila RMS. The Customer Care Centre at Nalabari and PSD at Guwahati were also computerised. Extending the facility of computerisation, 30 Multi Purpose Counter Machines (MPCMs), 8 Very Small Apperture Terminal (VSAT) stations, 8 extended Satellite Money Order stations were installed. One TMO at Guwahati and one HRO at Silchar 'S' division were computerised during 2000-2001. In-house training to 43 Group 'C' officials

कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण तथा 458 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स को विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 48 कर्मचारियों को फिलैटली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। 5 फिलैटली ब्यूरो कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं और 4 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर मुहैया कराए गए। 5 डाकघर भवनों और 2 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

अरुणाचल प्रदेश

12.6 दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया। 10 डाकघरों में बहुदेशीय काउंटर मशीनें लगाई गईं। एक वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन, 6 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किए गए। 12 समूह "ग" कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और 26 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स को विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण दिया गया। 44 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। 1 फिलैटली ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 2 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर मुहैया कराए गए। 16 कर्मचारियों को फिलैटली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मणिपुर

12.7 10 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किए गए। एक डाकघर और 6 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। 2000-2001 के दौरान 13 समूह "ग" कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स को विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण दिया गया। 97 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक फिलैटली ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 3 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर मुहैया कराये गए। 12 कर्मचारियों को फिलैटली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एक डाकघर और 6 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

मेघालय

12.8 मेघालय राज्य के 83 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में ढांचागत उपस्कर मुहैया कराए गए। इसके अलावा, 5 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किए गए। डाकघरों के लिए 10 बहुदेशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध कराई गईं। एक डाकघर भवन और 7 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है। एक समूह "क" अधिकारी और 14 समूह "ग" कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 77 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण और 43 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स

को विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक फिलैटली ब्यूरो को कम्प्यूटरीकरण किया गया और एक ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर मुहैया कराए गए। 14 कर्मचारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया। शिलांग में एक मेल मोटर सेवा वाहन उपलब्ध कराया गया। एक डाकघर भवन और 7 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

मिजोरम

12.9 राज्य में 1 डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया और 59 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में ढांचागत उपस्कर उपलब्ध कराए गए। आइजोल और लुंगलाई मार्ग पर मेल मोटर पर सेवा हेतु दो वाहन खरीदे गए। डाकघरों के लिए 10 बहुदेशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध कराई गईं। एक वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन और 1 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किए गए। 55 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 5 समूह "ग" कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स को विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक फिलैटली ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 2 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर उपलब्ध कराए गए, 8 कर्मचारियों को फिलैटली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक डाकघर भवन और एक स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया गया।

नागालैंड

12.10 राज्य में एक अतिरिक्त विभागीय डाकघर और 3 विभागीय उप डाकघर खोले गए। एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया और 63 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में ढांचागत उपस्करों का प्रावधान किया गया। एक वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन और 8 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर स्टेशन स्थापित किए गए। इसके अलावा, 65 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 22 समूह "ग" कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स को विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक फिलैटली ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 2 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर उपलब्ध कराए गए। 9 कर्मचारियों को फिलैटली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जन शिकायतों के निपटारे हेतु कोहिमा स्थित ग्राहक सुविधा केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण किया गया। एक डाकघर भवन और चार स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

and decentralised training to 458 EDBPMs was provided. 48 officials were imparted training under Philately. 5 Philatelic Bureaux have been computerised and 4 Bureaux were provided with Tools and Equipments. 5 Post Office buildings and 2 staff quarters were constructed.

Arunachal Pradesh

12.6 Two Extra Departmental Branch Offices (EDBOs) were opened. One Post Office was modernised. 10 Post Offices were provided with Multi Purpose Counter Machines (MPCMs). One Very Small Apperture Terminal (VSAT) station, 6 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) were installed. In service training was provided to 12 Group 'C' officials and decentralised training to 26 EDBPMs. 44 officials were imparted computer training. 1 Philatelic Bureau was computerised and 2 Bureaux were provided with tools and equipments. 16 officials have been imparted training in Philately.

Manipur

12.7 10 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) were installed. One post office and 6 staff quarters have been constructed. During 2000-2001, In-service training to 13 Group 'C' officials and decentralised training to 40 EDBPMs was provided. 97 officials were imparted computer training. One Philatelic Bureau was computerised and 3 Bureaux were provided with Tools and Equipments. 12 officials have been imparted training under Philately. One post office and 6 staff quarters were constructed.

Meghalaya

12.8 83 Extra-Departmental Post Offices (EDBOs) were provided with infrastructural equipments in the state of Meghalaya. Besides, 5 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) were installed. 10 Multi Purpose Counter Machines (MPCMs) were provided for Post Offices. One post office building and 7 staff quarters are being constructed. In-house training to one Gr. 'A' officer and 14 Group 'C' officials were imparted. Computer training to 77 officials and decentralised training to 43 EDBPMs was provided.

One philatelic bureau was computerised and one bureau was provided with tools and equipments. 14 officials were imparted training in Philately. One MMS vehicle was provided to Shillong. One post office building and 7 staff quarters were constructed.

Mizoram

12.9 One post office was modernised and 59 Extra-Departmental Post offices (EDBOs) were provided with Infrastructural equipments in the state. Two vehicles were purchased for MMS at Aizwal and Lunglai route. 10 Multi Purpose Counter Machines (MPCMs) were provided for Post Offices, One Very Small Apperture Terminal (VSAT) station and 1 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) were installed. 55 officials were imparted training in computer operations. In-service training to 5 Group 'C' officials and decentralised training to 40 EDBPMs was imparted. One Philatelic Bureau was computerised and 2 Bureau were provided with tools and equipments, 8 officials were imparted training in Philately. One Post Office building and one staff quarter building were constructed.

Nagaland

12.10 One Extra-Departmental Post Office (EDBO) and 3 DSOs were opened in the state. One Post Office was modernised and 63 EDBOs were provided with infrastructural equipments. One Very Small Apperture Terminal (VSAT) station and 8 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) were established. Further, 65 officials were imparted training in computer operations. In service training to 22 Group 'C' officials and decentralised training to 40 EDBPMs was imparted. One Philatelic Bureau was computerised and 2 Bureaux were provided with tools and equipments. 9 officials have been imparted training in Philately. One Customer Care Centre at Kohima was computerised for attending to Public Grievances. One Post Office building and four staff quarters building were constructed.

Tripura

12.11 7 Post Offices were provided with MPCMs and one Very Small Apperture Terminal (VSAT) station

त्रिपुरा

12.11 7 डाकघरों में बहुदेशीय काउंटर मशीनें लगाई गईं और एक वेरी स्माल अपचर स्टेशन और 3 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्र स्थापित किए गए, चार डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया। राज्य में 96 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में ढांचागत उपस्कर उपलब्ध कराए गए। अगरतला डाकघर के लिए एक वाहन (कैश वैन) खरीदा गया। इसके अलावा, 130 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 78 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण और 29 समूह “ग” कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक फिलैटली ब्यूरो का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 2 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर उपलब्ध कराए गए। 13 कर्मचारियों को फिलैटली के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। दो डाकघर भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए दो भवनों का निर्माण किया गया।

सिक्किम

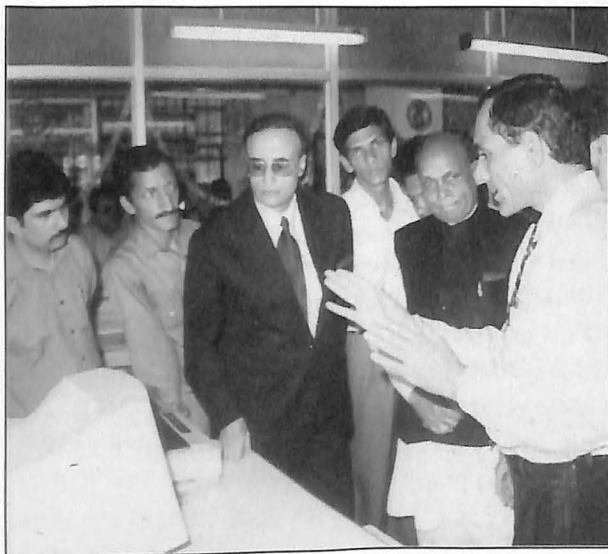
12.12 सिक्किम, पश्चिम बंगाल सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यह विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ अभिचिह्नित पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक भाग के रूप में भी शामिल किया गया। एक विभागीय उप डाकघर खोला गया। एक वेरी स्माल अपचर टर्मिनल स्थापित किया गया। 5 समूह “ग” कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक फिलैटली ब्यूरो को कम्प्यूटरीकरण किया गया है और 2 ब्यूरो में औजार एवं उपस्कर उपलब्ध कराए गए। 5 कर्मचारियों को फिलैटली के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।



and 3 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) were installed, four Post Offices were modernised. 96 Extra Departmental Branch Offices (EDBOs) were provided with infrastructural equipments in the state. One vehicle (cash van) was purchased for Agartala P.O. Further 130 officials have been imparted training in computer operations. Decentralised training to 78 EDBPMs and in service training to 29 Group 'C' officials was imparted. One Philatelic Bureau was computerised and 2 Bureaux were provided with tools and equipments. 13 officials have been imparted training under philately. Two Post Office buildings and two buildings for staff quarters were constructed.

Sikkim

12.12 Sikkim, which falls under the administrative control of West Bengal Circle also, comprises a part of the identified North Eastern Region for the purpose of developmental activities. One Departmental Sub post office was opened. One Very Small Apperture Terminal (VSAT) station was installed. In-service training to 5 Group 'C' officials and decentralized training to 25 EDBPMs was imparted. One Philatelic Bureau has been computerised and 2 Bureaux, were provided with tools and equipments. 5 officials have been imparted training under Philately.



सोलन में मुख्य डाकघर में कम्प्यूटर प्रचालन का प्रदर्शन देखते हुए प्रो. पी. के. धूमल, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश और श्री विजय भूषण, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश सर्किल।

Prof. P.K. Dhumal, Chief Minister of Himachal Pradesh, accompanied by Shri Vijay Bhushan, Chief Postmaster General, Himachal Pradesh Circle, seeing demonstration of computer operations in Solan, Head Post Office.

मैसूर स्थित डाक प्रशिक्षण केन्द्र में डाक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

International Training Programme on Information Technology in Postal Services held at Postal Training Centre, Mysore.



बाड़मेर डिवीजन के सर्वश्रेष्ठ पोस्टमैन का पुरस्कार लेते हुए श्री विरमा राम सरन, बाड़मेर मुख्य डाकघर, राजस्थान सर्किल।

Best Postman award for Barmer Division, being received by Shri Virma Ram Saran at Barmer Head Post Office, Rajasthan Circle.



भाग - II
PART - II

कार्यकलाप
ACTIVITIES

(अप्रैल-दिसम्बर 2001)
(April-December 2001)

भाग II

कार्यकलाप (अप्रैल-दिसम्बर 2001)

डाक नेटवर्क का विस्तार

1.1 संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2001-2002 के दौरान 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 50 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया। देशभर में पुनर्परिनियोजन द्वारा अब तक 196 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 39 विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए गए हैं। इनमें से 31.12.2001 तक 122 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 15 विभागीय शाखा डाकघर खोले जा चुके हैं।

मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

1.2 मेल प्रोसेसिंग के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत शामिल कार्यकलाप निम्नानुसार है :-

1. मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण
2. ट्राजिट मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण
3. पंजीकरण छंटाई का कम्प्यूटरीकरण
4. हेड रिकार्ड कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

1.3 वर्ष 2001-2002 के दौरान 17 मेल कार्यालयों को आधुनिकीकृत करने, जिसमें 2.5 मिलियन रु. का वित्तीय परिव्यय निहित है, के लक्ष्य की तुलना में 20 मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना निर्धारित किया गया है। इस काम को मार्च 2002 के पहले पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2001-2002 के दौरान 4 ट्राजिट मेल कार्यालयों के लक्ष्य की तुलना में 8 ट्राजिट मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसका वित्तीय परिव्यय 6.0 मिलियन रु. है। वार्षिक योजना 2001-2002 के दौरान 7 हेड रिकार्ड कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 7.0 मिलियन रुपये का वित्तीय परिव्यय नियत किया गया है। इस परियोजना को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूरा कर लिए जाने की आशा है।

फिलैटली

1.4 01.04.2001 से आगे की अवधि के दौरान छप्पन (56) स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए। फिलैटली सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप व्यक्तित्व आधारित डाक-टिकट, इन डाक-टिकटों की फिलैटलिक सार्थकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विषयपरक सेट में निकाले जा रहे हैं। विभाग ने निम्नलिखित शीर्षक से डाक-टिकटों का सेट जारी किया :-

1.5 06 जुलाई, 2001 को "स्वतंत्रता संघर्ष" (चार डाक-टिकटों का सेट) और 09 अक्टूबर, 2001 को "कविता एवं प्रदर्शन कला" (तीन डाक-टिकटों का सेट)।

1.6 इस अवधि के दौरान विभाग ने कला एवं संस्कृति, पादप एवं जन्तु जगत, विरासत आदि पर सुन्दर डाक-टिकटों को जारी किया जैसे मूंगों पर चार डाक-टिकटों का सेट, पंचतंत्र की कहानियों पर चार डाक-टिकटों का सेट। विभाग ने बधाई पर दो डाक-टिकटों के सेट और दिसम्बर 2001 में मन्दिर वास्तुकला पर चार डाक-टिकटों के सेट जारी किए।

1.7 वर्ष 2000 में विभाग द्वारा जारी किए गए सर्वाधिक लोकप्रिय डाक-टिकट का चयन करने के लिए डाक विभाग ने 1 से 15 नवंबर, 2001 तक डाक-टिकट लोकप्रियता मतदान का आयोजन किया।

1.8 डाक सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में देशभर में डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का सर्किलवार आयोजन किया गया। 15.12.2001 से 19.12.2001 के दौरान नासिक में एक राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी इनपेक्स- इम्परेपेक्स 2001 का आयोजन किया गया।

1.9 भारतीय डाक ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी में भाग लिया :

प्रदर्शनी का नाम	स्थान	अवधि
बेलजिका-2001	ब्रुसेल्स	09/06/2001 से 15/06/2001
फिला निप्पन	टोक्यो	01/08/2001 से 07/08/2001
हाफिना	डेनमार्क	16/10/2001 से 21/10/2001
मलेशिया डाक-टिकट मेला	क्वालालम्पुर	08/11/2001 से 17/11/2001



PART II

ACTIVITIES

(April - December 2001)

Expansion of Postal Network

1.1 Against a target of opening of 500 Extra Departmental Branch Post Offices (EDBOs) and 50 Departmental Sub Offices (DSOs) subject to availability of resources, during the year 2001-2002, so far 196 EDBOs and 39 DSOs have been sanctioned by redeployment throughout the country. Out of these, 122 EDBOs and 15 SOs have been opened upto 31.12.2001.

Computerisation of Mail Offices

1.2 The activities covered under Modernisation of Mail Processing are as under :

1. Modernisation of Mail Offices
2. Computerisation of TMOs
3. Computerisation of Registration Sorting
4. Computerisation of HROs

1.3 Against a target of modernising 17 Mail Offices with a financial outlay of Rs.2.5 million, 20 Mail Offices have been earmarked for modernisation during the year 2001-2002. The work is expected to be completed before March 2002. 8 TMOs as against a target of 4, with a financial outlay of Rs. 6.0 million are being computerised during the year 2001-2002. 7 Mail Offices have been identified for computerisation of Registration Sorting work with a financial outlay of Rs. 6.0 million. 7 HROs with a financial outlay of Rs. 7.0 million have been earmarked for computerisation during the annual plan 2001-2002. The project is expected to be completed before the end of the financial year.

Philately

1.4 During the period from 01.04.2001, fifty six (56) commemorative/special postage stamps have been issued. In accordance with the decision taken by the Philatelic Advisory Committee, personality based stamps are being brought out in thematic sets, to ensure philatelic relevance of these stamps. The Department released sets of stamps titled-

1.5 "The Struggle for Independence" (set of four stamps) on 06th July 2001 and "Poetry and Performing Arts" (set of three stamps) on 09th October 2001.

1.6 During the period, the Department released beautiful stamps on art & culture, flora & fauna, heritage etc. such as - set of four stamps on Corals, set of four stamps on Tales from Panchatantra. The Department is to release set of two stamps on Greetings and set of four stamps on Temple Architecture in December 2001.

1.7 A Stamp Popularity Poll was organised by the Department of Posts during 1 to 15 November, 2001 for selecting the most popular stamp issued by the Department in the year 2000.

1.8 Stamp design competition was held Circle-wise all over the country as a part of Postal Week celebration. INPEX-EMPIREPEX2001 a National Level Exhibition was held at Nashik during 15.12.2001 to 19.12.2001.

1.9 India Post has also participated in the following International Philatelic Exhibitions:

Name of the Exhibition	Place	Duration
Belgica-2001	Brussels	09/06/2001 to 15/06/2001
Phila Nippon	Tokyo	01/08/2001 to 07/08/2001
Hafina	Denmark	16/10/2001 to 21/10/2001
Malaysia Stamp Fair	Kuala Lumpur	08/11/2001 to 17/11/2001

व्यवसाय विकास

1.10 डाक विभाग ने विदेश मंत्रालय की भागीदारी में 5 मार्च, 2001 को स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा का शुभारंभ किया। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा का प्रमुख उद्देश्य देशभर में स्पीड पोस्ट केन्द्रों में पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों के प्रतिग्रहण की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना है।

1.11 स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा के अधीन विदेश मंत्रालय की ओर से चुनिंदा स्पीड पोस्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र स्वीकार किए जाते हैं। इस सेवा के दो प्रमुख संघटक हैं :-

(क) चुनिंदा स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर लिफाफों सहित पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों की बिक्री; और

(ख) भरे हुए पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों का प्रतिग्रहण और इन्हें आगे प्रोसेस करने हेतु पासपोर्ट कार्यालयों में इनका प्रेषण। इस सेवा के अधीन स्पीड पोस्ट कार्यालय पासपोर्ट प्रतिग्रहण कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार यह ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

1.12 भारतीय डाक ने बर्न, स्विटजरलैंड में डाक प्रचालन परिषद की 18 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2001 तक आयोजित हुए वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया।

1.13 भारत ने यूपीयू के उच्चस्तरीय दल की 7वीं एवं 8वीं बैठक में भाग लिया जो बर्न, स्विटजरलैंड में क्रमशः 29 अप्रैल से 02 मई, 2001 और 4 जुलाई से 6 जुलाई, 2001 तक आयोजित हुई। उच्चस्तरीय दल वरिष्ठ डाक अधिकारियों का एक फोरम है जिसे यूपीयू के भावी मिशन और संरचना पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है। भारत इस दल के 24 सदस्यों में से एक है।

1.14 भारत ने पेरिस, फ्रांस में 28 से 31 मई, 2001 तक आयोजित डाक स्वचलीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इसमें विभिन्न देशों की डाक प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित की गईं।

1.15 दूरसंचार तथा डाक पर भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की एक बैठक पेरिस, फ्रांस में 13 से 15, जून 2001 तक आयोजित की गई। इसमें डाटा बेस पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, पोस्टल कन्सल्टेंसी और विपणन प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

1.16 इस अवधि के दौरान सचिव (डाक) ने बंगलादेश के साथ परस्पर सहयोग में वृद्धि करने और इसे तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए 17 से 19 जुलाई, 2001 तक ढाका, बंगलादेश का दौरा किया।

1.17 इस अवधि के दौरान चीन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात के डाक प्रशासनों और उप महानिदेशक-आईबी, यूपीयू के चार उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया। परस्पर हित के मुद्दों पर विचार करने हेतु चीन जनवादी गणराज्य के राज्य पोस्ट ब्यूरो के उप पोस्टमास्टर जनरल मिस्टर तान जियाओवई के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18 से 24 जून, 2001 तक भारत का दौरा किया।

1.18 मिस्टर अब्दुला इब्राहिम अल डबूस, महानिदेशक संयुक्त अरब अमीरात डाक प्राधिकरण ने 24 जुलाई, 2001 को नई दिल्ली का दौरा किया। डाक क्षेत्र में परस्पर हित के मामलों खासकर भूतल तथा हवाई पार्सलों के लिए आवक लैंड दरों में कमी करने और पार्सलों की भार सीमाओं में बढ़ोतरी करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

1.19 ईरान डाक प्रशासन के मिस्टर अब्बास रियाही वफा, बोर्ड सदस्य एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी तकनीकी डिप्टी और मिस्टर मुहम्मद सईद रेजाई, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय ने परस्पर हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु 4 से 10 अगस्त, 2001 तक भारत का दौरा किया। प्रशिक्षण, डाक बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रौद्योगिकी और फिलैटली के क्षेत्र में चर्चा की गई। भारत के उपग्रह मनीआर्डर प्रौद्योगिकी को ईरान हस्तांतरित करने के विषय पर भी बात की गई।

1.20 एशियाई प्रशांत डाक यूनियन, जो एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के 28 देशों की एक सीमित यूनियन है, के कार्यों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने 3 से 8 सितम्बर, 2001 तक मनीला, फिलीपींस में आयोजित हुए एशियाई प्रशांत डाक प्रशिक्षण केन्द्र के शासी बोर्ड और एशियाई प्रशांत डाक यूनियन की कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया। भारतीय डाक ने एशियाई प्रशांत डाक प्रशिक्षण केन्द्र, बैंकाक की गुणवत्ता सेवा निधि पर कार्यशाला में भी भाग लिया।

1.21 सचिव (डाक) ने वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर डिवेलपमेंट ऑफ फिलैटली (डब्ल्यू ए डी पी) की ब्रुसेल्स में 10 जून से 12 जून, 2001 तक और लंदन में 15 से 17 सितम्बर, 2001 तक आयोजित हुई बैठक में भाग लिया। सचिव (डाक) डब्ल्यूएडीपी के अध्यक्ष हैं।

Business Development

1.10 Department of Posts, in partnership with Ministry of External Affairs launched Speed Post Passport Service on 5 March 2001. The primary objective of Speed Post Passport Service is to decentralize the acceptance of passport application forms to Speed Post Centres across the country.

1.11 Under Speed Post Passport Service passport applications forms are accepted at selected Speed Post Offices, on behalf of the Ministry of External Affairs. This service has two basic components:

- (a) Sale of Passport application forms along with envelopes at selected Speed Post Centres and,
- (b) Acceptance of filled up Passport application forms and despatch to Passport offices, for further processing. Under this service, Speed Post offices function as Passport Acceptance offices thus providing convenience to the customers.

International Relations

1.12 India Post attended the Annual Session of the Postal Operation Council, held at Berne, Switzerland from 18th April to 27th April, 2001.

1.13 India participated in the 7th and 8th meeting of the High Level Group of UPU held from 29th April to 2nd May, 2001 and 4th July to 6th July, 2001 respectively at Berne, Switzerland. The High Level Group, is a forum of senior postal officers, mandated to consider the future mission and structure of the UPU. India is one of the 24 members of the Group.

1.14 India attended the International Conference on Postal Automation held from 28th to 31st May, 2001 at Paris, France. It was an exhibition of postal technologies from various countries.

1.15 A meeting of Indo-French Joint Committee on Telecommunication and Posts was held at Paris, France from 13th to 15th June, 2001. The issues discussed pertained to Data Base Post, Express Post, Postal Consultancy and Marketing Training.

1.16 During the period Secretary (Posts) visited Dhaka, Bangladesh from 17th to 19th July, 2001 for

enhancing the mutual cooperation and providing technical assistance to Bangladesh.

1.17 During the period four high level delegations from Postal Administration of China, Iran, United Arab Emirates and Deputy Director General, IB, UPU visited India. A seven member Chinese delegation led by Mr. Tan Xiaowei. Deputy Postmaster General of the State Post Bureau of the People's Republic of China visited India from 18th to 24th June, 2001 to discuss matters of mutual interest.

1.18 Mr. Abdulla Ibrahim AI Daboos, Director General, United Arab Emirates Postal Authorities visited New Delhi on 24th July, 2001. Discussions were held on the matters of mutual interest in postal sphere especially regarding the reduction of inward land rates for surface and air parcels and raising the weight limit of parcels.

1.19 Mr. Abbas Reahy Vafa, member of the Board and Acting Technical Deputy of Managing Director and Mr. Mohammad Saied Rezaee, Head of International Relations office from the Postal Administration of Iran visited India from 4th to 10th August, 2001 to hold discussions on matters of mutual interest. Discussions were made in the field of training, technology for Postal Saving Banks Computerization and Philately. Discussion were also held on transfer of technology of Satellite Money Order of India to Iran.

1.20 India plays an important role in the affairs of the Asian Pacific Postal Union (APPU), a restricted Union comprising 28 countries of the Asian and the Pacific Region. India participated in the meeting of the Governing Board of the Asian Pacific Postal Training Centre (APPTC) and Executive Council of Asian Pacific Postal Union held from 3rd to 8th September, 2001 at Manila, Philippines. India Post also attended the workshop on Quality of Service Fund (QSF) at APPTC, Bangkok.

1.21 Secretary (Posts) attended the meeting of World Association for Development of Philately (WADP) at Brussels from 10th June to 12th June, 2001 at London from 15th to 17th Sept. 2001. Secretary (Posts) is the Chairman of the WADP.

1.22 भारत ने गुवर्नसें, यू.के. में 10 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2001 तक आयोजित राष्ट्रमंडल डाक प्रशासन (सीसीपीए) के 13वें सम्मेलन की बैठकों में भाग लिया। कुल तीस राष्ट्रमंडल डाक प्रशासनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। राष्ट्रमंडल डाक प्रशासन में इस पर चर्चा की गई कि विकासशील देशों में गुणवत्ता सुधार परियोजना के लिए यूपीयू की गुणवत्ता सेवा निधि का सर्वोत्तम और सम्पूर्ण संभव उपयोग कैसे किया जाए।

1.23 भारत-ईरान संयुक्त आर्थिक आयोग के ढांचे के अधीन डाक एवं दूरसंचार पर प्रथम भारत-ईरान कार्यदल की 30 से 31 अक्टूबर, 2001 को संचार भवन, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। सहयोग के क्षेत्र पर विचार-विमर्श करने के अलावा विभाग के प्रौद्योगिकी डिवीजन द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया।

1.24 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 29.10.2001 से 09.11.2001 तक पोस्टल स्टाफ कॉलज भारत, गाजियाबाद में कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुरुन्डी, वियतनाम, मंगोलया, इरिट्रिया, ईरान और केन्या के प्रतिभागियों को छह फैलोशिप प्रदान की गई।

1.25 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री मौस्सीबहौ मजाऊ ने 25 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2001 तक भारत का दौरा किया। इस सद्भावना दौरे के दौरान श्री मजाऊ ने दिल्ली, बंगलूर, मैसूर और हैदराबाद स्थित पोस्टल संस्थानों और डाक प्रशिक्षण केन्द्रों में भारतीय डाक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रौद्योगिकी प्रगति को देखने के लिए दौरा किया।

1.26 भारतीय डाक ने सिंगापुर में 29 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2001 तक आयोजित एशियाई प्रशांत डाक कोओपरेटिव प्रबंधन बोर्ड (एपीपीसीएमबी) की बैठक में भाग लिया। भारत इस बोर्ड का एक चयनित सदस्य है। एपीपीसीएमबी, एपीपी कोओपरेटिव कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने वाला एक नामित निकाय है।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक

1.27 पश्चिम बंगाल की सुश्री स्यानी सुर राय ने यूपीयू पत्रलेखन प्रतियोगिता में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार जीता है।

1.28 16 सितम्बर को 17वीं सार्क पत्रलेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें रिकार्ड संख्या में 4689 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

1.29 नवयुवकों के लिए यूपीयू और सार्क द्वारा आयोजित पत्र-लेखन प्रतियोगिता का उद्देश्य रचनात्मक कार्यों में उनकी योग्यता विकसित करना और अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री को सुदृढ़ता प्रदान करने में उनका योगदान लेना है।

1.30 मंत्रिमण्डल ने नेपाल और माल्टा के साथ मनीआर्डर सीमा में वृद्धि करना अनुमोदित कर दिया है। इस संबंध में संबंधित डाक प्रशासनों की पुष्टि होने के पश्चात आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

1.31 गुवाहाटी और मुरादाबाद स्थित निर्यात विस्तार काउन्टरों ने 1.1.2001 और 15.12.2001 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। निर्यात विस्तार काउन्टर अन्तर्राष्ट्रीय जावक डाक/पार्सल के लिए कस्टम समाशोधन सुविधाएं प्रदान करेगा। एनईपीजैड-नौएडा स्थित निर्यात विस्तार काउन्टर का आवक/जावक डाक/पार्सलों हेतु कस्टम समाशोधन सुविधाओं सहित 1.11.2001 से एनईपीजैड नौएडा स्थित उप विदेश डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ा दिया गया।

प्रौद्योगिकी

1.32 चालू वित्त वर्ष के दौरान बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क (एसबीएलएएन) सहित 1000 बहुदेशीय काउन्टर मशीनों की संस्थापना किए जाने की संभावना है। उपग्रह मनीआर्डरों (एसएमओ) के लिए 88 सूक्ष्म भू-केन्द्रों की संस्थापना की गई है। वर्ष के दौरान 400 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर (ईएसएमओ) और 100 इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनें संस्थापित करने की भी संभावना है। जनवरी 2002 से 31 मार्च, 2002 तक 20 डाक-टिकट विरूपण मशीनें भी लगाया जाना संभावित है।

1.33 विभाग ने 2.8.2001 को 'ई-पोस्ट' के नाम से एक नई ई-मेल सेवा की पायलट परियोजना शुरू की है। इस सेवा से विश्व के किसी भी भाग में रहने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को भी ई-मेल भेज सकता है जिसके पास कम्प्यूटर नहीं है। पायलट परियोजना के इस चरण में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं।

वित्तीय सेवाएं

1.34 भारत और विश्व भर में वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा डाकघर बचत बैंक के मौजूदा अधिदेश की पुनरीक्षा करने के लिए एक पांच सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति ने डाकघर बचत बैंक खूबियों और खामियों का गहन विश्लेषण

1.22 India participated in the meetings of the 13th Conference of Commonwealth Postal Administration (CCPA) held from 10th Sept. to 15th Sept. 2001 at Guernsey, U.K. A total of thirty Commonwealth Post Administrations were represented in the meeting. CCPA discussed how to make the best and fullest possible use of the UPU's Quality of Service Fund for quality improvement project in developing countries.

1.23 The meeting of the First Indo-Iran Working Group of Posts and Telecommunications under the frame-work of Indo-Iran Joint Economic Commission was held on 30th -31st Oct. 2001 at Sanchar Bhawan, New Delhi. Besides discussions on area of cooperation, presentation was also made by the Technology Division of the Department.

1.24 An Executive Development Programme was organized at Postal Staff College of India, Ghaziabad from 29.10.2001 to 09.11.2001 under the assistance in kind scheme of Universal Postal Union. Six fellowships were granted to participants from Burundi, Vietnam, Mongolia, Eritrea, Iran and Kenya.

1.25 Mr. Moussibahou Mazou, Deputy Director General of the International Bureau of Universal Postal Union visited India from 25th November to 1st December 2001. During this goodwill visit, Mr. Mazou visited Postal Installations and Postal Training Centres at Delhi, Bangalore, Mysore and Hyderabad to observe the technological advances made by India Post in various spheres.

1.26 India Post attended the Asian Pacific Post Cooperative Management Board (APP -CMB) meeting held at Singapore from 29th Nov. to 30th Nov. 2001. India is an elected member of the Board. The APP-CMB is the structure designated to supervise the activities of the APP Cooperative.

International Mails

1.27 Ms. Sayani Sur Roy of West Bengal has won the third prize at the International level in the 30th UPU Letter Writing Competition.

1.28 The 17th SAARC letter writing competition was held on 16th September in which a record number of

4689 entries were received.

1.29 The purpose of the letter writing competition conducted by UPU and the SAARC for young people is to develop their faculty in composition and to contribute to the strengthening of International friendship.

1.30 Cabinet has approved enhancement of M.O. limit with Nepal and Malta. Orders in this regard will be issued after getting confirmations from the respective Postal administrations.

1.31 The Export Extension Counter at Guwahati and Moradabad began working w.e.f. 1.1.2001 and 15.12.2001. The Export Extension will provide customs clearance facilities for international outward mails/parcel. The Export Extension Counter at any NEPZ-Noida was upgraded as a Sub Foreign Post Office at NEPZ Noida w.e.f. 1.11.2001, with customs clearance facilities for inward/outward mails/parcels.

Technology

1.32 During the current financial year, 1000 multipurpose counter machines including the S.B. LAN are likely to be installed. 88 Micro Earth Stations for Satellite Money Orders (SMO) have been installed. 400 Extended Satellite Money Order (ESMO) and 100 Electronic Franking Machines are also likely to be installed during the year. 20 Stamps Cancelling Machines are also likely to be installed during January 2002 to 31 March 2002.

1.33 A Pilot-project for a new e-mail service called "e-post" was launched by the Department on 2.8.2001. This service allows people from anywhere in the world to send e-mails to persons who do not have computers. In the pilot project phase, 5 States of Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Maharashtra & Goa have been covered.

Financial Services

1.34 In recognition of the changes taking place in the financial services sector in India as well as worldwide a five member Committee was constituted by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to review the existing mandate of the Post office Savings

किया। इस समिति ने विभिन्न शहरों में डाकघर बचत बैंक के ग्राहकों और चैम्बर्स आफ ट्रेड एंड कामर्स के भी विचार प्राप्त किए और इसके पश्चात समिति के निष्कर्षों को विधि मान्यता के लिए इस विषय पर परामर्श हेतु के पी एम जी को सौंपा गया।

1.35 सिफारिशों के आधार पर विभाग ने इसके द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सेवाओं की शृंखला में विविधता एवं विस्तार करने के लिए पहले ही निम्नलिखित कई कदम उठाए हैं :

(i) म्युचुअल फंडों का वितरण :

(ii) यू टी आई बैंक और आई डी बी आई बैंक के साथ सहमति ज्ञापन : हाल ही में विभाग ने यू टी आई बैंक और आई डी बी आई बैंक के साथ एक-दूसरे के ग्राहकों को निम्नलिखित मूल्यवर्द्धित सेवाएं मुहैया कराने की संभावनाओं का पता लगाने से एक सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं :-

(क) ए टी एम

(ख) नकदी प्रबंधन सेवाएं

(ग) सुगम ऋण सेवा

(घ) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल और अन्य का प्रयोग

(ङ) डाक विभाग की प्रीमियम सेवाएं

(iii) मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के साथ सहमति ज्ञापन : सितम्बर, 2001 में विभाग ने मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के साथ कार्ड आधारित भुगतान समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए। इस समय विभाग निम्नलिखित पर भी ध्यान दे रहा है :

(क) पूर्वदत्त कार्ड : जबकि भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड पहले ही मौजूद हैं, डाकघर देश में पूर्वदत्त कार्डों को प्रचलित करेगा। इस उत्पाद को जनसामान्य के लिए अभीष्ट माना जाता है क्योंकि वह क्रेडिट के प्रतिकूल है और यहां तक कि वह अधिकांश मामलों में क्रेडिट कार्डों का पात्र भी नहीं होता है।

(ख) डेबिट कार्ड : विभिन्न डाकघर बचत बैंक शाखाओं को जोड़ने के पश्चात डाकघर बचत बैंक खाताधारकों को स्वीकार्य मास्टर कार्ड लोगो वाले डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो उन्हें कारगर रूप से भुगतान की सुविधाएं प्रदान करेंगे और क्रेडिट कार्डधारकों को मर्चेन्ट स्थापनाओं और ए टी एम से नकदी आहरण उपलब्ध कराएंगे।

(ग) स्मार्ट कार्ड : पतों की पक्की जानकारी होने के कारण यह वास्तव में सत्यापन करने और डिजिटल रूप में पहचान करने के लिए अभीष्ट है। मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के साथ डाकघर बचत बैंक के सहयोग से डाकघर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देनों को सुगम बना सकेगा।

(घ) पूर्णरूपेण मुद्रा परिवर्तन : हाल ही में विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक से मुद्रा परिवर्तन करने संबंधी सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त किया है।

ई एफ टी इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारण प्रणाली के माध्यम से भौगोलिक अवस्थितियों को पार करके निधियों के अंतरण का कार्य करता है। विभाग का मौजूदा समर्पित देशव्यापी वी-सेट नेटवर्क उपलब्ध क्षमता के साथ यह सेवा प्रदान करता है। इसे विभाग ने अक्टूबर, 2001 से प्रारंभ किया है।

(iv) कर्मचारी प्रशिक्षण और निवेशक शैक्षिक कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्वेस्ट इंडिया इकोनामिक फाउंडेशन नामक एक निजी संस्था डाकघर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और विभाग द्वारा प्रस्तावित विभिन्न वित्तीय सेवाओं के संबंध में निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कारपोरेट की सहायता ली जाएगी। इस पर सरकार को कोई भी व्यय वहन नहीं करना पड़ेगा और यह सरकार कारपोरेट क्षेत्र के साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

डाक जीवन बीमा (पी एल आई)

1.36 वर्ष 2001-2002 के व्यावसायिक लक्ष्य तथा अप्रैल से दिसम्बर 2001 तक किया गया व्यवसाय तालिका सं. 16 में दिया गया है।

Bank. The Committee made an in depth analysis of the strengths and weaknesses of the POSB. It also solicited the views of the customers of the POSB as well as of the Chambers of Trade and Commerce in different cities and the findings of the Committee were thereafter put to validation by entrusting a consultancy on the subject to the KPMG.

1.35 Based on the recommendations, the Department has already taken a number of initiatives to diversify and expand the range of financial services provided by it including:

- (i) Distribution of Mutual Funds.
- (ii) **Memorandum of Understanding with the UTI Bank and IDBI Bank:-** The Department has recently signed a MOU with UTI Bank and IDBI Bank to explore the possibility of providing the following value added services to each other's customers:-
 - (a) ATMs
 - (b) Cash management services
 - (c) Easy loans
 - (d) Use of speed post, express parcel post and other
 - (e) Premium services of the Department of Posts.
- (iii) **Memorandum of Understanding with the MasterCard International:** In Sept., 2001 the Department signed a MOU with Master Card International to explore the possibility of introducing card based payment solutions. The department is currently looking at the following options:
 - (a) **Prepaid cards :-** While credit and debit cards already exist in India, the post office will pioneer prepaid cards into the country. This product is considered ideal for the common man who is credit averse and in most cases not even eligible for credit cards.

(b) **Debit cards :-** After connecting different POSB branches debit cards bearing the MasterCard acceptance logo shall be issued to POSB account holders which will effectively give them the facilities of payment and cash withdrawal available to credit card holders at merchant establishments and ATMs.

(c) **Smart Cards :-** By virtue of its intimate knowledge of addresses it is in fact ideally positioned to verify and provide digital identities. The POSB's alliance with MasterCard International shall enable the Post Office to facilitate domestic as well as international financial transactions.

(d) **Full-fledged money changing :-** The Department has recently received a license from the Reserve Bank of India to provide money changing services.

EFT implies the transfer of funds across the geographical locations, through electronic messaging systems. The Department's existing dedicated countrywide V-SAT Network provides it with ready capability to provide this service, which the department initiated in October 2001.

(iv) **Employee Training and Investor Education Programme:-** Under the programme a private organization called Invest India Economic Foundation will draw corporate support to train post office employees and educate investors on different financial services offered by the department. This will be done at no cost to the government and is a sterling example of government - corporate sector partnership.

Postal Life Insurance (PLI)

1.36 The Business targets for the year 2001-2002 and business secured from April to December 2001 is as given in Table No. 16:

तालिका 16

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय : 2001-2002

श्रेणी	लक्ष्य (मिलियन रु. में)	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2001 तक) पालिसियों की सं.	बीमित राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	19050	103526	9516.9
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	10960	94225	4419.3

1.37 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन बीमा के रूप में बचतों को जुटाना ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य को कारगर ढंग से कर सकें, इसके लिए ग्रामीण डाक सेवकों (जी डी एस) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इस वित्त वर्ष के दौरान अब तक 1,75,338 ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

1.38 वर्ष के दौरान अजमेर, जोधपुर, नागपुर और धारवाड़ क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य कम्प्यूटीकृत किया गया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अब तक 27 ग्रामीण डाक जीवन बीमा क्षेत्रीय कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण किया जा चुका है और निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता का कार्यालय विचाराधीन है।

1.39 वर्ष के दौरान डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पर वेबसाइट प्रारंभ की गई, अब भावी उपभोक्तागण हमारे उत्पादों के बारे में संबद्ध सूचना हमारी साइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंडियापोस्ट.ऑर्ग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थापना

1.40 निरीक्षण श्रेणी के 144 कर्मचारियों को डाक सेवा समूह "ख" में पदोन्नत कर दिया गया है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/वरिष्ठ उप महानिदेशक ग्रेड के एक अधिकारी श्री एस.बी.भट्टाचार्य को प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/वरिष्ठ उप महानिदेशक ग्रेड की एक अधिकारी श्रीमती आशा कुलकर्णी को प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है। एस ए जी ग्रेड के 5 अधिकारियों को वरिष्ठ उप महानिदेशक/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है। सिविल सर्विस परीक्षा-2000 के परिणाम के आधार पर 16 उम्मीदवारों

को भारतीय डाक सेवा समूह "क" में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है तथा सरकार द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वरिष्ठ निजी सहायक ग्रेड (अब निजी सचिव के बतौर पुनर्निर्दिष्ट) के 21 अधिकारियों को 6500-10500 रु. के वेतनमान से 7500-12000 रु. के प्रधान निजी सचिव के उन्नत वेतनमान में रखा गया है।

आंतरिक कार्य अध्ययन

1.41 कार्य अध्ययन यूनिट ने एससीटी सेल, डी ई ब्रांच, सी एण्ड ए अनुभाग, पी ए विंग के सी एण्ड ई का अध्ययन किया। 1 अप्रैल से दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के दौरान डाक प्रशिक्षण केन्द्रों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मंजूर करने के मानदंड तथा मेल मोटर सेवा में कुशल/अर्धकुशल और अकुशल कारीगरों के पदों को मंजूर करने के मानदंड तैयार किए गए।

1.42 पीए विंग के बुक-I और बुक-II, प्रशासन, जीए, भवन, ओ एंड एम, पीजी अनुभागों, सर्किलों में व्यवसाय डाक का प्रणाली अध्ययन (मास मेलिंग कार्य), एमबीसी (बल्क मेल केन्द्रों) में प्रचालन के आउटपुट मानदंडों और समय तत्वों के निर्धारण का अध्ययन तथा मुख्य डाकघरों के कोषागार शाखा के लिए मानदंडों का विकास करने हेतु कार्य अध्ययन भी मार्च 2002 के अंत तक किए जाने/पूरा किए जाने/प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

नई योजना ई पी एस- 1995 के अंतर्गत पेंशन का संवितरण

1.43 ईपीएस-1995 नामक नई योजना के अंतर्गत सभी विभागीय डाकघरों के माध्यम से ईपीएफओ के पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण करने हेतु डाक विभाग और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सहमति प्रदान कर दी है।

TABLE NO. 16
PLI/RPLI BUSINESS : 2001-2002

Category	Target (Rs. in million)	Achievement (Upto December 2001)	
		No. of Policies	Sum assured (Rs. in million)
PLI	19050	103526	9516.9
Rural PLI	10960	94225	4419.3

1.37 The mobilisation of savings as well as life insurance of people in Rural areas has been the hall mark of Rural Postal Life Insurance. To equip the RPLI manpower to undertake the task effectively in rural areas, a training programme was launched for the Gramin Dak Sewaks (GDS) and 1,75,338 GDS have been trained so far during this financial year.

1.38 Rural Postal Life Insurance work in Ajmer, Jodhpur, Nagpur and Dharwad Regional offices have been computerised during the year. 27 RPLI Regional Offices have been Computerised so far and office of Director, PLI, Kolkata is under consideration during this financial year.

1.39 Website on PLI and RPLI was launched during the year, prospective customers can now get relevant information about our products by visiting our site www.Indiapost.org.

Establishment

1.40 144 Inspectors' line official have been promoted to Postal Service Group 'B'. Shri S.B. Bhattacharya, an officer of CPMG/Sr. DDG grade has been promoted to the grade of Principal CPMG. Smt. Asha Kulkarni, an officer of CPMG/Sr. DDG grade has been promoted to the grade of Principal CPMG. 5 officers of SAG grade have been promoted to the grade of Sr. DDG/CPMG. 16 candidates have been issued offer of appointment to Indian Postal Service Group 'A' on the basis of result of Civil Service Examination-2000 and 21 officers of Sr. Personnel Assistant grade (now redesigned as Private Secretary) have been given placement from pay scale of Rs. 6500-10500/- to the up graded pay scale of Pr. Private Secretary of

Rs.7500-12000, in view of acceptance of the recommendations of Vth Pay Commission by the Govt.

Internal Work Study

1.41 Work Study Unit carried out the studies of SCT Cell, DE Branch, C&A Section, C&E of PA Wing. Evolution of norms for sanctioning of Staff of various categories for Postal Training Centres and Evolution of norms for sanctioning posts of skilled/semi-skilled and unskilled tradesmen in MMS during the period from 1st April to Dec., 2001.

1.42 Work Study of Book-I, Book-II of PA Wing, Admn., GA, Building, O&M, PG Sections, Method study of Business Post(Mass Mailing Work) in circles, study for evolution of output norms and time factors for operation in MBCs(Bulk Mail Centres) and also work study for evolution of norms for Treasury Branch of HOs are likely to be conducted/completed/ submitted by the end of March' 2002.

Disbursement of Pension under the new Schemes EPS - 1995

1.43 Department of Posts and Employees Provident Fund Organisation (EPFO) have agreed to disburse pension to the pensioners of the EPFO through all Departmental Post Offices under New Scheme called EPS-1995. The scheme has been launched with effect from 1st July, 2001.

Prime Minister National Relief Fund

1.44 For the cause of the victims of Gujarat earthquake contribution towards Prime Minister National Relief Fund through money orders and registered articles have

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

1.44 गुजरात भूकंप पीड़ितों के लिए मनीआर्डरों और पंजीकृत वस्तुओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिया गया अंशदान कमीशन और डाक प्रभार के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास

1.45 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान, पोस्टल स्टाफ कॉलेज, भारत, गाजियाबाद ने 6 प्रवेश और 15 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 381 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 94 अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। अनुमान है कि 1.1.2002 से 31.3.2002 तक कम्प्यूटर में 35 अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ अतिरिक्त 159 अधिकारियों को प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

1.46 पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिनांक 1.4.2001 से 31.12.2001 के दौरान कुल 8640 कर्मचारियों को सेवाकालीन और प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया। अनुमान लगाया जाता है कि चालू वित्त वर्ष यानी 1.1.2002 से 31.3.2002 की अवधि के दौरान अतिरिक्त 1927 कर्मचारियों को भी प्रवेश और सेवाकालीन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण

1.47 दिनांक 29.10.2001 से 09.11.2001 तक एक अंतर्राष्ट्रीय ईडीपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें भारत से 7 अधिकारियों के साथ-साथ केन्या, वियतनाम, मंगोलिया, इरेट्रिया तथा बुरुंडी से एक-एक अधिकारी ने भाग लिया।

1.48 डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर में दिनांक 13.08.2001 से 24.08.2001 तक दूरवर्ती शिक्षा तथा सीबीटी पर एक यूपीयू कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न देशों के 14 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

1.49 डाक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जनवरी, 2002 से शुरू हुआ जो 16 फरवरी, 2002 तक चलेगा।

कार्यस्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं

1.50 पांच क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों और 33 सीटीएल द्वारा 1.4.2001 से 31.12.2001 के दौरान कुल लगभग 7500 कर्मचारियों

को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुमान है कि 1.1.2002 से 31.03.2002 की अवधि के दौरान लगभग 3000 और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कर्मचारी संबंध

1.51 अवधि के दौरान विभाग ने स्टाफ यूनियनों/एसोसिएशनों और इसके कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं-सार्थक संबंध बनाने का प्रयास किया।

1.52 माननीय संचार मंत्री ने तीन डाक फेडरेशनों और उनकी सम्बद्ध संस्थाओं के साथ 23.10.2001 को बैठक की और उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। सचिव (डाक) की अध्यक्षता में तीन डाक फेडरेशनों और समूह "ग" और समूह "घ" तथा पोस्टमैन की सम्बद्ध यूनियनों के मध्य ई-पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, प्रमाणन प्राधिकरण और वी-सेट जैसी नई सेवाओं के मुद्दों पर 5 अक्टूबर 2001 को एक विशेष बैठक हुई।

1.53 सदस्य (कार्मिक) और सदस्य (आई एण्ड एफएस) ने राष्ट्रीय श्रम आयोग के साथ इस विभाग के सदस्यों में श्रमिक कानूनों, विशेष रूप से उदारीकरण के संबंध में चर्चा करने के लिए 24.7.2001 को बैठक की।

स्टाफ कल्याण

1.54 डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण, खेल-कूद, और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसार, विकास और आयोजन करना है। बोर्ड इस प्रयोजन हेतु भारत के समेकित कोष से अंशदान, कर्मचारियों से स्वैच्छिक अंशदान तथा खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्राप्त संग्रह जिनका आयोजन अधीनस्थ संघटकों द्वारा भी किया जाता है, अपने कोष प्राप्त करता है।

1.55 कल्याण बोर्ड के कोषों का उपयोग खेलकूद, मनोरंजन क्लबों, बीमारी, मृत्यु और प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में वित्तीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, आमोद यात्राओं के लिए आर्थिक सहायता, विकलांग कर्मचारियों तथा उनके संतानों की सहायता करने के लिए अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा शिशुसदन आदि चलाने जैसे कार्यक्रमों के लिए किया जाता है।

1.56 वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार से 35 मिलियन रुपये का कुल अंशदान प्राप्त हुआ। कोष द्वारा आंतरिक रूप से इकट्ठा किए गए स्रोतों के साथ इसका उपयोग सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

been exempted from payment of commission and postage charges.

Human Resource Development

1.45 During the period under review, the Postal Staff College of India, Ghaziabad conducted 6 Induction and 15 In-service training programmes, in which 381 officers participated. Besides, 94 officers were imparted training in computers during the period. It is anticipated that an additional 159 officers would be imparted Induction and In-service training including 35 officers in computers from 1.1.2002 to 31.3.2002.

Regional Postal Training Centres

1.46 A total number of 8640 officials were imparted In-service and induction training during 1.4.2001 to 31.12.2001 by the five Regional Training Centres. It is anticipated that an additional number of 1927 officials would also be imparted training in Induction and In-service programmes during the period of current financial year i.e. 1.1.2002 to 31.3.2002.

Training for Foreign Participants

1.47 An International EDP programme was organized from 29.10.2001 to 09.11.2001 with participation of one officer each from Kenya, Vietnam, Mongolia, Eritrea and Burundi along with 7 officers from India.

1.48 An UPU Workshop on Distance Learning and CBT with participation of 14 candidates from different countries was held at *Postal Training Centre, Mysore* from 13-08-2001 to 24-08-2001.

1.49 The international training programme on information technology in postal services commenced on 7th Jan 2002 and would continue till 16th Feb.2002.

Work Place Computer Training Facilities

1.50 A total number of about 7500 officials were imparted training on computers during 1-4-2001 to 31-12-2001 by the five Regional Postal Training Centres & 33 CTLs. It is anticipated that an additional number of about 3000 officials would also be imparted training during the period 1-1-2002 to 31-03-2002.

Staff Relations

1.51 During the period, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with staff Unions/Associations of its employees.

1.52 The Hon'ble Minister of Communications Information Technology met the three Postal Federations and their affiliates on 23.10.2001 and discussed their problems in brief. A special meeting was held under the Chairmanship of Secretary (P) with the three Postal Federations and their affiliated Unions of Group 'C' and Group 'D' & Postmen on 5th October, 2001 on the issue of new services like e-post, e-bill Post, Certifying Authority and VSAT.

1.53 Member (P) and Member (I&FS) had a meeting with the National Commission on Labour on 24.7.2001 to discuss Labour Laws having bearing on this Department, particularly in the context of liberalisation.

Staff Welfare

1.54 The objective of the Postal Services Staff Welfare Board is to promote, develop and organize Welfare Sports and Cultural activities for the employees of the Department. The Board receives its funds from contribution for this purpose from the Consolidated Fund of India, voluntary contribution from the staff and collection through sports and cultural activities are also arranged by the subordinate formations.

1.55 The funds of the Welfare Board are utilized for activities like sports, recreation clubs, financial assistance in cases of illness, death and natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips, grants to help handicapped staff and their children, vocational training centres and creches etc.

1.56 During the year 2001-2002, a total contribution of Rs.35 million was received from the Govt. which along with the sources raised internally by the Fund is being used in addition to normal activities to provide financial assistance in cases of natural calamities.

Holiday Home

1.57 During the year one new holiday home has been opened at Digha in West Bengal Circle, in addition to

अवकाश गृह

1.57 वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सर्किल के दीघा में एक नया अवकाश गृह खोला गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ हेतु 24 अवकाश गृह पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

खेलकूद

1.58 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2001 तक की अवधि के दौरान टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, सर्वश्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव बास्केटबाल, हॉकी और कुश्ती की अखिल भारतीय डाक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 1.1.2002 से 31.3.2002 तक की अवधि के दौरान कबड्डी, क्रिकेट, फुटबाल, बैडमिंटन, वालीबॉल, शतरंज और कैरम तथा एथलेटिक्स एवं साइक्लिंग की अखिल भारतीय डाक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

राजभाषा

1.59 संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 21.05.2001 को पोस्टमास्टर जनरल, औरंगाबाद का कार्यालय, 06.06.2001 को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर-पूर्व सर्किल शिलांग का कार्यालय,

17.07.2001 को उप डाकघर मनाली, 18.07.2001 को मुख्य डाकघर कोलांग, 27.09.2001 को पोस्टमास्टर जनरल, जोधपुर का कार्यालय, 29.09.2001 को जीपीओ जामनगर, 01.10.2001 को पोस्टमास्टर जनरल, राजकोट का कार्यालय, 06.11.2001 को अगाती डाकघर और 07.11.2001 को सब पोस्टऑफिस कवरत्ती के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवधि के दौरान 10 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

1.60 प्रस्ताव है कि "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित उन सर्किलों को "अखिल भारतीय राजभाषा शील्ड योजना" के अंतर्गत 'राजभाषा शील्ड' और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएं जिन्होंने वर्ष 1999-2000 के दौरान हिन्दी में सबसे अधिक कार्य किया है।

1.61 दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को निदेशालय में हिन्दी दिवस मनाया गया। दिनांक 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2001 तक निदेशालय में "हिन्दी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त उप महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवधि के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक सरकारी कार्य किया गया। राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष तथा हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सदस्य (कार्मिक) ने नकद पुरस्कार प्रदान किए।



24 holiday homes already functioning for the benefit of employees and their families.

Sports

1.58 During the period from 1st April to 31st December 2001 All India Postal Sports Tournaments in Table Tennis, Weightlifting, Power-lifting, Best Physique, Basketball, Hockey and Wrestling have been organized. In addition, a cultural meet was also organized. During the period from 1.1.2002 to 31.3.2002, All India Postal Sports Tournaments in Kabaddi, Cricket, Football, Badminton, Volleyball, Chess, Carrom, Athletics and Cycling would be organized.

Official Language

1.59 The Committee of Parliament on Official Language carried out inspection of PMG office Aurangabad on 21-05-2001, Office of the CPMG North-East Circle, Shillong on 06-06-2001, Sub PO Manali on 17-07-2001, HPO Kaylang on 18-7-2001, PMG office Jodhpur on 27-09-2001, GPO Jamnagar

on 29-09-2001, PMG office Rajkot on 01-10-2001, Agati Post Office on 06-11-2001 and office of the SPO Kawarathi on 07-11-2001. 10 Subordinate Offices were inspected during the period.

1.60 It is proposed to present "RAJBHASHA SHIELDS" and cash awards to the circles located in regions "A", "B" and "C" which have done their maximum work in Hindi during the years 1999-2000 under the "Akhil Bhartiya Dak Rajbhasha Shield Yojana",

1.61 Hindi Diwas was observed in the Directorate on 14th September 2001. "HINDI FORTNIGHT" was organized in the Directorate from 14th September to 28th September 2001. Besides other officials, Sr. officer of the DD'sG level took part in various competitions during Hindi fortnight with enthusiasm. Maximum official work was done in Hindi during that period. Member (P) gave away the cash prizes to the winners of various competitions conducted during the observation of Golden Jubilee Year of Official Language and Hindi Fortnight.

तालिका 17

6.2.2002 की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बकाया पैराओं का ब्यौरा

सी एवं एजी रिपोर्ट की संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	विषय
1997 की सं. 7	3.1	उपग्रह मनीआर्डर योजना
1999 की सं. 6	59	1.19 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि
1999 की सं. 6	62	डाकघर के लिए भूमि अधिग्रहण करने में असफल होना
2001 की सं. 6	45.4	डाक परियात
2001 की सं. 6	45.6	मूल्यवर्धित सेवाएं
2001 की सं. 6	47.5.1	वित्तीय निष्पादन
2001 की सं. 6	47.5.2	वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धि
2001 की सं. 6	47.6.1.1	डाकघरों में कम्प्यूटर आधारित एमपीसीएम की संस्थापना
2001 की सं. 6	47.6.1.2	एमपीसीएम की संस्थापना न होने के कारण हुई हानि
2001 की सं. 6	47.6.1.3	दोषपूर्ण एम पी सी एम की आपूर्ति
2001 की सं. 6	47.6.2.1	उपग्रह मनीआर्डर योजना-वी-सेटों की संस्थापना
2001 की सं. 6	47.6.2.1.1	प्रौद्योगिकी का चयन
2001 की सं. 6	47.6.2.1.2	प्रणाली का कम उपयोग और प्रत्याशित बचतों को प्राप्त न कर पाना
2001 की सं. 6	47.6.2.1.3	विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर प्रणाली की संस्थापना में विलंब
2001 की सं. 6	47.6.2.1.4	युग्मन कार्य पर कार्रवाई न करना
2001 की सं. 6	47.6.3.1	ई एफ एम के निष्पादन में अनियमितताएं
2001 की सं. 6	47.6.3.2	आपूर्तिकर्ता को परिहार्य अधिक भुगतान
2001 की सं. 6	47.7.1	कम्प्यूटरीकृत ट्रांजिट मेल कार्यालयों का कार्यनिष्पादन
2001 की सं. 6	47.7.2	13.74 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय
2001 की सं. 6	48	2.96 करोड़ के राजस्व की कम उगाही
2001 की सं. 6	49	ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों के मूल्य की वसूली न होना
2001 की सं. 6	50(i)	जिन ग्राहकों ने "अभी बुक करें भुगतान बाद में करें" योजना का लाभ उठाया था, उनसे देय राशि की वसूली न होना
2001 की सं. 6	51	बने बनाए क्वार्टरों का अधिग्रहण न करना और परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध होना।
2001 की सं. 6	52	अन्य विभागों की ओर से पेंशन/भविष्य निधि के रूप में प्रदत्त 15.04 करोड़ रुपये की वसूली न होना।

TABLE 17
DETAILS OF OUTSTANDING PARAS IN REPORT OF COMPTROLLER & AUDITOR
GENERAL OF INDIA AS ON 6.2.2002

C&AG Report No. & Year	Para No.	Subject
No. 6 of 1997	3.1	Satellite Money Order Scheme
No. 6 of 1999	59	Loss of Revenue of Rs. 1.19 crore
No. 6 of 1999	62	Failure to acquire land for Post Office
No. 6 of 2001	45.4	Postal Traffic
No. 6 of 2001	45.6	Value Added Services
No. 6 of 2001	47.5.1	Financial Performance
No. 6 of 2001	47.5.2	Physical targets and achievement
No. 6 of 2001	47.6.1.1	Installation of computer bases MP CMs in Pos
No. 6 of 2001	47.6.1.2	Loss due to non installation of MPCMs
No. 6 of 2001	47.6.1.3	Supply of defective MPCMs
No. 6 of 2001	47.6.2.1	Satellite Money Order Scheme-installation of VSATs
No. 6 of 2001	47.6.2.1.1	Selection of Technology
No. 6 of 2001	47.6.2.1.2	Under utilisation of the system & failure to achieve anticipated savings
No. 6 of 2001	47.6.2.1.3	Delay in installation of ESMO System
No. 6 of 2001	47.6.2.1.4	Non handling of pairing work
No. 6 of 2001	47.6.3.1	Irregularities in execution of EFMs
No. 6 of 2001	47.6.3.2	Avoidable excess payment to the supplier
No. 6 of 2001	47.7.1	Performance of computerised Transit Mail Offices (TMOs)
No. 6 of 2001	47.7.2	Irregular expenditure of Rs. 13.74 crore
No. 6 of 2001	48	Short realisation of revenue of Rs. 2.96 crore
No. 6 of 2001	49	Non recovery of value of British Postal Orders
No. 6 of 2001	50(i)	Non realisation of dues from customers who availed "Book Now Pay Later" Scheme
No. 6 of 2001	51	Non taking of possession of ready built quarters & resultant blocking of funds
No. 6 of 2001	52	Non recovery of Rs. 15.04 crore paid as pension/FP on behalf of other Departments

तालिका 18

31.3.2001 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

ग्रुप	अनुसूचित जाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत
ग्रुप "क"	84	10.33	36	4.43
ग्रुप "ख"	260	13.51	74	3.84
ग्रुप "ग"	41490	18.15	15736	6.88
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	10192	19.89	3829	7.47
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी)	812	77.63	59	5.64

तालिका 19

31.3.2001 को भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और महिला कर्मचारियों की संख्या

ग्रुप	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग भूतपूर्व सैनिक	महिला
ग्रुप "क"	1	-	81
ग्रुप "ख"	2	-	136
ग्रुप "ग"	2218	61	27576
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	454	23	4961
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी)	1	1	371

TABLE 18

NUMBER OF EMPLOYEES: SCHEDULED CASTES/TRIBES AS ON 31.3.2001

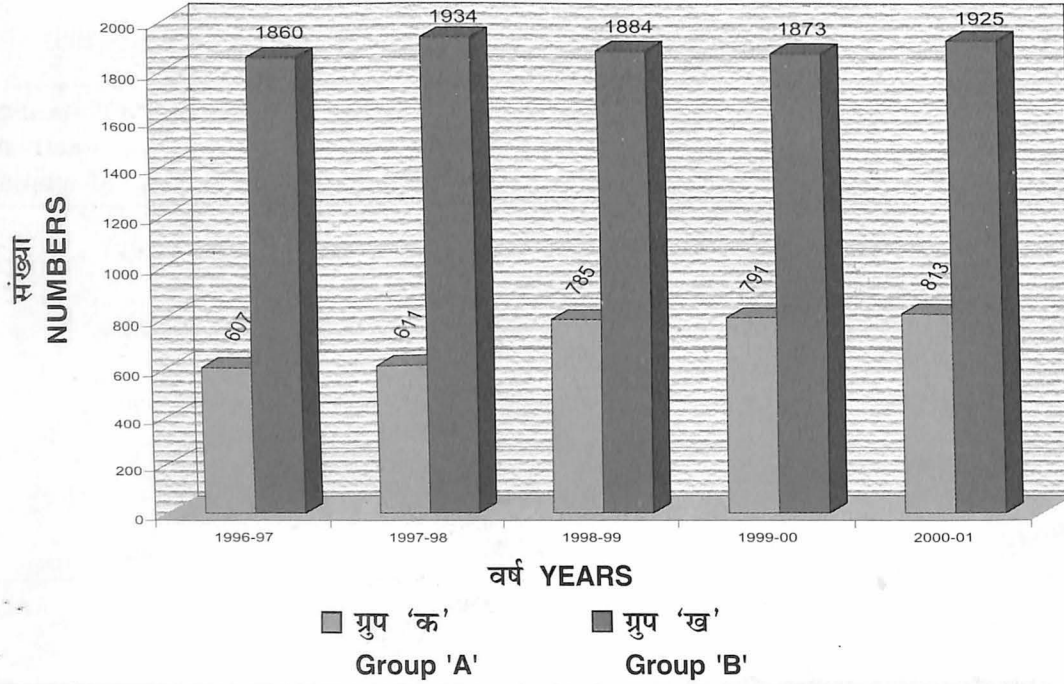
Group	Scheduled Percentage to Castes total number of employees		Scheduled Percentage to Tribe total number of employees	
Group 'A'	84	10.33	36	4.43
Group 'B'	260	13.51	74	3.84
Group 'C'	41490	18.15	15736	6.88
Group 'D' (Excluding Sweeper)	10192	19.89	3829	7.47
Group 'D' (Sweeper)	812	77.63	59	5.64

TABLE 19

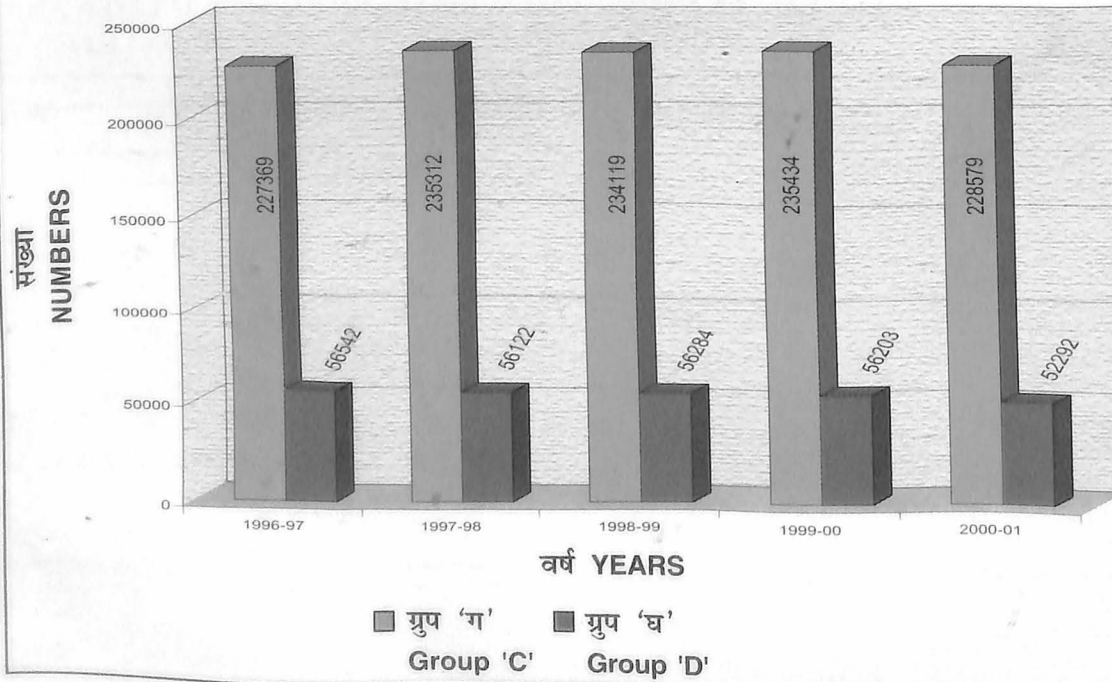
**NUMBER OF EMPLOYEES: EX-SERVICEMEN, DISABLED EX-SERVICEMEN AND
WOMEN AS ON 31.3.2001**

Group	Ex-servicemen	Disabled Ex-servicemen	Women
Group 'A'	1	-	81
Group 'B'	2	-	136
Group 'C'	2218	61	27576
Group 'D' (excluding Sweeper)	454	23	4961
Group 'D' (Sweeper)	1	1	371

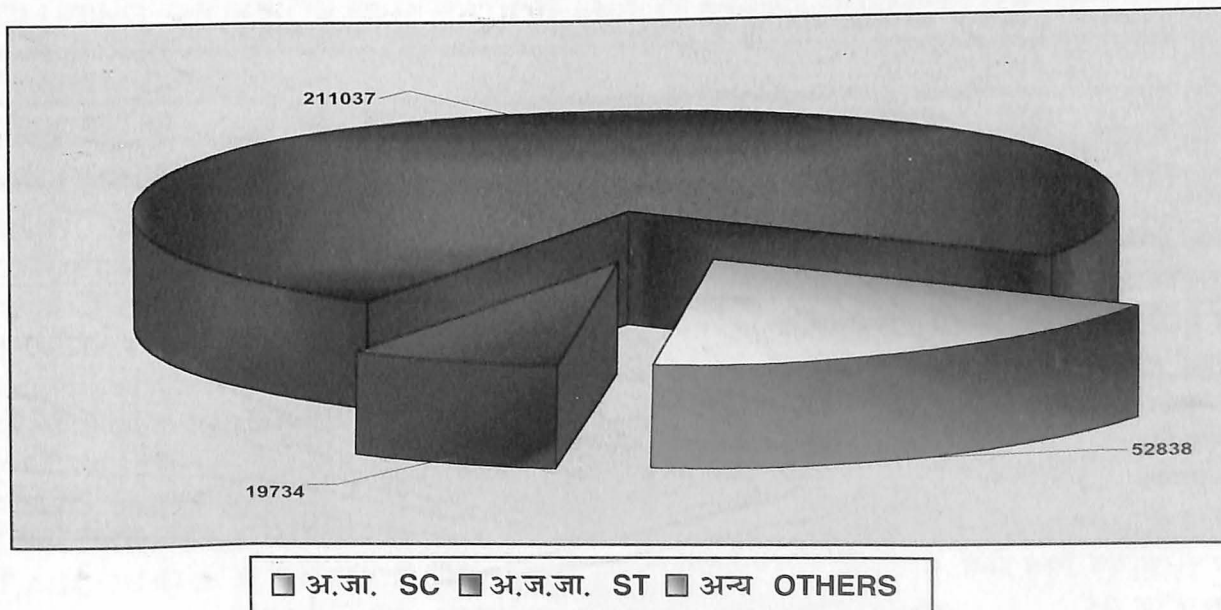
राजपत्रित अधिकारी
GAZETTED STAFF



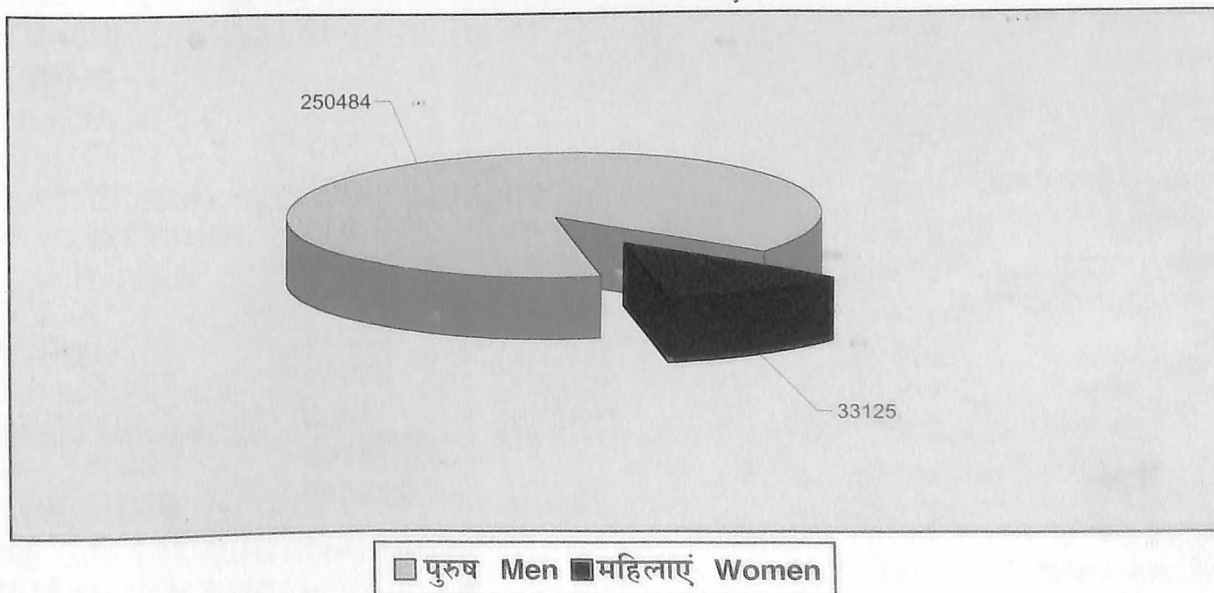
अराजपत्रित कर्मचारी
NON-GAZETTED STAFF



31-3-2001 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी (विभागीय)
SC/ST EMPLOYEES AS ON 31.3.2001 (DEPARTMENTAL)



31-3-2001 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारी (विभागीय)
WOMEN EMPLOYEES AS ON 31.3.2001 (DEPARTMENTAL)



तालिका 20

कार्मिक : 31.3.2001 को वास्तविक संख्या

(विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण पर गए कार्मिकों सहित)

क. विभागीय			
राजपत्रित	ग्रुप "क"	ग्रुप "ख"	कुल
भारतीय डाक सेवा समूह "क"			
सचिव (डाक)	1	-	1
सदस्य, डाक सेवा बोर्ड	3	-	3
प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	2	-	2
वरिष्ठ उप महानिदेशक/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	23	-	23
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	73	-	73
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	138	-	138
वरिष्ठ समयमान	79	-	79
कनिष्ठ समयमान	200	-	200
डाक सेवा ग्रुप "ख"	-	829	829
डाक-तार लेखा एवं वित्त सेवा			
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1	-	1
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	10	-	10
वरिष्ठ समयमान	24	-	24
कनिष्ठ समयमान	19	-	19
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	-	230	230
सहायक लेखा अधिकारी	-	565	565
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	14	59	73
सिविल विंग			
मुख्य अभियंता	2	-	2
अन्य	57	175	232
अन्य सामान्य केन्द्रीय सेवाएं	167	67	234
कुल (राजपत्रित)	813	1925	2738
अराजपत्रित			
निदेशालय	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"	कुल
डाकघर	434	140	574
रेल डाक सेवा	198214	31728	229942
मेल डाक सेवा	24959	17602	42561
अन्य	1809	466	2275
कुल (अराजपत्रित)	3163	2356	5519
कुल विभागीय (क)	228579	52292	280871
ख. ग्रामीण डाक सेवक			283609
कुल योग (क+ख)			310269
			593878

TABLE 20

**PERSONNEL: ACTUAL STRENGTH AS ON 31.3.2001
(INCLUDING THOSE ON DEPUTATION AND TRAINING OUTSIDE THE DEPARTMENT)**

A.DEPARTMENTAL			
GAZETTED	GROUP "A"	GROUP "B"	TOTAL
INDIAN POSTAL SERVICE GROUP "A"			
Secretary(Posts)	1	-	1
Member, Postal Services Board	3	-	3
Principal Chief Postmaster General	2	-	2
Sr.DDG/Chief PMG	23	-	23
Senior Administrative Grade	73	-	73
Junior Administrative Grade	138	-	138
Senior Time Scale	79	-	79
Junior Time Scale	200	-	200
POSTAL SERVICE GROUP "B"	-	829	829
P & T ACCOUNTS & FINANCE SERVICE			
Senior Administrative Grade	1	-	1
Junior Administrative Grade	10	-	10
Senior Time Scale	24	-	24
Junior Time Scale	19	-	19
Senior Accounts Officer/Accounts Officer	-	230	230
Asstt. Accounts Officer	-	565	565
CENTRAL SECRETARIAT SERVICE	14	59	73
CIVIL WING			
Chief Engineer	2	-	2
Others	57	175	232
OTHER GENERAL CENTRAL SERVICE	167	67	234
TOTAL(GAZETTED)	813	1925	2738
NON GAZETTED	GROUP "C"	GROUP "D"	TOTAL
Directorate	434	140	574
Post Offices	198214	31728	229942
Railway Mail Service	24959	17602	42561
Mail Motor Service	1809	466	2275
Others	3163	2356	5519
TOTAL(NON GAZETTED)	228579	52292	280871
TOTAL DEPARTMENTAL(A)			283609
B. GRAMIN DAK SEWAK			
			310269
GRAND TOTAL(A+B)			593878

तालिका 21

डाकघरों, कार्मिकों तथा मेल परियात की संख्या : एक रूपरेखा
'1947-48 से 2000-2001 तक'

वर्ष	डाकघर का नाम	कर्मचारियों की संख्या	मेल परियात (मिलियन में)
1947-48	23,344		2204
1950-51	36,094	1,53,000	2350
1960-61	76,839	3,00,000	4165
1970-71	1,09,059	4,23,000	6457
1980-81	1,39,224	5,63,000	1,0627
1990-91	1,48,719	5,92,000	1,4683
1994-95	1,52,792	5,97,175	1,3608
1995-96	1,52,781	5,98,323	1,3958
1996-97	1,53,021	5,94,685	1,5096
1997-98	1,53,454	6,04,257	1,5749
1998-99	1,54,149	6,02,987	1,5767
1999-2000	1,54,551	6,03,950	1,5782
2000-2001	1,54,919	5,93,878	1,4203

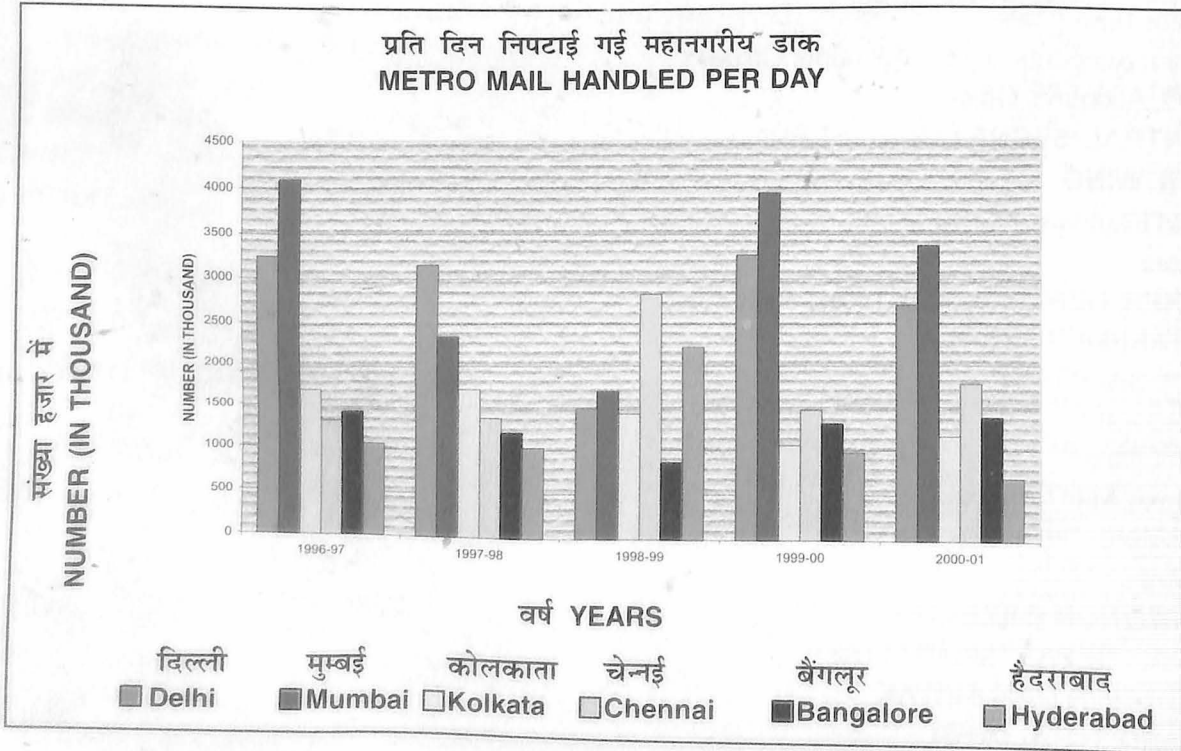
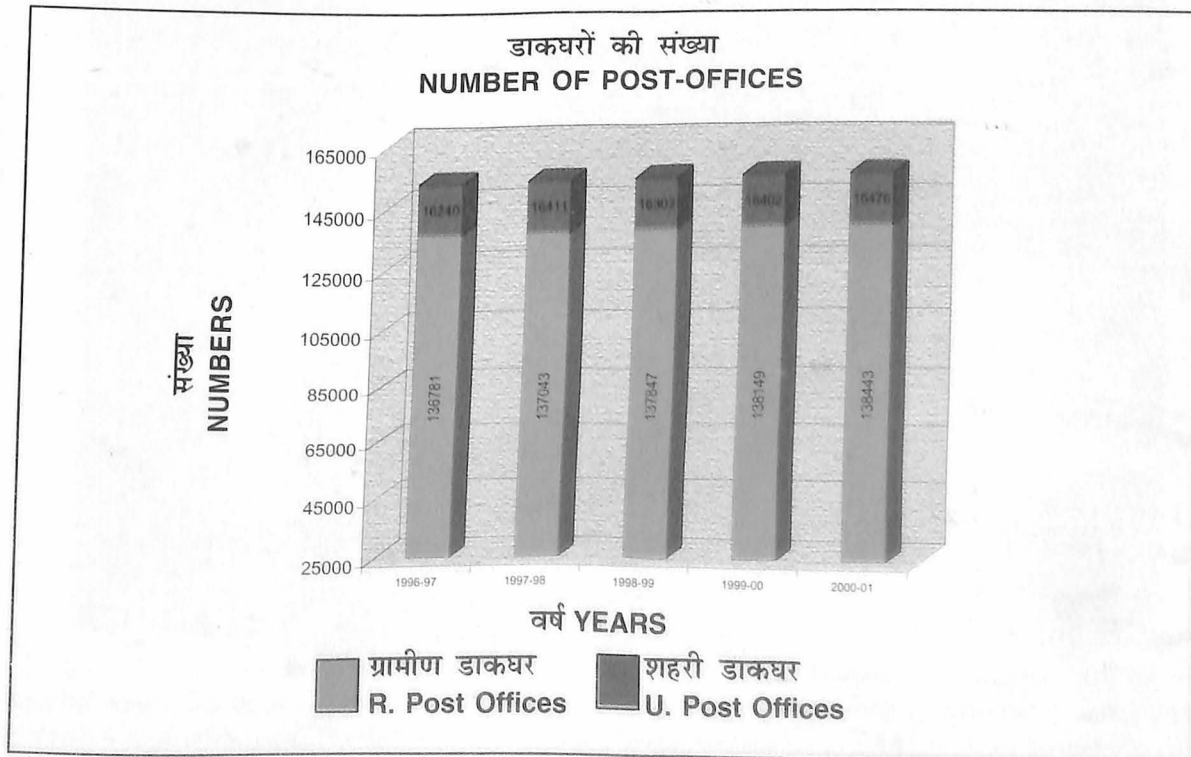


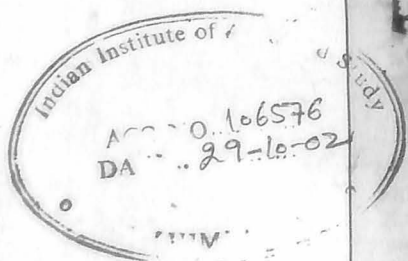
TABLE 21
NUMBER OF POST OFFICES, PERSONNEL AND MAIL TRAFFIC:
A PROFILE 1947-48 TO 2000-2001

Year	No. of Post Offices	Personnel employed	Mail Traffic(in million)
1947-48	23,344		2204
1950-51	36,094	1,53,000	2350
1960-61	76,839	3,00,000	4165
1970-71	1,09,059	4,23,000	6457
1980-81	1,39,224	5,63,000	1,0627
1990-91	1,48,719	5,92,000	1,4683
1994-95	1,52,792	5,97,175	1,3608
1995-96	1,52,781	5,98,323	1,3958
1996-97	1,53,021	5,94,685	1,5096
1997-98	1,53,454	6,04,257	1,5749
1998-99	1,54,149	6,02,987	1,5767
1999-2000	1,54,551	6,03,950	1,5782
2000-2001	1,54,919	5,93,878	1,4203





दिल्ली में इंडिया पोस्टमास्टर कार्ड इंटरनेशनल पार्टनरशिप के शुभारंभ के अवसर पर माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री तपन सिकदर।
Shri Tapan Sikdar, Hon'ble Minister of State for Communications & Information Technology, at the launch of India Post-MasterCard International partnership at Delhi.



ठाणे सेंट्रल डिवीजन के उल्हासनगर-5, डाकघर भवन के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमती अपर्णा मोहिले, सदस्य (आधारिक संरचना एवं वित्तीय सेवाएं)।
Smt. Aparna Mohile, Member (I&FS) at the inauguration of Ulhasnagar-5, Post Office Building at Thane Central Division.



डाक भवन में 31 जनवरी, 2002 को इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान सेवा के उद्घाटन समारोह के अवसर पर श्री प्रमोद महाजन, माननीय संसदीय कार्य और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

Shri Pramod Mahajan, Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs and Communications & Information Technology at the inauguration function of Electronic Bill Payment Service at Dak Bhawan on 31st Jan. 2002.



डाक भवन, नई दिल्ली में 3 जनवरी, 2002 को स्पीड पोस्ट वस्तुओं की ऑन लाइन ट्रैकिंग की राष्ट्रीय परियोजना, स्पीड नेट का शुभारंभ करते हुए श्री प्रमोद महाजन, माननीय संसदीय कार्य और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

Shri Pramod Mahajan, Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs and Communications & Information Technology launches SPEEDNET, National Project for tracking speed post articles on line at Dak Bhawan, New Delhi on 3rd January 2002.